दैनिक जागरण

जिसको लगन है वह साधन भी पा जाता है

मंदिर ही है भोजशाला

मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद मामले में इंदौर हाई कोर्ट के इस निर्णय पर आश्चर्य नहीं कि भोजशाला परिसर एक हिंदू मंदिर ही था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआइ के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें निर्देशित किया गया था कि भोजशाला परिसर में शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाएगी और मंगलवार को पूजा होगी। हाई कोर्ट ने मुस्लिम समाज से सरकार से मस्जिद के लिए अलग से जमीन की मांग करने को कहा है। यह फैसला अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्मरण कराने वाला है। इंदौर हाई कोर्ट के फैसले पर इसलिए किसी को चकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि परमार राजवंश के राजा भोज के वंशजों ने भोजशाला परिसर में मां वाग्देवी यानी देवी सरस्वती के मंदिर का निर्माण कराया था। एक समय यह संस्कृत शिक्षण का बड़ा केंद्र था। इस धार्मिक स्थल के मंदिर होने के साक्ष्य कथित कमाल मौला मस्जिद की दीवारों पर उससे भी स्पष्ट रूप से अंकित थे, जैसे अयोध्या में मिले थे। इस विवादित स्थल को लेकर इंदौर हाई कोर्ट इसलिए अपना फैसला दे सका, क्योंकि यह स्थल 1958 के अधिनियम के तहत एक एएसआइ संरक्षित स्मारक है। यदि ऐसा नहीं होता तो 1991 में पारित धार्मिक स्थल अधिनियम के चलते इस स्थान की यथास्थिति कायम रहती। दुर्भाग्य से इस भेदभावपूर्ण अधिनियम के चलते धार जैसे अन्य मामलों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है और इसके चलते समय-समय पर विवाद उभरते रहते हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव पर बुरा असर डालते हैं।

यह अच्छा है कि धार मामले में हाई कोर्ट की ओर से फैसला आने के कारण किसी तरह का सांप्रदायिक विग्रह देखने को नहीं मिला, लेकिन इतना तो है ही कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, इसकी अनदेखी न की जाए कि इस तरह के न जाने कितने मामले हैं। उनके निस्तारण में जो धार्मिक स्थल अधिनियम बाधक है, उसे भी चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के लिए उचित यह होगा कि वह इस अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं का निपटारा शीघ्र करे। इसी के साथ यह भी उचित होगा कि विवादित धार्मिक स्थलों को संबंधित पक्ष अर्थात हिंदू और मुस्लिम आपसी सहमति से सुलझाएं। इससे उनमें सद्भाव बढ़ेगा। यह तभी संभव हो पाएगा, जब मुस्लिम पक्ष इस यथार्थ को स्वीकार करेगा कि गजनवी, गोरी, खिलजी, बाबर, औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने सैकड़ों मंदिरों का ध्वंस ही नहीं किया, बल्कि उनके ही अवशेषों से ही वहां मस्जिदें बनवाईं। ऐसा केवल अयोध्या और धार में ही नहीं किया गया, बल्कि वाराणसी, मथुरा, संभल, जौनपुर समेत न जाने कितने स्थानों पर किया गया।

सुरक्षित पर्यटन के लिए

हिमाचल प्रदेश की वादियों में आकर किसी व्यक्ति का खो जाना मुहावरों में ही अच्छा लगता है। वास्तविकता में किसी का गुम हो जाना संबंधित व्यक्ति के परिवार ही नहीं, शासन और प्रशासन के लिए भी सरोकार का विषय होता है। ताजा घटना यह है कि मलाणा की वेचिंग वैली में दिल्ली का युवक लापता हो गया है। जाहिर है, इससे साहसिक पर्यटन की सुरक्षा भी प्रश्नांकित हुई है। दिल्ली का युवक दोस्तों के साथ गया था एवं कुछ सामान लेने की बात कहकर गया, लेकिन देर रात तक नहीं लौटा। उसका मोबाइल फोन भी बंद है। दोस्त, स्वजन एवं स्थानीय लोग उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। बात एक व्यक्ति की नहीं, त्रियुंड की पहाड़ियां हों या अन्य ऐसे स्थान, कई लोग लापता हो चुके हैं। चिंतनीय यह है कि कुल्लू जिला में पांच वर्ष में 795 लोग लापता हुए जिनमें 169 अब भी गुम हैं। राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन सुरक्षित पर्यटन के लिए भी प्रबंध किए जाने आवश्यक हैं। ट्रैकिंग आदि के लिए जाने वालों का पंजीकरण आवश्यक किया जाना चाहिए। बिना गाइड के किसी को भी पहाड़ों पर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ट्रैकिंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने पर भी विचार करना चाहिए। यह दायित्व पर्यटकों का भी है कि वे प्रशासनिक निर्देशों का पालन करते हुए अपरिचित और जोखिम से भरे क्षेत्रों में अकेले न जाएं।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए योजनाएं हैं, लेकिन सुरक्षित पर्यटन के लिए प्रबंध करना भी बहुत आवश्यक है

पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं

अशोक कुमार

भारत के सामने चुनौती केवल आतंकी हमलों का जवाब देने की नहीं, बल्कि उन्हें पहले से भांपकर विफल करने की भी है

अवधेश राजपूत

हाल में आपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने के समय सभी ने इसे स्मरण किया कि भारत ने किस तरह पाकिस्तान को धूल चटाई थी, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की फितरत अभी बदली नहीं है। इसका प्रमाण है पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर का यह बयान कि यदि पाकिस्तान पर फिर हमला हुआ तो जवाब बेहद व्यापक, खतरनाक, दूरगामी और दर्दनाक होंगे। हम इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क अब भी सक्रिय हैं। उसकी कुख्यात खुफिया एजेंसी आइएसआइ भारत विरोधी गतिविधियों में पहले की तरह ही लिप्त है और अमेरिकी समर्थन के कारण उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। यह मान लेना उचित नहीं होगा कि पाकिस्तान सुधरने वाला है। पिछले साल दिल्ली में लाल किले के निकट विस्फोट और सफेदपोश आतंकी माड्यूल का सामने आना यही जाहिर करता है कि आतंक का खतरा बना हुआ है। हाल में एनआइए और विभिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा कई संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। ये हथियारों की व्यवस्था, लाजिस्टिक्स प्रबंधन और आतंकी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।

चिंता का विषय आतंकवाद से जुड़े व्यक्तियों की बदलती प्रोफाइल है। कुछ आरोपी शिक्षित पेशेवर थे, जिनमें डाक्टर और तकनीकी रूप से दक्ष लोग भी थे। यह व्हाइट कालर टेररिज्म की बढ़ती पैठ को दर्शाता है, जहां सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और वित्तीय क्षमता का उपयोग आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा है। ऐसे तत्वों की पहचान करना अधिक कठिन होता है, क्योंकि वे वैध संस्थागत ढांचों के भीतर रहकर बहुल लो प्रोफाइल होकर काम करते हैं। भारत में इस्लामिक स्टेट से जुड़े माड्यूल भी सक्रिय दिख रहे हैं। ऐसे स्लीपर सेल सामने आए हैं, जो भर्ती, निगरानी और विस्फोटक प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों में शामिल थे। विभिन्न राज्यों में हुई गिरफ्तारियां यह भी दर्शाती हैं कि ये अलग-थलग समूह नहीं, बल्कि व्यापक और परस्पर जुड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं।

आज आतंकवाद तेजी से अपना स्वरूप बदल रहा है। यह अब केवल बंदूक और बम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अधिक विकेंद्रीकृत, तकनीक-आधारित और पकड़ से बचने वाला स्वरूप ले चुका है। अवैध हथियार तस्करी भी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। एके-47 जैसे हथियारों की बरामदगी ने सीमा पार से जुड़े संगठित सप्लाई नेटवर्क को उजागर किया है, जो बाहरी समर्थन और घरेलू नेटवर्कों के गठजोड़ को रेखांकित करता है। स्पष्ट है कि भर्ती, फंडिंग, लाजिस्टिक्स और क्रियान्वयन का एक सुव्यवस्थित तंत्र सक्रिय है। यह बढ़ती हुई परिष्कृत रणनीति आतंकी ढांचे की बारीकियों में भी जाहिर हो रही है। मार्च में दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर आइएसआइ से जुड़े एक जासूसी षड्यंत्र का खुलासा हुआ था, जिसमें गुप्त रूप से लगाए गए सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरों का उपयोग कर सैन्य गतिविधियों की रियल-टाइम फुटेज पाकिस्तानी हैंडलरों तक भेजी जा रही थी। यह दर्शाता है कि निगरानी गतिविधियां अब अधिक गुप्त और तकनीक आधारित होती जा रही हैं। ऐसे उपकरण सैन्य गतिविधियों का मानचित्रण, कमजोरियों की पहचान और भविष्य के हमलों में सहायता कर सकते हैं। चूंकि छोटी घटनाएं भी किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती हैं, इसलिए निरंतर सतर्कता अत्यंत आवश्यक है।

एक अन्य चिंता वैध व्यावसायिक प्लेटफार्मों के दुरुपयोग की है, जिसे कारपोरेट जिहाद के रूप में भी देखा जाता है। नासिक स्थित एक बीपीओ से जुड़े मामले ने यह दिखाया कि किस प्रकार व्यावसायिक संस्थानों का उपयोग नेटवर्क तैयार करने, आतंकी गतिविधियों को आड़ देने के लिए किया जा सकता है। यह दर्शाता है कि आतंकी रणनीतियां अब पारंपरिक तरीकों से कहीं आगे बढ़ चुकी हैं। डिजिटल कट्टरपंथ भी तेजी से बढ़ता खतरा बन चुका है। आनलाइन प्रचार, एन्क्रिप्टेड प्लेटफार्म और लक्षित संदेशों के माध्यम से युवाओं को प्रभावित और भर्ती किया जा रहा है। इससे आतंकवाद का खतरा अधिक व्यापक, अदृश्य और दीर्घकालिक बन गया है।

पाकिस्तान की ओर से खालिस्तान जैसे पुराने मुद्दे को पुनर्जीवित कर भारत में माहौल बिगाड़ने के प्रयास जारी हैं। चंडीगढ़ में भाजपा कार्यालय के पास विस्फोट, जालंधर में बीएसएफ मुख्यालय के बाहर धमाका तथा आइएसआइ समर्थित माड्यूलों का पर्दाफाश इसी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। इन गतिविधियों को डिजिटल माध्यम से सामाजिक विभाजन गहरा करने और जनमत प्रभावित करने का हिस्सा भी समझा जा रहा है। ऐसे में भारत किसी भी प्रकार की आत्मसंतुष्टि का जोखिम नहीं उठा सकता।

आपरेशन सिंदूर की सफलता को एक मजबूत और आधुनिक आंतरिक सुरक्षा ढांचे का समर्थन मिलना आवश्यक है। विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, रियल-टाइम खुफिया सूचनाओं को साझा करना और उन्नत तकनीक का उपयोग समय रहते खतरे की पहचान के लिए बेहद जरूरी है। इस क्रम में 'प्रहार' जैसे प्रतिक्रिया तंत्र आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कर सकते हैं। कट्टरपंथ के मूल कारणों पर भी प्रभावी ढंग से काम करना होगा। युवाओं को उग्रवाद और भ्रामक सूचनाओं के प्रति जागरूक करना रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विद्यालय स्तर पर आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी बुनियादी समझ विकसित करना समाज को अधिक सजग और जिम्मेदार बना सकता है। सामाजिक समरसता और समावेशी विकास को बढ़ावा देना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि अलगाव और असंतोष का लाभ अक्सर आतंकी संगठन उठाते हैं। आतंक के विरुद्ध यह संघर्ष केवल भौतिक नहीं, बल्कि वैचारिक भी है, जिसके लिए प्रभावी प्रतिपक्षी नैरेटिव की आवश्यकता है। भारत के सामने चुनौती केवल आतंकी हमलों का जवाब देने की नहीं, बल्कि उन्हें पहले से भांपकर विफल करने की भी है। हाइब्रिड आतंकवाद के इस दौर में, जहां बाहरी और आंतरिक खतरे तेजी से एक-दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, निरंतर सतर्कता, तैयारी और रणनीतिक दृढ़ता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।

(लेखक उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं)

response@jagran.com

बंगाल को पटरी पर लाने की बारी

प्रो. गौरव वल्लभ

बंगाल की आवश्यकता निवेशकों, वित्तीय संस्थानों और आम नागरिकों के विश्वास को पुनर्स्थापित करने की है

नई सरकार के नेतृत्व में बंगाल का बदलता माहौल। फाइल

पांच दशकों से अधिक समय बाद पूर्वी भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है, जहां राजनीतिक समन्वय, नीतिगत स्थिरता और आर्थिक संभावनाएं एक साथ आकार ले रही हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भाजपा अब पूर्वी भारत के चार प्रमुख राज्यों-बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में सत्ता में है और केंद्र में भी उसकी सरकार है। 1974 के बाद यह पहला अवसर है जब पूर्वी भारत में इस प्रकार का राजनीतिक समन्वय देखने को मिल रहा है। पिछली बार ऐसा तब हुआ था, जब देश की राजनीतिक और आर्थिक संरचना बिल्कुल अलग थी। इस परिवर्तन का महत्व केवल चुनावी गणित तक सीमित नहीं है। यह उन रणनीतिक अवसरों का संकेत है, जो लंबे समय से संभावनाओं के बावजूद अपेक्षित विकास से वंचित रहे पूर्वी भारत के लिए निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं।

बंगाल में बदलाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के समय बंगाल भारत के सबसे समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली क्षेत्रों में गिना जाता था, लेकिन समय के साथ राज्य अपनी आर्थिक ऊर्जा खोता गया। सरकारें उद्योग, निवेश और उद्यम के लिए अनुकूल वातावरण तैयार नहीं कर सकीं। उद्योग विरोधी सोच, नीतिगत अनिश्चितता, श्रमिक उग्रवाद और वैचारिक कठोरता ने धीरे-धीरे निवेशकों का विश्वास कम किया। परिणामस्वरूप औद्योगिक गिरावट, पूंजी पलायन और प्रतिभाओं का बड़े पैमाने पर बाहर जाना जारी रहा। 1960-61 में भारत की जीडीपी में बंगाल की हिस्सेदारी लगभग 10.5 प्रतिशत थी, जो आज घटकर लगभग 5.6 प्रतिशत रह गई है। कभी राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर रहने वाली प्रति व्यक्ति आय अब उससे नीचे पहुंच चुकी है। 2011 के बाद 6,600 से अधिक कंपनियां या तो बंद हुईं या राज्य से बाहर चली गईं। यह स्थिति इसलिए दुखद है, क्योंकि बंगाल के पास प्राकृतिक और रणनीतिक शक्तियां हमेशा मौजूद रहीं। उपजाऊ कृषि भूमि, लंबी समुद्री तटरेखा, प्रमुख बंदरगाह, दक्षिण-पूर्व एशिया से निकटता और पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार होने जैसी विशेषताएं किसी भी क्षेत्र को आर्थिक शक्ति बना सकती हैं।

बंगाल बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पूर्वोत्तर भारत के लिए भारत का प्रमुख संपर्क बिंदु है, लेकिन केवल भौगोलिक स्थिति विकास की गारंटी नहीं देती। इसके लिए संस्थागत क्षमता और नीति समन्वय भी उतने ही आवश्यक होते हैं। लंबे समय तक केंद्र और पूर्वी राज्यों के बीच राजनीतिक असमानता के कारण इस क्षेत्र के लिए समग्र विकास रणनीति विकसित नहीं हो सकी। लाजिस्टिक्स कारिडोर, पोर्ट आधुनिकीकरण, औद्योगिक क्षेत्र और सीमा व्यापार जैसी परियोजनाएं समन्वय के अभाव में अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकीं। अब यह बाधा काफी हद तक समाप्त होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक रूप से समन्वित पूर्वी भारत अब दीर्घकालिक योजना निर्माण की संभावना पैदा करता है। ईस्ट कोस्ट इकोनमिक कारिडोर, ताजपुर पोर्ट, लाजिस्टिक्स नेटवर्क, औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर और एक्ट ईस्ट नीति के साथ एकीकरण को अब अधिक नीति स्थिरता और तेज क्रियान्वयन मिल सकता है। भारत-बांग्लादेश व्यापार का आकार वार्षिक 1.8 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है, लेकिन बंगाल इसका सीमित लाभ ही प्राप्त कर पाता है। नेपाल और भूटान बंगाल के ट्रांजिट नेटवर्क पर निर्भर हैं, जबकि पूरा पूर्वोत्तर समुद्री संपर्क के लिए इसी क्षेत्र पर आधारित है। कोलकाता और हल्दिया पूर्वी भारत के प्रमुख समुद्री द्वार बने हुए हैं और प्रस्तावित ताजपुर डीप-सी पोर्ट पूरे क्षेत्र की आर्थिक दिशा बदलने की क्षमता रखता है।

केवल अवसंरचना बंगाल को पुनर्जीवित नहीं कर सकती। आवश्यकता निवेशकों, वित्तीय संस्थानों और आमजन के विश्वास को पुनर्स्थापित करने की है। वर्तमान में बंगाल पर लगभग आठ लाख करोड़ रुपये का सार्वजनिक ऋण बोझ है। पूंजीगत व्यय अक्सर कल्याण आधारित खर्चों की तुलना में पीछे रहा है। इसलिए चुनौती कल्याण योजनाओं को समाप्त करने की नहीं, बल्कि उन्हें उत्पादकता, उद्यमिता और भागीदारी के आधार में बदलने की है। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और कृषक बंधु जैसी योजनाओं ने सामाजिक सुरक्षा का व्यापक ढांचा तैयार किया है और इन्हें जारी रहना चाहिए, लेकिन दीर्घकालिक समृद्धि केवल प्रत्यक्ष सहायता से संभव नहीं होगी। कल्याण को सुरक्षा कवच से आगे बढ़ाकर उद्यमिता, कौशल विकास, महिला-नेतृत्व वाले व्यवसाय, एमएसएमई विकास और कृषि मूल्य संवर्धन का आधार बनाना होगा। बंगाल का भविष्य सब्सिडी आधारित राजनीति में नहीं, बल्कि सामान्य नागरिकों को अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदारी का अवसर देने में निहित है। इसके साथ ही शासन व्यवस्था का आधुनिकीकरण भी उतना ही आवश्यक है। पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध प्रशासनिक प्रणाली, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और पूर्वानुमान योग्य स्वीकृति तंत्र अब अपरिहार्य बन चुके हैं।

(लेखक प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्मबल

मनुष्य का जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों से संचालित नहीं होता, बल्कि उसकी वास्तविक दिशा उसकी मनःस्थिति और आत्मबल तय करते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति सदैव अनुकूल परिस्थितियों में नहीं रहता। कभी जीवन में सुख की मधुर धूप आती है तो कभी संघर्षों की कठोर छाया। किंतु जो व्यक्ति परिस्थितियों का दास बन जाता है, वह अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को पहचान नहीं पाता। वास्तव में परिस्थितियां उतनी प्रभावशाली नहीं होतीं, जितना हमारा दृष्टिकोण। इतिहास के महान व्यक्तियों ने विपरीत परिस्थितियों को ही अपनी साधना का माध्यम बनाया। उनका विश्वास बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि अपने पुरुषार्थ और आत्मबल में था। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लेता है, तब अभाव भी अवसर बन जाते हैं और कठिनाइयां सफलता की सीढ़ियां। आज मनुष्य के पास सुविधाएं पहले से कहीं अधिक हैं, फिर भी उसका मन अशांत और तनावग्रस्त है। इसका कारण बाहरी अभाव नहीं, बल्कि भीतर की अतृप्त इच्छाएं हैं। लोभ, संग्रह और तुलना की प्रवृत्ति मनुष्य को निरंतर बेचैन करती है। जिस क्षण जीवन में तनाव प्रवेश करता है, उसी क्षण सुख और शांति दूर होने लगते हैं। आधुनिक जीवन की अंधी दौड़ ने मनुष्य को स्वयं से भी दूर कर दिया है।

जीवन का सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि संतोष, संयम और आत्मविश्वास में निहित है। जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदलने के बजाय अपने आत्मबल को मजबूत करता है, वही सच्चे अर्थों में सफल और शांत जीवन जी पाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम परिस्थितिवादी न बनें, बल्कि आत्मबल, सकारात्मक चिंतन और पुरुषार्थ को अपना आधार बनाएं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी विजय बाहरी संसार पर नहीं, स्वयं पर प्राप्त की गई विजय होती है।

ललित गर्ग

जेल सुधार की दिशा में ठोस प्रयास

देवेंद्रराज सुथार

'फील द जेल' जैसी पहल का महत्व तभी होगा जब यह जेल पर्यटन से आगे बढ़कर जेल सुधारों की बहस को मजबूत करे

हाल में तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई 'फील द जेल' पहल ने भारतीय जेल व्यवस्था को लेकर नई बहस खड़ी कर दी है। इस पहल के तहत आम नागरिक सशुल्क 12 या 24 घंटे जेल में रहकर कैदियों जैसा जीवन अनुभव कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य लोगों को अनुशासन, कानून और स्वतंत्रता का महत्व समझाना बताया गया है। यह पहल ऐसे समय आई है जब भारत की जेलें पहले से ही गंभीर भीड़भाड़, विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं।

दुनिया के कई देशों में जेल पर्यटन की अवधारणा पहले से मौजूद है। अमेरिका की अलकाट्राज जेल, दक्षिण अफ्रीका की राबेन आइलैंड जेल और कंबोडिया की ट्यूल स्लेंग जेल जैसे स्थान ऐतिहासिक स्मृति और जन-जागरूकता के केंद्र बन चुके हैं। इनका उद्देश्य केवल पर्यटन नहीं, बल्कि अपराध, दमन और मानवाधिकारों के इतिहास को समाज के सामने रखना भी है। भारत में तेलंगाना का यह प्रयोग उसी दिशा में एक नया प्रयास माना जा रहा है। लेकिन भारत की जेलों की वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की 'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2022' रिपोर्ट के अनुसार देश की जेलों की कुल क्षमता लगभग 4.36 लाख कैदियों की है, जबकि इनमें 5.73 लाख से अधिक कैदी बंद हैं। यानी औसत अधिभोग दर 131 प्रतिशत से अधिक है। दिल्ली की जेलों में यह दर 170 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और महाराष्ट्र की जेलों में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। चिंताजनक है कि भारतीय जेलों में लगभग 75 प्रतिशत कैदी विचाराधीन हैं। यानी अदालतों ने अभी उनका अपराध सिद्ध नहीं किया है। यह दुनिया में विचाराधीन कैदियों के सबसे बड़े अनुपातों में से एक है।

ऐसे में 'फील द जेल' जैसी पहल दो तरह के प्रश्न खड़े करती है। पहला, क्या जेल जीवन को अनुभवात्मक कार्यक्रम बनाकर समाज को कानून और अनुशासन के प्रति जागरूक किया जा सकता है? दूसरा, क्या यह पहल जेलों की वास्तविक समस्याओं को सतही तरीके से प्रस्तुत करने का जोखिम नहीं उठाती? क्योंकि किसी आम व्यक्ति के लिए 24 घंटे का जेल अनुभव और एक विचाराधीन कैदी के लिए वर्षों तक जेल में रहना पूरी तरह अलग स्थितियां हैं। हालांकि इस पहल का सकारात्मक पक्ष भी है। भारत में जेलों को लेकर आम समाज में जागरूकता बहुत कम है। यदि इस प्रयोग के माध्यम से लोग जेलों की वास्तविक स्थिति, कैदियों की समस्याओं और सुधार की जरूरत को समझ पाते हैं, तो यह उपयोगी कदम हो सकता है। जेलों में भीड़ कम करने, विचाराधीन कैदियों की संख्या घटाने, न्यायिक प्रक्रिया तेज करने और पुनर्वास आधारित माडल अपनाने की दिशा में गंभीर कदम उठाने होंगे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

तिलहन उत्पादन को मिले बढ़ावा

'समय रहते चेतें' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में पेट्रोलियम के साथ खाद्य तेल को लेकर व्यक्त की गई चिंता पर सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रमों से यह वाक्य हटाना पड़ेगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यह जानकारी हैरत में डालती है कि भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 58 प्रतिशत खाद्य तेल आयात करता है। इसके बावजूद सरकार तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रति अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रही है। उल्लेखनीय है कि हमारे क्षेत्र आजमगढ़ और आसपास में हजारों एकड़ भूमि पर किसान सरसों और दलहन की खेती इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी फसलों को झुंड के झुंड घूमने वाले नीलगाय और घड़रोज जैसे जंगली पशु चट कर जाते हैं। किसान अपनी फसलों की सुरक्षा उस जानवर से कैसे करें, जिसे सरकार और उसके तंत्र का पूरा संरक्षण प्राप्त है? यदि कोई किसान अपनी फसल बचाने के लिए ऐसे पशुओं को मारने या भगाने की कोशिश करता है, तो पुलिस उस पर ऐसे शिकंजा कसती है, मानो वह कोई गंभीर अपराधी हो। स्थिति यह हो गई है कि जो पशु किसानों के लिए शत्रु हैं, वे सरकार के मित्र बन गए हैं। यही कारण है कि किसानों ने अब दलहन और तिलहन की खेती छोड़कर धान और गेहूं की खेती को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। उनसे जो आय होती है, उसी से वे बाजार से दाल और तेल खरीद लेते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे देश में गेहूं और धान का उत्पादन पहले से ही अधिशेष में है। ऐसे में जिन खेतों में तिलहन और दलहन की खेती हो सकती है, वहां इन फसलों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा? यह चिंता सरकार को करनी चाहिए, ताकि देश खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बन सके।

डा. हरिप्रसाद राय, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

मेलबाक्स

सनातनी गौरव की पुनर्स्थापना

इतिहास के पन्नों पर जमी धूल जब हटती है, तो सत्य अपनी पूरी चमक के साथ प्रदीप्त हो उठता है। धार की ऐतिहासिक भोजशाला के संदर्भ में हाल ही में आए घटनाक्रम और विधिक निर्णयों ने न केवल हिंदू पक्ष की आस्था को संबल दिया है, बल्कि इसे न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है। यह केवल एक कानूनी विजय नहीं है, बल्कि उस सांस्कृतिक चेतना का पुनरुत्थान है, जो सैकड़ों वर्षों से अपनी पहचान को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्षरत थी। राजा भोज द्वारा निर्मित यह सरस्वती सदन, जो कभी ज्ञान, विज्ञान और कला का विश्वविख्यात केंद्र था, समय के थपेड़ों और आक्रांताओं की कुदृष्टि के कारण विवादों के घेरे में आ गया था। दशकों तक चली कानूनी लड़ाई और हालिया पुरातात्विक सर्वेक्षणों के बाद सामने आए तथ्यों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस परिसर के कण-कण में सनातनी सभ्यता के प्रमाण रचे-बसे हैं। स्तंभों पर उकेरी गई संस्कृत की ऋचाएं, देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां और वास्तुशिल्प की सनातनी शैली इस बात की गवाह हैं कि यह स्थान मां वाग्देवी का पावन धाम ही है। जिस प्रकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक युग परिवर्तन का प्रतीक बना, उसी प्रकार भोजशाला में हिंदू पक्ष के अधिकारों की पुष्टि भारत की सांस्कृतिक जड़ों की ओर वापसी का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है। यह केवल एक धार्मिक स्थल की प्राप्ति नहीं है, भारतीय इतिहास के उन गौरवशाली पृष्ठों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है जिन्हें षड्यंत्रपूर्वक धुंधला कर दिया गया था। भोजशाला का परिसर, जो कभी महान राजा भोज की विद्वत्ता का परिचायक था, अब पुनः अपनी उसी गरिमा को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। समावेशी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह निर्णय सत्य और साक्ष्यों की जीत है। जब पुरातात्विक साक्ष्य चीख-चीख कर सत्य बयां कर रहे हों, तो उसे नकारा नहीं जा सकता। न्यायालय और संबंधित संस्थानों ने जिस निष्पक्षता और वैज्ञानिक पद्धति से तथ्यों को परखा, उसने न्याय व्यवस्था के प्रति आम जन के विश्वास को और सुदृढ़ किया है। अब समय है कि भोजशाला को उसके प्राचीन वैभव के अनुरूप सजाया जाए। यह स्थान पुनः एक बार संस्कृत, संस्कृति और संस्कारों की पाठशाला बने, यही सच्ची जीत होगी।

आदित्य सोनी 'सार्थक', मनावर, धार

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नान एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशनलि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

बिजनेस

तीन कंपनियों को आइपीओ लाने की मंजूरी

नई दिल्ली: कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी से तीन कंपनियों को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) लाने की मंजूरी मिल गई है। इसमें नियोलाइट जेकेडब्ल्यू लाइटिंग्स, एसएस रिटेल और एसप्री स्प्रिट्स शामिल हैं। यह तीनों कंपनियां आइपीओ के जरिये संयुक्त रूप से 1,200 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि जुटाना चाहती हैं। (प्रेट्र)

पूंजी प्रवाह में कमी, आयात पर बढ़ती निर्भरता, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और बढ़ते चालू खाता घाटा के कारण भारतीय रुपया के दबाव में रहने की संभावना है।

-देवेंद पंत, मुख्य अर्थशास्त्री, इंडिया रेटिंग्स

सेंसेक्स	75,237.99 ▼ 160.73	निफ्टी	23,643.50 ▼ 46.10	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 1,62,800 ▼ ₹ 3,200	चांदी प्रति किलो ग्राम	₹ 2,75,000 ▼ ₹ 21,600	$ डालर	₹ 95.81 ▲ ₹ 0.17	कूड प्रति बैरल	$ 109.23

एक नजर में

रेयर अर्थ मैग्नेट योजना में आवेदन की तिथि बढ़ाई

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली 7,280 करोड़ रुपये की योजना में वैश्विक आवेदन की अंतिम तिथि को एक माह के लिए बढ़ा दिया। इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 28 मई को समाप्त हो रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 29 जून 2026 कर दिया गया है। सरकार ने देश में छह हजार मीट्रिक टन मैग्नेट मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए इसी वर्ष 20 मार्च को बोलियां आमंत्रित की थीं। (प्रेट्र)

एमसीएल को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने महानंदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोल इंडिया ने शुक्रवार को रेग्युलेटरी फाइलिंग में बताया कि आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) के जरिये एमसीएल की 25 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेची जाएगी। कोल इंडिया एमसीएल की पैरेंट कंपनी है। इस आइपीओ में नए शेयर और प्रमोटर शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 2030 तक कोल इंडिया की सभी आठों सब्सिडियरी को सूचीबद्ध कराने का निर्देश दिया है। (प्रेट्र)

बीते वर्ष 14,026 करोड़ रहा टाटा स्टील का निवेश

नई दिल्ली: टाटा स्टील ने शुक्रवार को बताया कि बीते वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसने 14,026 करोड़ रुपये का निवेश (पूंजीगत खर्च) किया है। पूरे वर्ष के दौरान कंपनी को 10,885.52 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है और इसमें 2024-25 के 3,173.78 करोड़ रुपये के मुकाबले तीन गुना से ज्यादा वृद्धि रही है। इसमें भारत से ज्यादा आय का प्रमुख योगदान रहा है। जनवरी-मार्च 2026 में कंपनी का शुद्ध लाभ दोगुना से ज्यादा बढ़कर 2,965 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी चार रुपये प्रति शेयर का लाभांश देगी। (प्रेट्र)

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निर्यात 13% बढ़ा

भारत को नए बाजार तलाशने का मिला लाभ, 43.56 अरब डालर रहा पिछले माह कुल वस्तु निर्यात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश का निर्यात अप्रैल में 13.78 प्रतिशत बढ़कर पांच महीने के उच्चस्तर पर 43.56 अरब डालर रहा। पिछले दस सालों में अप्रैल में होने वाला यह अब तक का सबसे अधिक निर्यात है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल में युद्ध से प्रभावित पश्चिम एशिया देशों में होने वाले निर्यात में गिरावट रही, लेकिन कई नए बाजार में निर्यात बढ़ने से वस्तुओं का कुल निर्यात बढ़ा। पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 38.2 अरब डालर रहा था।

अप्रैल में वस्तुओं का आयात 72 अरब डालर रहा, जो पिछले साल अप्रैल की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल में खाद्य तेल के आयात में पिछले साल अप्रैल की तुलना में 40 प्रतिशत, सोने में 81 प्रतिशत (कुल 5.62 अरब डालर) तो चांदी के आयात में 157 प्रतिशत (41.1 करोड़ डालर) का इजाफा रहा। सोने और चांदी के आयात को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने इनके आयात शुल्क को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि अप्रैल में निर्यात बढ़ने की दो-तीन वजहें हैं। एक तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं। इससे मूल्य बढ़ा हुआ दिख रहा है। शुक्रवार को एक डालर का मूल्य 96 रुपये के पार चला गया जबकि पिछले साल मध्य अप्रैल में यह डालर के मुकाबले 85.44 रुपये था। वहीं पारंपरिक बाजार के अलावा सिंगापुर, नीदरलैंड, तंजानिया, हांगकांग, मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों में भारी मात्रा में निर्यात बढ़ा है। उन्होंने बताया कि सेवा निर्यात में पहले की तरह वृद्धि जारी है और अप्रैल में यह 13.7 प्रतिशत बढ़ा।

40 प्रतिशत का इजाफा हुआ खाद्य तेल के आयात में

81 प्रतिशत बढ़ा सोने का आयात पिछले महीने

157 प्रतिशत की वृद्धि रही चांदी के आयात में

72 अरब डालर रहा कुल वस्तु आयात अप्रैल में

पश्चिम एशियाई देशों को निर्यात 28 प्रतिशत घटा

अप्रैल में पश्चिम एशियाई देशों को वस्तु निर्यात 28 प्रतिशत घटकर 4.16 अरब डालर रह गया। जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 5.78 अरब डालर था। इस क्षेत्र से आयात भी 31.64 प्रतिशत घटकर 10.47 अरब डालर रह गया, जो एक साल पहले इसी समय 15.32 अरब डालर था। अप्रैल में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सऊदी अरब को भारत का निर्यात 36.39 प्रतिशत घटकर क्रमशः 2.18 अरब डालर और 85.2 करोड़ डालर रह गया।

डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य में हो रही गिरावट से भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धा क्षमता प्रभावित नहीं हुई है। इसका एक कारण यह है कि अन्य देशों की करेंसी में भी डालर के मुकाबले गिरावट हो रही है। ब्रिटेन के हाल के इस्पात संरक्षण उपाय से उत्पन्न मुद्दों से निपटने के लिए 'विशिष्ट एवं रचनात्मक समाधान' तलाश रहे हैं ताकि प्रस्तावित व्यापार समझौता को जल्द लागू किया जा सके। **-राजेश अग्रवाल,** वाणिज्य सचिव

पिछले महीने विभिन्न देशों को बढ़ा निर्यात (% में)

सिंगापुर	179.18
चीन	27
वियतनाम	53
बांग्लादेश	64
तंजानिया	157
श्रीलंका	214
हांगकांग	90.61
मलेशिया	60
अमेरिका	1.14
यूएई	(-36.39)

मुनाफावसूली से 21,600 रुपये घटा चांदी का मूल्य

नई दिल्ली, प्रेट्र: डालर में मजबूती और निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते शुक्रवार को दिल्ली में चांदी और सोने के मूल्य में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार, चांदी के मूल्य में 21,600 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। अब दिल्ली में इसका मूल्य घटकर 2.75 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है।

इसी प्रकार, सोने के मूल्य में 3,200 रुपये की गिरावट दर्ज की गई और अब इसका मूल्य 1,62,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कहा कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों और अमेरिका-ईरान तनाव के कारण सप्लाई चेन में आ रही लगातार रुकावटों ने सख्त मौद्रिक नीति लागू करने की जरूरत को और मजबूत कर दिया है। इस कारण शुक्रवार को कीमती धातुओं पर भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला।

- 2.75 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हुई दिल्ली में सफेद धातु की कीमत
- सोना 3,200 रुपये गिरकर 1,62,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया

इंट्रा-डे में रुपया 96.14 के रिकार्ड स्तर तक गिरा

मुंबई, प्रेट्र: कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और महंगाई संबंधी चिंताओं के चलते शुक्रवार को डालर के मुकाबले रुपया इंट्रा-डे में 96.14 के स्तर तक गिर गया। हालांकि, बाद में यह कुछ संभला और गुरुवार के बंद भाव से 22 पैसे टूटकर 95.86 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। रुपया इस वर्ष अब तक छह प्रतिशत से अधिक टूट चुका है और पिछले छह कारोबारी सत्रों में यह दो प्रतिशत कमजोर हुआ है।

6.29 अरब डालर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार

मुंबई, प्रेट्र: आरबीआइ ने शुक्रवार को कहा कि आठ मई को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.295 अरब डालर बढ़कर 696.988 अरब डालर हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार के यह आंकड़े प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाओ की अपील से पहले के हैं। इससे पिछले सप्ताह में कुल रिजर्व 7.794 अरब डालर घटकर 690.693 अरब डालर के स्तर पर आ गया था। इस साल 27 फरवरी को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 728.494 अरब डालर के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया था।

आरबीआइ के आंकड़ों के अनुसार, बीते सप्ताह विदेशी मुद्रा आस्तियां 56.2 करोड़ डालर बढ़कर 552.387 अरब डालर हो गईं। विदेशी मुद्रा भंडार में इनकी सबसे अधिक हिस्सेदारी होती है। इसी तरह, स्वर्ण भंडार का मूल्य 5.637 अरब डालर बढ़कर 120.853 अरब डालर हो गया।

कई साल के निचले स्तर पर पहुंची बैंकों की बट्टा खाता राशि

मुंबई, प्रेट्र: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तरफ से बट्टेखाते में डाले गए कर्ज की राशि वित्त वर्ष 2025-26 में घटकर कई वर्षों के निचले स्तर पर आ गई। कर्ज फंसने के मामलों में कमी और बकाया कर्ज की वसूली में सुधार इसकी प्रमुख वजह रहे।

इन बैंकों के वित्तीय नतीजों के विश्लेषण से पता चलता है कि बैंक आफ बड़ौदा, यूनियन बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक सहित अधिकांश बैंकों ने पिछले आठ वर्षों में सबसे कम कर्जों को बट्टेखाते में डाला। बैंक आफ बड़ौदा ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6,330 करोड़ रुपये के कर्ज बट्टेखाते में डाले, जो 2017-18 के बाद सबसे कम है। इसी तरह, बैंक आफ इंडिया ने 5,735 करोड़ रुपये बट्टेखाते में डाले, जो 2015-16 के बाद न्यूनतम स्तर है। इंडियन बैंक का कर्ज बट्टा खाता 2018-19 के बाद सबसे कम 6,695 करोड़ रुपये रहा। इसी तरह, इंडियन ओवरसीज बैंक का 1,189 करोड़ रुपये रहा, जो कई वर्षों के निचले स्तर पर है। सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने पिछले वित्त वर्ष में 1,718 करोड़ रुपये के कर्ज बट्टेखाते में डाले, जो 2021-22 के बाद सबसे कम है। आमतौर पर बैंक उन कर्जों को बट्टेखाते में डालते हैं, जिनकी वसूली की संभावना कम होती है और जिनके लिए 100 प्रतिशत वित्तीय प्रविधान करना पड़ता है।

- कर्ज फंसने के मामलों में कमी और बकाया कर्ज की वसूली में सुधार रहे इसकी प्रमुख वजह
- बैंक आफ बड़ौदा ने 6,330 करोड़ बट्टेखाते में डाले, यह 2017-18 के बाद सबसे कम

अप्रैल में बेरोजगारी दर छह महीने के उच्चस्तर 5.2 प्रतिशत पर रही

नई दिल्ली, प्रेट्र: अप्रैल में भारत की बेरोजगारी दर छह महीने के उच्चस्तर 5.2% पर पहुंच गई। जबकि, मार्च 2026 और अप्रैल 2025 में यह 5.1 प्रतिशत थी। सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी अप्रैल, 2026 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वे अनुसार शहरी बेरोजगारी दर मार्च, 2026 के 6.8 प्रतिशत से थोड़ा कम होकर अप्रैल, 2026 में 6.6 प्रतिशत हो गई, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर इसी समय के दौरान 4.3 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गई।

अप्रैल में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के पुरुषों की बेरोजगार दर 5.1 प्रतिशत रही, जबकि मार्च, 2026 में यह पांच प्रतिशत थी। इसी तरह अप्रैल में ग्रामीण पुरुषों की बेरोजगारी दर 4.7 प्रतिशत रही, जो इसी वर्ष मार्च 4.4 प्रतिशत थी। वार्षिक आधार पर पुरुषों की बेरोजगारी दर 0.1 प्रतिशत घटी है।

बीते वित्त वर्ष के लिए आइटीआर जमा करने की प्रक्रिया शुरू, 31 जुलाई तक है मौका

नई दिल्ली, आइएनएनएस: यदि बीते वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) में आप पर कोई कर देनदारी है या फिर आपको रिफंड लेना है तो इसके लिए आप आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने सोमवार को बताया कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर आइटीआर-1 और आइटीआर-4 फार्म के एक्सल प्रारूप जारी कर दिए गए हैं। करदाता दोनों फार्म के एक्सल प्रारूप या आनलाइन फाइलिंग विकल्प का चयन करते हुए आइटीआर दाखिल कर सकते हैं।

आयकर विभाग की इस घोषणा के साथ आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आइटीआर फाइल करने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। सामान्य तौर पर जिन करदाताओं का आडिट नहीं होता है, उन्हें 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल करना होता है। इस समय आय के प्रकार और करदाता की श्रेणी के आधार पर कुल सात आइटीआर फार्म उपलब्ध हैं। आइटीआर-1 (सहज) उन सभी करदाताओं के लिए है जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है। आइटीआर-4 (सुगम) उन व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और फर्मों (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को छोड़कर) के लिए है जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है।

आयकर विभाग ने आइटीआर-1 और आइटीआर-4 के एक्सल प्रारूप जारी किए, आनलाइन-आफलाइन भरें आयकर रिटर्न

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) पहले ही बदलाव के अनुसार सभी आइटीआर फार्म जारी कर चुका है। इन बदलावों में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, शेयर बायबैक से होने वाले नुकसान और कुछ विशिष्ट ट्रेडिंग लेन-देन से संबंधित अतिरिक्त रिपोर्टिंग आवश्यकताएं शामिल हैं।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

राष्ट्रीय फलक

लुधियाना के काल सेंटर में 22 टीमें चलाती थीं ठगी का नेटवर्क, रोज ऐंठते थे साढ़े सात करोड़

जागरण संवाददाता, लुधियाना

- 132 आरोपितों को गिरफ्तार कर 1.07 करोड़, 229 मोबाइल व 98 लैपटाप किए बरामद
- विदेश में भी आरोपितों ने बनाई थी टीम

लुधियाना में अवैध इंटरनेशनल काल से बरामद नकदी, लैपटाप व मोबाइल के बार में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा। फोटो : अजय शर्मा

दो अवैध इंटरनेशनल काल सेंटर में साइबर ठगी के मामले में पंजाब पुलिस ने बड़ा राजफाश किया है। पुलिस ने बुधवार देर रात करीब 12 बजे छापा मारकर 132 युवक-युवतियों को गिरफ्तार किया था। इन काल सेंटर के जरिये दिल्ली और गुजरात में बैठे किंगपिन अमेरिका व यूरोप के लोगों से ठगी कर रहे थे। यहां 22 टीमें बनाई गई थीं। सभी आरोपित एक दिन में करीब आठ लाख डालर कमाते थे, जो कि भारतीय मुद्रा में करीब साढ़े सात करोड़ रुपये हैं। पुलिस ने 1.07 करोड़ रुपये, 229 मोबाइल, 98 लैपटाप और 19 गाड़ियां भी बरामद की हैं।

जांच में पता चला है कि काल सेंटर में ओपनर व क्लोजर टीम बनाकर काम होता था। ओपनर टीम पीड़ित को झांसे में लेकर सिस्टम एक्सेस लेती थी जबकि क्लोजर खुद को बैंक अधिकारी बताकर पैसे ट्रांसफर करवाते थे। वे लोगों से कहते थे कि अगर खाते से पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया तो फ्राड हो जाएगा। दूसरे खातों में रुपये ट्रांसफर करने के अलावा घर से रुपये लेने का भी विकल्प दिया जाता था। जहां से कैश लेना होता था, वहां ठगों की विदेश में बैठी टीम जाती थी। फिर वह राशि हवाला के जरिए भारत भेजी जाती थी।

हैक करते थे सिस्टम : पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि आरोपित विदेशी लोगों के कंप्यूटर पर नामी कंपनी के नाम से फर्जी सुरक्षा अलर्ट भेजते थे और स्क्रीन पर कस्टमर केयर नंबर दिखाते थे। जैसे ही पीड़ित नंबर डायल करता, काल ठगों तक पहुंचती थी।

सुपरनोवा से जुड़े सभी सौदों के लिए समिति से अनुमति जरूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक अधिकार प्राप्त समिति ने सार्वजनिक सूचना जारी की है कि नोएडा में सुपरटेक रियल्टर्स की सुपरनोवा परियोजना में किसी भी अचल संपत्ति लेनदेन के लिए समिति से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। समिति ने सुपरटेक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (एसआरपीएल) की परियोजना में इकाइयों की बिक्री या हस्तांतरण पर प्रतिबंधों से जुड़ी सूचना जारी की थी।

सुपरटेक रियल्टर्स नोएडा के सेक्टर 94 में आवासीय, वाणिज्यिक, कार्यालय स्थान, अपार्टमेंट, सर्विस अपार्टमेंट व शापिंग सेंटर वाली मिश्रित उपयोग वाली अचल संपत्ति परियोजना 'सुपरनोवा' का निर्माण कर रही है। इसमें 2,800 संपत्ति खरीदार फंसे हुए हैं। समिति ने सभी संबंधित पक्षों को सूचित किया है कि परियोजनाओं में बिक्री, हस्तांतरण, के लिए पूर्व लिखित स्वीकृति अनिवार्य है।

देहरादून में नया निवेश घोटाला, क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 25 करोड़ रुपये ठगे

जागरण संवाददाता, देहरादून

- बोटब्रो, क्रास मार्केट व माइन क्रिप्टो मामला सामने आया, छह पर मुकदमा
- पांच से 10 प्रतिशत मासिक मुनाफे का झांसा देकर जुटाए करोड़ों रुपये

देहरादून में बोटब्रो, क्रास मार्केट व माइन क्रिप्टो नामक प्लेटफार्म के जरिये करोड़ों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि निवेशकों को हर महीने पांच से 10 प्रतिशत तक रिटर्न का लालच देकर 20 से 25 करोड़ रुपये जुटाए। बाद में कंपनी बंद कर दी गई।

मामले में पुलिस ने छह आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रायपुर क्षेत्र निवासी दुर्गा बहादुर की तहरीर के अनुसार करीब दो वर्ष पहले नवीन सिंह नेगी ने उन्हें पहले बोटब्रो, फिर क्रास मार्केट और बाद में माइन क्रिप्टो प्लेटफार्म में निवेश के लिए प्रेरित किया। कंपनियों को पूरी तरह वैध बताते हुए व्यक्तिगत गारंटी तक दी गई और प्रतिमाह मोटे मुनाफे का दावा किया गया। निवेशकों को ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर बिजनेस आईडी दी जाती थी। इसके लिए पहले 10 हजार रुपये लाइसेंस शुल्क लिया जाता, फिर बड़ी धनराशि निवेश कराई जाती थी। भरोसा भी दिलाया गया कि छह महीने बाद मूल रकम बिना किसी कटौती के वापस ली जा सकेगी। देहरादून में ठगी के शिकार हुए लोगों की संख्या 100 से अधिक जबकि पूरे उत्तराखंड में हजारों लोगों ठगी के शिकार बताए जा रहे हैं।

निवेशकों को जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर प्रचार अभियान चलाया। अधिक सदस्य जोड़ने वालों को अतिरिक्त लाभ और बोनस का झांसा दिया गया। अक्टूबर 2025 में प्लेटफार्म अचानक बंद हो गया। रायपुर थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि जांच के बाद छह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

खराब गुणवत्ता वाले अंडों की शिकायतों पर ब्लिंकिट से मांगा जवाब

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने क्विक-कामर्स कंपनी ब्लिंकिट से उसके प्लेटफार्म पर खराब क्वालिटी के अंडे बेचने की ग्राहकों की शिकायतों के बारे में सफाई मांगी है। एफएसएसएआइ ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर ग्राहकों की शिकायतों का खुद से संज्ञान लिया है।

सूत्रों ने बताया कि एफएसएसएआइ ने शुक्रवार को ब्लिंकिट कामर्स प्राइवेट लिमिटेड को पत्र लिखकर शिकायतों के बारे में एक हफ्ते में कार्रवाई रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि कई ग्राहकों ने अंडों से बदबू आने और उनके रबर जैसे होने की शिकायत की है। तीन दिसंबर 2024 की एक एडवाइजरी में एफएसएसएआइ ने कहा था, आनलाइन बेचे जाने वाले फूड प्रोडक्ट्स की सुरक्षा, क्वालिटी के लिए ई-कामर्स फूड बिजनेस आपरेटर्स द्वारा नियमों का पालन करना जरूरी है।"

सिमुलेटर आधारित प्रशिक्षण से हजार करोड़ की बचत कर सकते हैं सशस्त्र बल : टेरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय सशस्त्र बल सिमुलेटर-आधारित प्रशिक्षण को व्यापक रूप से अपनाकर सालाना 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत कर सकते हैं। इससे ईंधन की खपत कम करने, गोला-बारूद की लागत घटाने और रसद व्यय को कम करने में मदद मिल सकती है। यह जानकारी द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) द्वारा शुक्रवार को जारी अध्ययन में दी गई है।

टेरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ईंधन बचाने, विदेश यात्राओं को स्थगित करने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए सोने की खरीद को टालने के आह्वान का हवाला देते हुए कहा कि देश में ऐसा समय आ रहा है जहां हर लीटर ईंधन, आयातित संसाधन का हर हिस्सा और खर्च किया गया हर रुपया मायने रखता है। इस सप्ताह की शुरुआत में हैदराबाद में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों और बढ़ते आयात बिलों के मद्देनजर सामूहिक मितव्ययिता का आह्वान किया था। टेरी के अध्ययन में कहा गया है कि भारतीय सशस्त्र बल के लिए परिवर्तनकारी अवसर है। अध्ययन में 13 सिम्युलेटर सिस्टम का आकलन किया गया, जिसमें इन्फैंट्री, आर्टिलरी, सेना, एयर डिफेंस, आर्मर्ड कार्प्स और मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री शामिल हैं। टेरी के वरिष्ठ फेलो और निदेशक सौविक भट्टाचार्य ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरणीय जिम्मेदारी अब अलग-अलग नहीं रह गए हैं। रक्षा सिमुलेटर यह प्रदर्शित करते हैं कि कैसे तकनीकी नवाचार युद्ध की तैयारी को मजबूत कर सकता है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकता है।

- द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में किया गया दावा
- सिमुलेटर से ईंधन की खपत कम करने में मिल सकती है मदद

चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बलिया पहुंची सीबीआइ ने राज सिंह के स्वजन से 10 घंटे की पूछताछ

जागरण संवाददाता, बलिया

- हत्याकांड में सीबीआइ की 10 सदस्यीय टीम ने राज के बड़े भाई, मां व बहन-बहनोई से की पूछताछ
- चार दौर की पूछताछ में राजनीतिक संबंध, संपत्ति व बैंक खातों की जानकारी भी जुटाई

सदर कोतवाली में पूछताछ के बाद शुक्रवार रात साढ़े सात बजे के करीब बाहर निकलते राज सिंह के स्वजन। जागरण

बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक रहे चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में सीबीआइ ने जांच तेज कर दी है। शुक्रवार को सीबीआइ की 10 सदस्यीय टीम ने इस मामले में गिरफ्तार राज सिंह के परिवार और मित्र से गहन पूछताछ की। इस दौरान राज सिंह की संपत्ति और बैंक खातों की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने राज के स्वजन और मित्र से करीब चार दौर में करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। गुरुवार सुबह 10 बजे बलिया पहुंची टीम पूछताछ के बाद शुक्रवार रात पौने आठ बजे लखनऊ के लिए रवाना हो गई। बलिया के एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि सीबीआइ ने राज सिंह के परिवार वालों और उसके दोस्त से पूछताछ की है।

गत छह मई की रात बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई थी। 10 मई को हत्याकांड में बक्सर से मयंक मिश्रा व विक्की मौर्य को पकड़ा गया। उनसे पूछताछ के आधार पर 11 मई को अयोध्या से राज सिंह को पकड़ा गया था। राज की मां जामवंती ने बताया कि राज के बड़े भाई ऋषवंत सिंह और उसके एक मित्र को गुरुवार दोपहर तीन बजे सीबीआइ ने कोतवाली थाने बुलाया। तीन घंटे तक पूछताछ चली। इसमें राज के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। अगले दिन शुक्रवार को सुबह नौ बजे राज के स्वजन को बुलाया गया। दो घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया, फिर दोपहर में पूछताछ की गई। शुक्रवार शाम छह बजे आधा घंटे तक पूछताछ की गई। टीम ने राज के बड़े भाई, मां और बहन-बहनोई से भी पूछताछ की। परिवार की ओर से घटना के दिन घर और कपड़े के शोरूम के सीसीटीवी फुटेज सहित कई दस्तावेज टीम को सौंपे गए। जामवंती सिंह ने दावा किया कि घटना के दिन राज बलिया में था। आठ मई को लखनऊ में शादी में जाने के लिए राज ने छह मई को बलिया की दुकान में कपड़े खरीदे।

नर्मदा के आदिवासियों को मिली संजीवनी, घर-घर तैयार हुए बायोगैस प्लांट

शत्रुघ्न शर्मा • जागरण

- आदिवासियों को बायोगैस प्लांट देने का मोदी का वादा पूरा कर रही गुजरात सरकार
- नर्मदा जिले की गरुड़ेश्वर तहसील की 38 ग्राम पंचायतों के 89 गांवों में यह योजना लागू

अहमदाबाद : गुजरात के नर्मदा जिले के आदिवासी परिवारों को संजीवनी मिल गई है। अब तक साढ़े छह सौ परिवार बायोगैस प्लांट लगाकर अपने घर की रसोई की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू आफ यूनिटी के पास रहने वाले करीब एक हजार आदिवासी परिवार रसोई गैस के मामले में आत्मनिर्भर बनने की राह पर अग्रसर हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के दौरान स्टैच्यू आफ यूनिटी के आसपास रहने वाले 1000 आदिवासी घरों में बायोगैस प्लांट स्थापित करने की घोषणा की थी। नर्मदा जिले की गरुड़ेश्वर तहसील की 38 ग्राम पंचायतों के 89 गांवों में यह योजना लागू की गई है। इन परिवारों को पारंपरिक लकड़ी के ईंधन से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। वाघपुरा गांव निवासी रवि के जीवन में इस बायोगैस प्लांट के कारण बड़ा बदलाव आया है। उनके अनुसार, अब उन्हें न तो ईंधन के लिए लकड़ी की चिंता है और न ही सिलेंडर का झंझट। बायोगैस प्लांट के जरिये रोजाना स्वच्छ ईंधन मिलता है। चंदू तडवी बताते हैं कि योजना से महिलाओं का जीवन बदल गया है। बायोगैस प्लांट से महिलाओं को सबसे अधिक लाभ हुआ है। चूल्हे पर खाना बनाने के कारण आंखों को नुकसान होता था। लेकिन, अब बायोगैस के उपयोग से उन्हें धुएं से मुक्ति मिल गई है।

चिंतन

यह महंगाई की शुरुआत लग सकते हैं और झटके

आर्थिकी
डॉ. जयंतीलाल भंडारी

न दिनों पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक भूराजनीतिक चुनौतियों के बीच देश में महंगाई बढ़ने और विकास दर में कमी आने की चुनौती उभरकर दिखाई दे रही है। 15 मई को पेट्रोल- डीजल की कीमतों में तीन-तीन रुपये की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में अप्रैल 2026 में थोक महंगाई बढ़कर 8.3 प्रतिशत और खुदरा महंगाई बढ़कर 3.48 प्रतिशत हो गई है। महंगाई से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में भी भारत में महंगाई बढ़ने के विश्लेषण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई से जहां आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन में मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं अर्थव्यवस्था की विकास रफ्तार धीमी हो रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और गैस का संयम से इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत के पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं। ऐसे में पश्चिम एशियाई संकट के कारण नागरिकों को यह जिम्मेदारी निभानी होगी कि वे जहां तक संभव हो, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। इलेक्ट्रिक कारों और कार पूलिंग को प्राथमिकता दें। साथ ही कोरोना काल की तरह वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग्स को बढ़ावा दें। देश और दुनिया के अर्थ विशेषज्ञ भी भारत को पश्चिम एशिया संकट के झटकों और वैश्विक अनिश्चितता के लिए खुद को तैयार रखने संबंधी टिप्पणियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि महंगाई का दबाव बढ़ने पर अब नीतिगत रेपो रेट में वृद्धि की कार्रवाई की जानी होगी। यह बात महत्वपूर्ण है कि घटती हुई विकास दर के बीच भी भारत की कई आर्थिक अनुकूलताएं भी दिखाई दे रही हैं। भारत लगातार व्यापार समझौतों के माध्यम से निर्यात बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। राजनीतिक स्थिरता के परिदृश्य से भारत पर दुनिया का आर्थिक भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब भारत में देशी-विदेशी निवेश बढ़ने के साथ विदेश व्यापार और सेवा निर्यात का ग्राफ भी बढ़ते हुए दिखाई दे सकेगा। इस समय भारत के द्वारा विकास दर की चुनौती का सामना करने के लिए एफटीए और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का अधिकतम लाभ उठाने की जरूरत है। इसके मद्देनजर निर्यातकों को कम या शून्य का लाभ देने के साथ प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण जैसी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। यह कोई छोटी बात नहीं है कि दुनिया के विकसित और विकासशील देश भारत के साथ कारोबार बढ़ाने के मद्देनजर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय दुनिया में आकार ले रही नई विश्व अर्थव्यवस्था भारत की ओर झुकी हुई है। पहले अधिकांश अंतरराष्ट्रीय आर्थिक-व्यापारिक टिप्पणियों में कहा जाता था कि भारत ने मौका गंवा दिया, लेकिन अब दुनिया भर के देशों का मानना है कि अगर वे आर्थिक रूप से तेजी से बढ़ते हुए भारत के साथ नहीं जुड़ पाए तो वे महत्वपूर्ण मौका गंवा देंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में पिछले दिनों भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक एफटीए पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत न्यूजीलैंड में 100 प्रतिशत भारतीय निर्यात पर शून्य शुल्क (जीरो ड्यूटी) सुनिश्चित की गई है। भारत भी न्यूजीलैंड के 95 प्रतिशत निर्यात पर शुल्क

समाप्त करेगा या कम करेगा। इस एफटीए से अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने में मदद मिलेगी। साथ ही न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर के एफडीआई की प्रतिबद्धता भी जताई है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 2025 में भारत के द्वारा ब्रिटेन और ओमान के साथ किए गए एफटीए का भी इसी वर्ष 2026 में आगामी महीनों में कार्यान्वयन शुरू होगा। ये दोनों एफटीए भारत से निर्यात बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाले साबित हो सकते हैं। साथ ही भारत-यूरोपीय संघ के बीच हुए एफटीए का क्रियान्वयन भी भारत के लिए अत्यधिक लाभप्रद होगा। इस एफटीए से दो अरब लोगों का विशाल बाजार बनेगा। इस समझौते को सभी समझौतों की जननी कहा गया है। इस समय मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया और चार यूरोपीय देशों आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टाइन के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (एफ्टा) के साथ सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो रहे एफटीए के और अधिक लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। कनाडा, इजराइल, रूस, पेरू, चिली, दक्षिण अफ्रीका और मेक्सिको के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर काम में तेजी आएगी। यह बात ध्यान रखनी होगी कि अभी अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में जल्दबाजी न की जाए। भारत को अमेरिका के अधिक स्थिर और कानूनी रूप से विश्वसनीय व्यापार प्रणाली विकसित करने तक अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर अंतिम फैसले को लेकर इंतजार करना चाहिए। यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि भारत के द्वारा जितनी कुशलता से व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाएगा, उतने ही अधिक भारत से निर्यात बढ़ सकेंगे। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि विकास दर बढ़ाने के लिए अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करना होगा। पिछले दिनों उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव ने कहा कि नीतिगत सुधारों और आपूर्ति श्रृंखला में बदलावों की मदद से वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आंकड़ा 90 अरब डॉलर के पार जा सकता है। ज्ञातव्य है कि 9 मई को उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक्ष व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) के अधीन काम करने वाली एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया ने कहा कि दुनिया के दस प्रमुख देश भारत में उद्योग-कारोबार के 10 प्रमुख क्षेत्रों में 45 अरब डॉलर के निवेश करने के इच्छुक हैं। ऐसी संभावनाओं को साकार करने के लिए भारत में बंदरगाह, एयरकार्गो, लॉजिस्टिक्स और अन्य निवेश सुविधाएं बेहतर बनाना होगी। निश्चित रूप से पश्चिम एशिया संकट के बीच इस समय जब भारत की विकास दर घटते हुए दिखाई दे रही है, तब अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हमें बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ कई बातों पर ध्यान देना होगा। अब अल्पकालिक वृद्धि के पीछे भागने के बजाय, भारत को मध्यम अवधि की राजकोषीय और बाह्य स्थिरता को सुरक्षित रखना होगा। लंबित सुधारों को आगे बढ़ाना होगा। अब भारत का ध्यान सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर होना चाहिए। एआई जैसे उच्च-स्तरीय क्षेत्रों में निवेश, मजबूत डिजिटल अधोसंरचना, और नियामक बाधाओं को बहुपक्षीय प्रयासों के माध्यम से आसान बनाना होगा, जो सीमाओं के पार सेवा निर्यात को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकें। इस बात की ओर भी ध्यान देना होगा कि भारत का जो निर्यात कुछ ही बाजारों और कुछ ही देशों तक सीमित है, उसे विभिन्न वस्तुओं और अधिक देशों तक विस्तारित किया जाए। इन सबके साथ-साथ बुनियादी ढांचा, निवेश अनुकूल वातावरण, नवीनीकरण ऊर्जा आदि को ध्यान में रखकर भारत दुनिया का और अधिक आर्थिक भरोसा बढ़ा सकेगा।

न दिनों पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक भूराजनीतिक चुनौतियों के बीच देश में महंगाई बढ़ने और विकास दर में कमी आने की चुनौती उभरकर दिखाई दे रही है। 15 मई को पेट्रोल- डीजल की कीमतों में तीन-तीन रुपये की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में अप्रैल 2026 में थोक महंगाई बढ़कर 8.3 प्रतिशत और खुदरा महंगाई बढ़कर 3.48 प्रतिशत हो गई है। महंगाई से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में भी भारत में महंगाई बढ़ने के विश्लेषण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इनके साथ-साथ बुनियादी ढांचा, निवेश अनुकूल वातावरण, नवीनीकरण ऊर्जा आदि को ध्यान में रखकर भारत दुनिया का और अधिक आर्थिक भरोसा बढ़ा सकेगा।

(लेखक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

सियासत
योगेश कुमार सोनी

आम आदमी पार्टी को पुनः स्थापित होने की जरूरत

बीते दिनों आम आदमी पार्टी में आए भूचाल से अंदरूनी खाने पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर पड़ी है। पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। यह घटना आप के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। राज्यसभा में पार्टी के 10 में से केवल 3 सदस्य ही रह गए हैं। यह विषय एक बारगी देशभर में सुर्खियां बन गया था, लेकिन बीते दिनों पांच राज्यों के चुनाव में दब गया। अब फिर इस घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। मौजूदा स्थिति में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की नींव पूरी तरह हिल चुकी है। जैसा कि सब जानते हैं कि आप की सत्ता का रास्ता दिल्ली से निकला था, उसके बाद उसने देशभर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी और पंजाब का भी किला फतह किया था। जिस स्तर से पार्टी की रफ्तार पकड़ी थी, उससे बहुत कुछ बड़ा हो रहा था और आगे भी भविष्य सुगम नजर आ रहा था, लेकिन भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि तीन तिहाई सांसद एक साथ दूसरी पार्टी में चले गए। कानून के अनुसार यदि कोई निर्वाचित सांसद स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ता है या किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है। 'स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने' का मतलब सिर्फ इस्तीफा देना ही नहीं, बल्कि दूसरी पार्टी जॉइन करना भी इसी कैटेगरी में आता है। दिल्ली के परिवेश में समझें तो दशकभर राजधानी में राज करके आज आम आदमी पार्टी विपक्ष का किरदार निभा रही है। अब आप की इस स्थिति के बाद जो सांसद विपक्ष में बैठकर पार्टी की आवाज उठाते थे, आज वो बीजेपी के समर्थन में बोल रहे हैं। इससे यह तो स्पष्ट है कि पार्टी चाहे इस पर कुछ भी सफाई दे, लेकिन आंतरिक तौर पर स्थिति कमजोर पड़ गई। इससे अब दिल्ली की राह भी कठिन बन गई है। अगले साल पंजाब में भी विधानसभा चुनाव हैं, इसको भी लेकर पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है। बागी सांसदों ने आप का साथ तो छोड़ा ही, लेकिन तुरंत बीजेपी भी ज्वाइन कर पार्टी के अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया। इस वजह से जो पार्टी अपनी आक्रामक शैली से चुनाव लड़ने के लिए जानी जाती थी, आज वह बेहद कमजोर सी महसूस कर रही होगी। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत साहनी संसद में रचनात्मक तरीके से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते रहे हैं। अब यह सारी आवाजें विपरीत दिशा के साथ निकल रही हैं अर्थात जो सत्ता पक्ष के विपरीत मुखर होते थे, आज वह उनका ही समर्थन कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में ऐसी बगावत नई नहीं है लेकिन सवाल है कि जिस पार्टी को स्थापित हुए अभी डेढ़ दशक भी नहीं हुआ, उसके महत्वपूर्ण नेता आखिर दामन क्यों छोड़ते जा रहे हैं? राघव चड्ढा, संदीप पाठक तो पार्टी के शुरुआती दिनों से रणनीतिकार और संगठक रहे हैं। दोनों केजरीवाल के नजदीक भी माने जाते रहे। स्वाति मालीवाल का दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर कार्यक्षेत्र तो दिल्ली था पर, बीजेपी शासित राज्यों में हुए कथित महिला अत्याचारों की जांच के लिए भी वह पहुंचती थीं। अब वे भी बगावती हैं। बहरहाल, कई ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा से ज्यादा लोकसभा में ज्यादा प्रभावी माने जाते हैं जिससे किसी भी राज्य की केन्द्रीय स्तर की समस्या या सुझाव को राष्ट्रीय स्तर समझा जाता है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है, जब आम आदमी पार्टी को बड़े नाम छोड़कर निकले हों। पार्टी के संस्थापकों में शामिल रहे योगेंद्र यादव और मशहूर वकील प्रशांत भूषण को शुरू में ही निकल गए थे। अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल के साथ रहीं पूर्व पुलिस अधिकारी किरण बेदी ने अलग राह चुनी। जेएनयू के प्रोफेसर रहे आनंद कुमार और कैलाश गहलोत समेत कई अलग हो गए। कुमार विश्वास ने पार्टी से दूर रहकर अपनी कवि रूप में पहचान बनाए रखना ही सही समझा। संजय सिंह ने पहले भी बागियों के कडे.शब्दों का प्रयोग किया था और इन सातों सांसदों ने पंजाब की पीठ में छुरा घोंपने जैसा काम किया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आरोप लगाया कि वे एक अच्छी सरकार के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं। इन सब प्रकरण के बाद दिल्ली की राह को लेकर विश्वास को बनाए रखने के लिए कितनी चुनौतियां सामने आ चुकी इसको केजरीवाल भलिभांति समझ तो रहे हैं लेकिन हालात को लेकर अब वो इससे कैसे निकलें इसकी रणनीति बेहद गंभीरता से बनानी होगी चूंकि दिल्ली में उनका वोट ऑफ प्रतिशत ठीक है। भले ही वो चुनाव हारे हो, समीकरणों के आधार पर यह तो तय हो जाता है कि अब पार्टी को पुनः स्थापित होने के लिए फिर से नई रणनीति की जरूरत है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

हर मानव में शुभ व अशुभ इच्छाएं होती है

संकलित
दर्शन

शिव कल्याणकारी हैं। शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। कैलाश का अर्थ ही है कि जहां केवल उत्सव हो, केवल आनंद हो। श्रावण के महीने में संपूर्ण वातावरण उत्सव से भर जाता है। शिव-तत्व अपने चरम पर होता है, यह सहजता से उपलब्ध होता है। इसलिए यह मास भगवान शिव की पूजा करने के लिए सर्वोत्तम मास है। हमारे प्राचीन ऋषि अत्यंत बुद्धिमान थे। वे जानते थे कि हर मानव के भीतर इच्छाएं होती हैं, कुछ शुभ और कुछ अशुभ। जीवन में प्रगति के लिए आवश्यक है कि शुभ इच्छाएं फलित हों। विवेक के उपयोग से मनुष्य यह निर्णय ले सकता है कि कौन-सी इच्छाएं उसके लिए लाभदायक हैं और उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए क्या कार्य कर सकता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन वह अपने इच्छित लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता है। उसे मार्ग में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कारण विविध हो सकते हैं, कुछ अत्यंत सूक्ष्म, कुछ अधिक सूक्ष्म नहीं। ऋषियों ने इस समस्या पर विचार किया और एक अद्भुत समाधान निकाला। उन्होंने मानव कल्याण के लिए संकल्प और पूजा की प्रक्रिया तैयार की। पूजा आरंभ करने से पूर्व पूजा करने वाले यजमान द्वारा संकल्प लिया जाता है। संकल्प वह विशिष्ट उद्देश्य है, जिसके लिए पूजा आयोजित की जा रही है। संकल्प का उच्चारण करने से पहले स्थान (देश) और समय (काल) को परिभाषित किया जाता है, जहां पूजा आयोजित की जा रही है।

सुख शांति चाहते हैं तो काम हमेशा ईमानदारी से करें

संकलित
प्रेरणा

एक दिन गुरु नानक के पास एक गांव का जमींदार आया। जमींदार गुरु नानक के लिए भोजन लेकर आया था। गुरु नानक ने जमींदार से कहा कि भोजन यहां रख दीजिए। जमींदार बोला कि मैं आपको खाना परोसना चाहता हूं। कृपया आप खाना खा लीजिए। नानक जी ने उसे कुछ देर रुकने के लिए कहा। तभी वहां एक गरीब व्यक्ति आया। उसने गुरु नानक से कहा कि मैं आपके लिए रोटी लेकर आया हूं। जमींदार ने उसकी ओर देखकर कहा कि खाना तो आ चुका है, तुम ये रोटी वापस ले जाओ। नानक जी ने कहा कि नहीं, खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। जमींदार ने कहा कि मैं भी आपके लिए खाने की बहुत सी चीजें लेकर आया हूं। मेरी थाली में रोटी के साथ ही अन्य पकवान भी हैं, मिठाई भी है। नानक जी बोले कि हम उसे भी चख लेंगे। गुरु नानक ने उस गरीब की आधी रोटी खा ली और आधी अपने हाथ में रख ली। ये देखकर जमींदार ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आपने ये क्या किया? मेरा स्वादिष्ट भोजन छोड़कर इसकी साधारण रोटी खा ली। नानक जी ने गरीब की आधी रोटी को हाथों से मसला तो उसमें से दूध की बूंद गिरीं। इसके बाद नानक जी ने जमींदार की मिठाई को मसला तो उसमें खून की बूंद गिरीं। वहां मौजूद लोग ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। नानक जी ने उस जमींदार से कहा कि इसकी सूखी रोटी में ईमानदारी है और तुम्हारी मिठाई में कहीं न कहीं बेईमानी है। इसलिए मैंने इस गरीब की रोटी खाई है और तुम्हारी मिठाई नहीं खाई।

अंतर्मन

आज की पाती

नीट परीक्षा का रद्द होना सरकार की साख पर सवाल

देश में हाल ही में आयोजित नीट परीक्षा में करीब 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इन विद्यार्थियों ने डॉक्टर बनने का सपना साकार करने के लिए वर्षों तक कठिन परिश्रम किया,घर-परिवार से दूर रहकर दिन-रात पढ़ाई की और अपने भविष्य को संवारने के लिए हरसंभव त्याग किया। लेकिन परीक्षा समाप्त होते ही पेपर लीक की खबरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जांच एजेंसियों के लगातार खुलासों से यह स्पष्ट हो गया कि प्रश्नपत्र बड़े पैमाने पर और सुनियोजित तरीके से लीक किए गए थे।

- सांकेत जोशी, बिलासपुर

ट्रेंड

ज्ञान जीवन की पूंजी

ज्ञान जीवन की ऐसी पूंजी है, जिससे बड़े से बड़े लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ज्ञान हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर सफलता और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। विद्वान की विश्व में प्रशंसा होती है, विद्वान का सर्वत्र सम्मान होता है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सुखदेव की जयंती

अमर क्रांतिकारी सुखदेव की जयंती पर मैं उन्हें नमन अर्पित करता हूं। अदम्य साहस, देशभक्ति और बलिदान के प्रतीक सुखदेव ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया, स्वतंत्रता को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया।

- अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

डॉ. केतन को नमन

गोवा से हमारे युवा कांग्रेस नेता डॉ. केतन भाटिकर के असामयिक निधन से मुझे गहरा दुःख हुआ है। वे एक प्रख्यात फिजियोथेरेपिस्ट थे, जिन्होंने निष्ठा और दृढ़ विश्वास के साथ जनता की सेवा की। उनके परिवार, मित्रों और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं।

- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

प्रबुद्ध समाज का सम्मान

भारत ने हमेशा अपने प्रबुद्ध समाज का सम्मान किया है। देश, समय और परिस्थितियों के अनुरूप समाज को सही दिशा में मार्गदर्शन करने में हमारे प्रबुद्ध नागरिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

करंट अफेयर

हंटा वायरस प्रभावित छह यात्री आस्ट्रेलिया पहुंचे

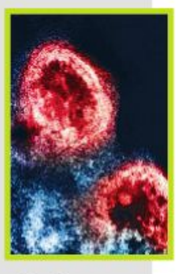

हंटा वायरस की चपेट में आए एक क्रूज जहाज के छह यात्री शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्हें कम से कम तीन सप्ताह तक पृथक-वास में रहना होगा। नीदरलैंड से इन्हें लेकर आया 'गल्फस्ट्रीम लॉन्ग-रेंज बिजनेस जेट' पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य की राजधानी पर्थ के बाहर स्थित 'आरएएएफ बेस पियर्स' पर उतरा। यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नजदीकी 'बुल्सब्रुक' पृथक-वास केंद्र में स्थानांतरित किया जाना था। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने बृहस्पतिवार को कहा था कि सरकार इस वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से की तुलना में सबसे मजबूत पृथक-वास व्यवस्थाओं में से एक लागू करेगी। पांच ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड के एक नागरिक को इस केंद्र में तीन सप्ताह की पृथक-वास अवधि बितानी होगी। बटलर ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार इस वायरस के लक्षण सामने आने में 42 दिन तक का समय लग सकता है। इसलिए, तीन सप्ताह के पृथक-वास के बाद शेष दिनों के दौरान क्या सावधानियां बरती जाएं, इस पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, नीदरलैंड से रवाना होने से पहले इन सभी छह यात्रियों की वायरस जांच रिपोर्ट निगेटिव आई थी और किसी में भी इसके लक्षण नहीं दिखे थे।

ऑफ बीट

अब वेबसाइटें बार-बार क्यों मांगती है कैप्चा

आप किसी लोकप्रिय संगीत कार्यक्रम के टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं और लिंक पर क्लिक करते ही भुगतान से पहले आपसे छोटे-छोटे धुंधले चित्रों के समूह में ट्रैफिक लाइट, साइकिल या ज़ेब्रा क्रॉसिंग पहचानने को कहा जाता है। बहुत से लोगों के लिए यह अब रोजमर्रा की ऑनलाइन जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। वित्तीय ऐप में लॉग इन करना, ऑनलाइन खरीदारी करना या नया खाता बनाना अब अक्सर ''यह साबित करने'' से जुड़ गया है कि आप मानव हैं। इन प्रणालियों को 'कैप्चा' (सीएपीटीसीएचए) कहा जाता है। सवाल यह है कि ये अब हर जगह क्यों दिखाई देने लगी हैं? इसका सीधा जवाब यह है कि वेबसाइटें अब बॉट्स के खिलाफ तेजी से बढ़ती जंग लड़ रही हैं। बॉट ऐसे स्वचालित सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटरनेट पर मनुष्यों जैसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में प्रगति के कारण ये बॉट अब पहले से कहीं अधिक स्मार्ट, सस्ते और पहचान में मुश्किल हो गए हैं। वेबसाइटों को क्यों चाहिए यह सबूत कि आप मानव हैं: आज इंटरनेट पर होने वाले भारी ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा स्वचालित प्रणालियों से संबद्ध है। इनमें कुछ उपयोगी होते हैं, जैसे गूगल सर्च के लिए पेजों को सूचीबद्ध करने वाले सर्च इंजन क्रॉलर।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

संपादकीय जागरण

शनिवार, 16 मई, 2026 : ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या वि. 2083

जिसको लगन है वह साधन भी पा जाता है

मंदिर ही है भोजशाला

मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद मामले में इंदौर हाई कोर्ट के इस निर्णय पर आश्चर्य नहीं कि भोजशाला परिसर एक हिंदू मंदिर ही था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआइ के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें निर्देशित किया गया था कि भोजशाला परिसर में शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाएगी और मंगलवार को पूजा होगी। हाई कोर्ट ने मुस्लिम समाज से सरकार से मस्जिद के लिए अलग से जमीन की मांग करने को कहा है। यह फैसला अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्मरण कराने वाला है। इंदौर हाई कोर्ट के फैसले पर इसलिए किसी को चकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि परमार राजवंश के राजा भोज के वंशजों ने भोजशाला परिसर में मां वाग्देवी यानी देवी सरस्वती के मंदिर का निर्माण कराया था। एक समय यह संस्कृत शिक्षण का बड़ा केंद्र था। इस धार्मिक स्थल के मंदिर होने के साक्ष्य कथित कमाल मौला मस्जिद की दीवारों पर उससे भी स्पष्ट रूप से अंकित थे, जैसे अयोध्या में मिले थे। इस विवादित स्थल को लेकर इंदौर हाई कोर्ट इसलिए अपना फैसला दे सका, क्योंकि यह स्थल 1958 के अधिनियम के तहत एक एएसआइ संरक्षित स्मारक है। यदि ऐसा नहीं होता तो 1991 में पारित धार्मिक स्थल अधिनियम के चलते इस स्थान की यथास्थिति कायम रहती। दुर्भाग्य से इस भेदभावपूर्ण अधिनियम के चलते धार जैसे अन्य मामलों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है और इसके चलते समय-समय पर विवाद उभरते रहते हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव पर बुरा असर डालते हैं। यह अच्छा है कि धार मामले में हाई कोर्ट की ओर से फैसला आने के कारण किसी तरह का सांप्रदायिक विग्रह देखने को नहीं मिला, लेकिन इतना तो है ही कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, इसकी अनदेखी न की जाए कि इस तरह के न जाने कितने मामले हैं। उनके निस्तारण में जो धार्मिक स्थल अधिनियम बाधक है, उसे भी चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के लिए उचित यह होगा कि वह इस अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं का निपटारा शीघ्र करे। इसी के साथ यह भी उचित होगा कि विवादित धार्मिक स्थलों को संबंधित पक्ष अर्थात हिंदू और मुस्लिम आपसी सहमति से सुलझाएं। इससे उनमें सद्भाव बढ़ेगा। यह तभी संभव हो पाएगा, जब मुस्लिम पक्ष इस यथार्थ को स्वीकार करेगा कि गजनवी, गोरी, खिलजी, बाबर, औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने सैकड़ों मंदिरों का ध्वंस ही नहीं किया, बल्कि उनके ही अवशेषों से ही वहां मस्जिदें बनवाईं। ऐसा केवल अयोध्या और धार में ही नहीं किया गया, बल्कि वाराणसी, मथुरा, संभल, जौनपुर समेत न जाने कितने स्थानों पर किया गया।

घोर लापरवाही

बाहरी दिल्ली के बुध विहार क्षेत्र में सड़क किनारे बने एमसीडी के नाले में गिरने से व्यक्ति की मौत की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और एमसीडी कर्मचारियों की घोर लापरवाही को उजागर करती है। ये मामला इसलिए और भी गंभीर हो जाता है कि मुख्यमंत्री ने सभी खुले नाले बंद करने के आदेश दिए थे, इसके बावजूद नाले ढके नहीं गए और ये जानलेवा हादसा हो गया। हादसा शुक्रवार सुबह रिठाला रोड पर उस समय हुआ, जब एक व्यक्ति पैदल जा रहा था। लोगों के अनुसार 15 दिन पूर्व नाले की सफाई की गई थी, लेकिन सफाई के बाद नाला खुला छोड़ दिया गया था।

दिल्ली की सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों को अपने-अपने नाले ढकने चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी नाले में न गिरने पाए

दिल्ली में नाले खुले होने और उनमें गिरकर लोगों की मौत होने की घटनाएं आए दिन सामने आती हैं, लेकिन ये निराशाजनक है कि एक के बाद एक हादसे होने के बावजूद सरकारी एजेंसियों की नींद नहीं टूटती और नाले ढके नहीं जाते। दस दिन पूर्व ही बाहरी दिल्ली के मुकुंदपुर क्षेत्र में खुले नाले में गिरने से दो साल की बच्ची की मौत हो गई थी। इस घटना से सबक लेते हुए दिल्ली की सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों को अपने-अपने नाले ढकने चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी नाले में न गिरने पाए।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल की जगह वीडी सतीशन को केरलम का मुख्यमंत्री बनाकर सही फैसला लिया?

आज का सवाल

क्या पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने आवश्यक हो गए थे?

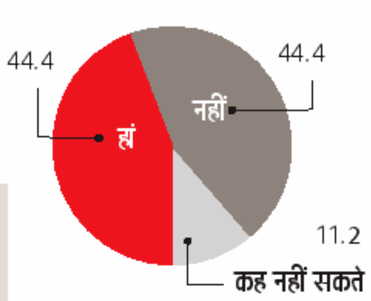

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। (सभी आकड़े प्रतिशत)

पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं

अशोक कुमार

भारत के सामने चुनौती केवल आतंकी हमलों का जवाब देने की नहीं, बल्कि उन्हें पहले से भांपकर विफल करने की भी है

हाल में आपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने के समय सभी ने इसे स्मरण किया कि भारत ने किस तरह पाकिस्तान को धूल चटाई थी, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की फितरत अभी बदली नहीं है। इसका प्रमाण है पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर का यह बयान कि यदि पाकिस्तान पर फिर हमला हुआ तो जवाब बेहद व्यापक, खतरनाक, दूरगामी और दर्दनाक होंगे। हम इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क अब भी सक्रिय हैं। उसकी कुख्यात खुफिया एजेंसी आइएसआइ भारत विरोधी गतिविधियों में पहले की तरह ही लिप्त है और अमेरिकी समर्थन के कारण उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। यह मान लेना उचित नहीं होगा कि पाकिस्तान सुधरने वाला है। पिछले साल दिल्ली में लाल किले के निकट विस्फोट और सफेदपोश आतंकी माड्यूल का सामने आना यही जाहिर करता है कि आतंक का खतरा बना हुआ है। पिछले कुछ समय में एनआइए और विभिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा कई संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारियां हुई हैं। ये हथियारों की व्यवस्था, लाजिस्टिक्स प्रबंधन और आतंकी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।

सबसे अधिक चिंता का विषय आतंकवाद से जुड़े व्यक्तियों की बदलती प्रोफाइल है। कुछ आरोपी शिक्षित पेशेवर थे, जिनमें डाक्टर और तकनीकी रूप से दक्ष लोग भी थे। यह व्हाइट कालर टेररिज्म की बढ़ती पैठ को दर्शाता है, जहां सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और वित्तीय क्षमता का उपयोग आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा है। ऐसे तत्वों की पहचान करना अधिक कठिन होता है, क्योंकि वे वैध संस्थागत ढांचों के भीतर रहकर बहुल लो प्रोफाइल होकर काम करते हैं। भारत में इस्लामिक स्टेट से जुड़े माड्यूल भी सक्रिय दिख रहे हैं। ऐसे स्लीपर सेल सामने आए हैं, जो भर्ती, निगरानी और विस्फोटक प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों में शामिल थे। विभिन्न राज्यों में हुई गिरफ्तारियां यह भी दर्शाती हैं कि ये अलग-थलग समूह नहीं, बल्कि व्यापक और परस्पर जुड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं।

आज आतंकवाद तेजी से अपना स्वरूप बदल रहा है। यह अब केवल बंदूक और बम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अधिक विकेंद्रीकृत, तकनीक-आधारित और पकड़ से बचने वाला स्वरूप ले चुका है। अवैध हथियार तस्करी भी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। एके-47 जैसे हथियारों की बरामदगी ने सीमा पार से जुड़े संगठित सप्लाई नेटवर्क को उजागर किया है, जो बाहरी समर्थन और घरेलू नेटवर्कों के

अवधेश राजपूत

गठजोड़ को रेखांकित करता है। स्पष्ट है कि भर्ती, फंडिंग, लाजिस्टिक्स और क्रियान्वयन का एक सुव्यवस्थित तंत्र सक्रिय है। यह बढ़ती हुई परिष्कृत रणनीति आतंकी ढांचे की बारीकियों में भी जाहिर हो रही है। मार्च में दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर आइएसआइ से जुड़े एक जासूसी षड्यंत्र का खुलासा हुआ था, जिसमें गुप्त रूप से लगाए गए सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरों का उपयोग कर सैन्य गतिविधियों की रियल-टाइम फुटेज पाकिस्तानी हैंडलरों तक भेजी जा रही थी। यह दर्शाता है कि निगरानी गतिविधियां अब अधिक गुप्त और तकनीक आधारित होती जा रही हैं। ऐसे उपकरण सैन्य गतिविधियों का मानचित्रण, कमजोरियों की पहचान और भविष्य के हमलों में सहायता कर सकते हैं। चूंकि छोटी घटनाएं भी किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती हैं, इसलिए निरंतर सतर्कता अत्यंत आवश्यक है।

एक अन्य गंभीर चिंता वैध व्यावसायिक प्लेटफार्मों के दुरुपयोग की है, जिसे कारपोरेट जिहाद के रूप में भी देखा जाता है। नासिक स्थित एक बीपीओ से जुड़े मामले ने यह दिखाया कि किस प्रकार व्यावसायिक संस्थानों का उपयोग नेटवर्क तैयार करने और आतंकी गतिविधियों को आड़ देने के लिए किया जा सकता है। यह दर्शाता है कि आतंकी रणनीतियां अब पारंपरिक तरीकों से कहीं आगे बढ़ चुकी हैं। डिजिटल कट्टरपंथ भी तेजी से बढ़ता खतरा बन चुका है। आनलाइन प्रचार, एन्क्रिप्टेड प्लेटफार्म और लक्षित संदेशों के माध्यम से युवाओं को प्रभावित और भर्ती किया जा रहा है। इससे आतंकवाद का खतरा अधिक व्यापक, अदृश्य और दीर्घकालिक बन गया है।

पाकिस्तान की ओर से खालिस्तान जैसे पुराने मुद्दे को पुनर्जीवित कर भारत में माहौल बिगाड़ने के प्रयास जारी हैं। चंडीगढ़ में भाजपा कार्यालय के पास विस्फोट, जालंधर में बीएसएफ मुख्यालय के बाहर धमाका तथा आइएसआइ समर्थित माड्यूलों का पर्दाफाश इसी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। इन गतिविधियों को डिजिटल माध्यम से सामाजिक विभाजन गहरा करने और जनमत प्रभावित करने का हिस्सा भी समझा जा रहा है। ऐसे में भारत किसी भी प्रकार की आत्मसंतुष्टि का जोखिम नहीं उठा सकता।

आपरेशन सिंदूर की सफलता को एक मजबूत और आधुनिक आंतरिक सुरक्षा ढांचे का समर्थन मिलना आवश्यक है। विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, रियल-टाइम खुफिया सूचनाओं को साझा करना और उन्नत तकनीक का उपयोग समय रहते खतरे की पहचान के लिए बेहद जरूरी है। इस क्रम में 'प्रहार' जैसे त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ-साथ कट्टरपंथ के मूल कारणों पर भी प्रभावी ढंग से काम करना होगा। युवाओं को उग्रवाद और भ्रामक सूचनाओं के प्रति जागरूक करना रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विद्यालय स्तर पर आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी बुनियादी समझ विकसित करना समाज को अधिक सजग और जिम्मेदार बना सकता है। सामाजिक समरसता और समावेशी विकास को बढ़ावा देना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि अलगाव और असंतोष का लाभ अक्सर आतंकी संगठन उठाते हैं। आतंक के विरुद्ध यह संघर्ष केवल भौतिक नहीं, बल्कि वैचारिक भी है, जिसके लिए प्रभावी प्रतिपक्षी नैरेटिव की आवश्यकता है। भारत के सामने चुनौती केवल आतंकी हमलों का जवाब देने की नहीं, बल्कि उन्हें पहले से भांपकर विफल करने की भी है। हाइब्रिड आतंकवाद के इस दौर में, जहां बाहरी और आंतरिक खतरे तेजी से एक-दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, निरंतर सतर्कता, तैयारी और रणनीतिक दृढ़ता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।

(लेखक उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं)

response@jagran.com

बंगाल को पटरी पर लाने की बारी

प्रो. गौरव वल्लभ

बंगाल की पहली आवश्यकता निवेशकों, वित्तीय संस्थानों और आम नागरिकों के विश्वास को पुनर्स्थापित करने की है

नई सरकार के नेतृत्व में बंगाल का बदलता माहौल ● फाइल

पांच दशकों से अधिक समय बाद पूर्वी भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है, जहां राजनीतिक समन्वय, नीतिगत स्थिरता और आर्थिक संभावनाएं एक साथ आकार ले रही हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भाजपा अब पूर्वी भारत के चार प्रमुख राज्यों-बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में सत्ता में है और केंद्र में भी उसकी सरकार है। 1974 के बाद यह पहला अवसर है जब पूर्वी भारत में इस प्रकार का राजनीतिक समन्वय देखने को मिल रहा है। पिछली बार ऐसा तब हुआ था, जब देश की राजनीतिक और आर्थिक संरचना बिल्कुल अलग थी। इस परिवर्तन का महत्व केवल चुनावी गणित तक सीमित नहीं है। यह उन रणनीतिक अवसरों का संकेत है, जो लंबे समय से संभावनाओं के बावजूद अपेक्षित विकास से वंचित रहे पूर्वी भारत के लिए निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं।

बंगाल में बदलाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के समय बंगाल भारत के सबसे समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली क्षेत्रों में गिना जाता था। कोलकाता केवल एक शहर नहीं था, बल्कि व्यापार, विनिर्माण, वित्त, साहित्य, कला और बौद्धिक विमर्श का राष्ट्रीय केंद्र था, लेकिन समय के साथ राज्य अपनी आर्थिक ऊर्जा खोता गया। सरकारें उद्योग, निवेश और उद्यम के लिए अनुकूल वातावरण तैयार नहीं कर सकीं। उद्योग विरोधी सोच, नीतिगत अनिश्चितता, श्रमिक उग्रवाद और वैचारिक कठोरता ने धीरे-धीरे निवेशकों का विश्वास कम किया। परिणामस्वरूप औद्योगिक गिरावट, पूंजी पलायन और प्रतिभाओं का बड़े पैमाने पर बाहर जाना जारी रहा। 1960-61 में भारत की जीडीपी में बंगाल की हिस्सेदारी लगभग 10.5 प्रतिशत थी, जो आज घटकर लगभग 5.6 प्रतिशत रह गई है। कभी राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर रहने वाली प्रति व्यक्ति आय अब उससे नीचे पहुंच चुकी है। 2011 के बाद 6,600 से अधिक कंपनियां या तो बंद हुईं या राज्य से बाहर चली गईं। यह स्थिति इसलिए दुखद है, क्योंकि बंगाल के पास प्राकृतिक और रणनीतिक शक्तियां हमेशा मौजूद रहीं। उपजाऊ कृषि भूमि, लंबी समुद्री तटरेखा, प्रमुख बंदरगाह, दक्षिण-पूर्व एशिया से निकटता और पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार होने जैसी विशेषताएं किसी भी क्षेत्र को आर्थिक शक्ति बना सकती हैं।

बंगाल बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पूर्वोत्तर भारत के लिए भारत का प्रमुख संपर्क बिंदु है, लेकिन केवल भौगोलिक स्थिति विकास की गारंटी नहीं देती। इसके लिए संस्थागत क्षमता और नीति समन्वय भी उतने ही आवश्यक होते हैं। लंबे समय तक केंद्र और पूर्वी राज्यों के बीच राजनीतिक असमानता के कारण इस क्षेत्र के लिए समग्र विकास रणनीति विकसित नहीं हो सकी। लाजिस्टिक्स कारिडोर, पोर्ट आधुनिकीकरण, औद्योगिक क्षेत्र और सीमा व्यापार जैसी परियोजनाएं समन्वय के अभाव में अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकीं। अब यह बाधा काफी हद तक समाप्त होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक रूप से समन्वित पूर्वी भारत अब दीर्घकालिक योजना निर्माण की संभावना पैदा करता है। ईस्ट कोस्ट इकोनमिक कारिडोर, ताजपुर पोर्ट, लाजिस्टिक्स नेटवर्क, औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर और एक्ट ईस्ट नीति के साथ गहरे एकीकरण को अब अधिक नीति स्थिरता और तेज क्रियान्वयन मिल सकता है। आर्थिक संभावना अत्यंत व्यापक है। भारत-बांग्लादेश व्यापार का आकार वार्षिक 1.8 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है, लेकिन बंगाल अभी भी इसका सीमित लाभ ही प्राप्त कर पाता है। नेपाल और भूटान बंगाल के ट्रांजिट नेटवर्क पर निर्भर हैं, जबकि पूरा पूर्वोत्तर समुद्री संपर्क के लिए इसी क्षेत्र पर आधारित है। कोलकाता और हल्दिया पूर्वी भारत के प्रमुख समुद्री द्वार बने हुए हैं और प्रस्तावित ताजपुर डीप-सी पोर्ट पूरे क्षेत्र की आर्थिक दिशा बदलने की क्षमता रखता है।

हालांकि केवल अवसंरचना बंगाल को पुनर्जीवित नहीं कर सकती। सबसे बड़ी आवश्यकता निवेशकों, वित्तीय संस्थानों और आम नागरिकों के विश्वास को पुनर्स्थापित करने की है। वर्तमान में बंगाल पर लगभग आठ लाख करोड़ रुपये का सार्वजनिक ऋण बोझ है। पूंजीगत व्यय अक्सर कल्याण आधारित खर्चों की तुलना में पीछे रहा है। इसलिए चुनौती कल्याण योजनाओं को समाप्त करने की नहीं, बल्कि उन्हें उत्पादकता, उद्यमिता और भागीदारी के आधार में बदलने की है। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और कृषक बंधु जैसी योजनाओं ने सामाजिक सुरक्षा का व्यापक ढांचा तैयार किया है और इन्हें जारी रहना चाहिए, लेकिन दीर्घकालिक समृद्धि केवल प्रत्यक्ष सहायता से संभव नहीं होगी। कल्याण को सुरक्षा कवच से आगे बढ़ाकर उद्यमिता, कौशल विकास, महिला-नेतृत्व वाले व्यवसाय, एमएसएमई विकास और कृषि मूल्य संवर्धन का आधार बनाना होगा। बंगाल का भविष्य सब्सिडी आधारित राजनीति में नहीं, बल्कि सामान्य नागरिकों को अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदारी का अवसर देने में निहित है। इसके साथ ही शासन व्यवस्था का आधुनिकीकरण भी उतना ही आवश्यक है। पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध प्रशासनिक प्रणाली, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और पूर्वानुमान योग्य स्वीकृति तंत्र अब अपरिहार्य बन चुके हैं।

(लेखक प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्मबल

मनुष्य का जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों से संचालित नहीं होता, बल्कि उसकी वास्तविक दिशा उसकी मनःस्थिति और आत्मबल तय करते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति सदैव अनुकूल परिस्थितियों में नहीं रहता। कभी जीवन में सुख की मधुर धूप आती है तो कभी संघर्षों की कठोर छाया। किंतु जो व्यक्ति परिस्थितियों का दास बन जाता है, वह अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को पहचान नहीं पाता।

वास्तव में परिस्थितियां उतनी प्रभावशाली नहीं होतीं, जितना हमारा दृष्टिकोण। इतिहास के महान व्यक्तियों ने विपरीत परिस्थितियों को ही अपनी साधना का माध्यम बनाया। उनका विश्वास बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि अपने पुरुषार्थ और आत्मबल में था। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लेता है, तब अभाव भी अवसर बन जाते हैं और कठिनाइयां सफलता की सीढ़ियां। आज मनुष्य के पास सुविधाएं पहले से कहीं अधिक हैं, फिर भी उसका मन अशांत और तनावग्रस्त है। इसका कारण बाहरी अभाव नहीं, बल्कि भीतर की अतृप्त इच्छाएं हैं। लोभ, संग्रह और तुलना की प्रवृत्ति मनुष्य को निरंतर बेचैन करती है। जिस क्षण जीवन में तनाव प्रवेश करता है, उसी क्षण सुख और शांति दूर होने लगते हैं। आधुनिक जीवन की अंधी दौड़ ने मनुष्य को स्वयं से भी दूर कर दिया है।

आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन का वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि संतोष, संयम और आत्मविश्वास में निहित है। जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदलने के बजाय अपने आत्मबल को मजबूत करता है, वही सच्चे अर्थों में सफल और शांत जीवन जी पाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम परिस्थितिवादी न बनें, बल्कि आत्मबल, सकारात्मक चिंतन और पुरुषार्थ को अपना आधार बनाएं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी विजय बाहरी संसार पर नहीं, स्वयं पर प्राप्त की गई विजय होती है।

ललित गर्ग

पाठकनामा

pathaknama@nda.jagran.com

तिलहन उत्पादन को मिले बढ़ावा

'समय रहते चेतें' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में पेट्रोलियम के साथ खाद्य तेल को लेकर व्यक्त की गई चिंता पर सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रमों से यह वाक्य हटाना पड़ेगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यह जानकारी हैरत में डालती है कि भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 58 प्रतिशत खाद्य तेल आयात करता है। इसके बावजूद सरकार तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रति अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रही है। उल्लेखनीय है कि हमारे क्षेत्र आजमगढ़ और आसपास में हजारों एकड़ भूमि पर किसान सरसों और दलहन की खेती इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी फसलों को झुंड के झुंड घूमने वाले नीलगाय और घड़रोज जैसे जंगली पशु चट कर जाते हैं। किसान अपनी फसलों की सुरक्षा उस जानवर से कैसे करें, जिसे सरकार और उसके तंत्र का पूरा संरक्षण प्राप्त है? यदि कोई किसान अपनी फसल बचाने के लिए ऐसे पशुओं को मारने या भगाने की कोशिश करता है, तो पुलिस उस पर ऐसे शिकंजा कसती है, मानो वह कोई गंभीर अपराधी हो। स्थिति यह हो गई है कि जो पशु किसानों के लिए शत्रु हैं, वे सरकार के मित्र बन गए हैं। यही कारण है कि किसानों ने अब दलहन और तिलहन की खेती छोड़कर धान और गेहूं की खेती को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। उनसे जो आय होती है, उसी से वे बाजार से दाल और तेल खरीद लेते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे देश में गेहूं और धान का उत्पादन पहले से ही अधिशेष में है। ऐसे में जिन खेतों में तिलहन और दलहन की खेती हो सकती है, वहां इन फसलों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा? यह चिंता सरकार को करनी चाहिए, ताकि देश खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बन सके।

डा. हरिप्रसाद राय, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

तेल कीमतें बढ़ाने की विवशता

देश की नरेन्द्र मोदी सरकार का यह प्रशंसनीय पक्ष रहा कि वर्ष 2022 से चार साल में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की थी। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्धोंमाद के बाद कच्चे तेल के दाम तेजी से ऊपर गए हैं। तेल कीमतों में बढ़ोतरी के लिए भारत नहीं बल्कि युद्ध में लिप्त वे देश जिम्मेदार हैं, जिनके कारण तेल भंडार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उल्टा केंद्र सरकार ने तो मार्च 2024 में राहत देते हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी भी की थी। देश की प्रमुख तेल कंपनियों इंडियन आयल कार्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड आदि को अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग-आपूर्ति एवं क्रय-विक्रय में संतुलन बिठाने के साथ घरेलू ईंधन की कीमतें तय करने का अधिकार है। केंद्र सरकार की विवशता हो गई है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। भविष्य में तेल अर्थव्यवस्था के घाटे को पाटने के लिए और बढ़ोतरी संभावित है। हमें यथासंभव कार पूल सहयोग लेने-देने, सार्वजनिक यातायात के साधनों का प्रयोग करने जैसे अन्य उपाय स्वयं भी अपनाने होंगे।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

सड़क सुरक्षा की चुनौती

भारत तेजी से विकसित होता देश है। आधुनिक सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेस-वे तैयार हो रहे हैं, वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ सड़क दुर्घटनाओं का संकट भी भयावह रूप ले चुका है। आज सड़क हादसे केवल यातायात की समस्या नहीं रह गए हैं, बल्कि यह राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुके हैं। हर दिन सैकड़ों परिवार अपने प्रियजनों को खो रहे हैं। कोई बच्चा अनाथ हो रहा है, कोई माता-पिता अपने जवान बेटे को खो रहे हैं, तो कोई परिवार जीवनभर के लिए अपंगता और आर्थिक संकट में डूब जाता है। यही कारण है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भी सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता जता रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में ''लेन ड्राइविंग'' जैसी कोई अवधारणा ही नहीं रह गई है और यही सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है। अदालत ने सार्वजनिक वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन नहीं लगाए जाने पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि नियम बनने के बावजूद देश में एक प्रतिशत से भी कम सार्वजनिक वाहनों में ये सुरक्षा उपकरण लगे हैं। यह स्थिति बताती है कि सड़क सुरक्षा के नियम केवल कागजों तक सीमित होकर रह गए हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा अत्यंत भयावह है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2024 में लगभग दो लाख लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई। भारत में सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण यातायात नियमों की अनदेखी है।

कांतिलाल मांडोत नई दिल्ली

पोस्ट

भोजशाला मामले पर हाई कोर्ट का आया निर्णय पिछले कुछ समय में देश का मानस जिस तरह से बदला है, उसी का परिणाम है। कांग्रेस की सरकारों ने हिंदू आस्था के ऐसे केंद्रों को विवादित बनाए रखा। अब सारे विवाद एक-एक कर समाप्त हो रहे हैं।

हर्ष वर्धन त्रिपाठी@MediaHarshVT

देश में एक वर्ष के लिए सभी छोटी-बड़ी राजनीतिक रैलियां, बड़े धार्मिक समारोह-समागम और बड़े-बड़े सरकारी उद्घाटन कार्यक्रम रोक दिए जाने चाहिए। तेल की खपत इन सब में सबसे ज्यादा होती है।

अमिताभ अग्निहोत्री @Aamitabh2

आइएनडीआइए की सबसे बड़ी समस्या भाजपा नहीं, बल्कि उसकी अपनी विचार और नेतृत्व की अस्पष्टता है। यह गठबंधन मोदी विरोध की जमीन पर तो खड़ा हुआ, लेकिन साझा राजनीतिक दृष्टि और स्थायी संगठनात्मक ढांचे के बिना। जब तक चुनावी गणित साथ था, तस्वीर मजबूत दिखी। जैसे ही क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं टकराईं, दरारें सतह पर आ गईं।

डा. मीना कुमारी@DrMeenaJangid

जनपथ

'ताऊ' पहुंचे चीन थे खाने चाऊ मीन,
तड़का ताइवान का मजा ले गया छीन।
मजा ले गया छीन झुके ना बिल्कुल चिनफिंग,
रहो मानते आप स्वयं को दुनिया का किंग।
अकड़ चीन में जाय नहीं रह सकी टिकाऊ,
बुद्धू बनकर लौट गए घर अपने 'ताऊ'!

-ओम प्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 120- 4615800, E- mail:delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 301

अर्थ जागरण

एक नजर में

रेयर अर्थ मैग्नेट योजना में आवेदन की तिथि बढ़ाई

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली 7,280 करोड़ रुपये की योजना में वैश्विक आवेदन की अंतिम तिथि को एक माह के लिए बढ़ा दिया। इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 28 मई को समाप्त हो रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 29 जून 2026 कर दिया गया है। सरकार ने देश में छह हजार मीट्रिक टन मैग्नेट मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए इसी वर्ष 20 मार्च को बोलियां आमंत्रित की थीं। (प्रेट्र)

एमसीएल को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने महानंदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोल इंडिया ने शुक्रवार को रेग्युलेटरी फाइलिंग में बताया कि आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) के जरिये एमसीएल की 25 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेची जाएगी। कोल इंडिया एमसीएल की पैरेंट कंपनी है। इस आइपीओ में नए शेयर और प्रमोटर शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 2030 तक कोल इंडिया की सभी आठों सब्सिडियरी को सूचीबद्ध कराने का निर्देश दिया है। (प्रेट्र)

बीते वर्ष 14,026 करोड़ रहा टाटा स्टील का निवेश

नई दिल्ली: टाटा स्टील ने शुक्रवार को बताया कि बीते वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसने 14,026 करोड़ रुपये का निवेश (पूंजीगत खर्च) किया है। पूरे वर्ष के दौरान कंपनी को 10,885.52 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है और इसमें 2024-25 के 3,173.78 करोड़ रुपये के मुकाबले तीन गुना से ज्यादा वृद्धि रही है। इसमें भारत से ज्यादा आय का प्रमुख योगदान रहा है। जनवरी-मार्च 2026 में कंपनी का शुद्ध लाभ दोगुना से ज्यादा बढ़कर 2,965 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी चार रुपये प्रति शेयर का लाभांश देगी। (प्रेट्र)

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निर्यात 13% बढ़ा

भारत को नए बाजार तलाशने का मिला लाभ, 43.56 अरब डालर रहा पिछले माह कुल वस्तु निर्यात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश का निर्यात अप्रैल में 13.78 प्रतिशत बढ़कर पांच महीने के उच्चस्तर पर 43.56 अरब डालर रहा। पिछले दस सालों में अप्रैल में होने वाला यह अब तक का सबसे अधिक निर्यात है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल में युद्ध से प्रभावित पश्चिम एशिया देशों में होने वाले निर्यात में गिरावट रही, लेकिन कई नए बाजार में निर्यात बढ़ने से वस्तुओं का कुल निर्यात बढ़ा। पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 38.2 अरब डालर रहा था।

अप्रैल में वस्तुओं का आयात 72 अरब डालर रहा, जो पिछले साल अप्रैल की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल में खाद्य तेल के आयात में पिछले साल अप्रैल की तुलना में 40 प्रतिशत, सोने में 81 प्रतिशत (कुल 5.62 अरब डालर) तो चांदी के आयात में 157 प्रतिशत (41.1 करोड़ डालर) का इजाफा रहा। सोने और चांदी के आयात को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने इनके आयात शुल्क को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि अप्रैल में निर्यात बढ़ने की दो-तीन वजहें हैं। एक तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं। इससे मूल्य बढ़ा हुआ दिख रहा है। शुक्रवार को एक डालर का मूल्य 96 रुपये के पार चला गया जबकि पिछले साल मध्य अप्रैल में यह डालर के मुकाबले 85.44 रुपये था। वहीं पारंपरिक बाजार के अलावा सिंगापुर, नीदरलैंड, तंजानिया, हांगकांग, मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों में भारी मात्रा में निर्यात बढ़ा है। उन्होंने बताया कि सेवा निर्यात में पहले की तरह वृद्धि जारी है और अप्रैल में यह 13.7 प्रतिशत बढ़ा।

40 प्रतिशत का इजाफा हुआ खाद्य तेल के आयात में

81 प्रतिशत बढ़ा सोने का आयात पिछले महीने

157 प्रतिशत की वृद्धि रही चांदी के आयात में

72 अरब डालर रहा कुल वस्तु आयात अप्रैल में

पश्चिम एशियाई देशों को निर्यात 28 प्रतिशत घटा

अप्रैल में पश्चिम एशियाई देशों को वस्तु निर्यात 28 प्रतिशत घटकर 4.16 अरब डालर रह गया। जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 5.78 अरब डालर था। इस क्षेत्र से आयात भी 31.64 प्रतिशत घटकर 10.47 अरब डालर रह गया, जो एक साल पहले इसी समय 15.32 अरब डालर था। अप्रैल में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सऊदी अरब को भारत का निर्यात 36.39 प्रतिशत घटकर क्रमशः 2.18 अरब डालर और 85.2 करोड़ डालर रह गया।

पिछले महीने विभिन्न देशों को बढ़ा निर्यात (%में)

सिंगापुर	179.18
चीन	27
वियतनाम	53
बांग्लादेश	64
तंजानिया	157
श्रीलंका	214
हांगकांग	90.61
मलेशिया	60
अमेरिका	1.14
यूएई	(-36.39)

"डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य में हो रही गिरावट से भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धा क्षमता प्रभावित नहीं हुई है। इसका एक कारण यह है कि अन्य देशों की करेंसी में भी डालर के मुकाबले गिरावट हो रही है। ब्रिटेन के हाल के इस्पात संरक्षण उपाय से उत्पन्न मुद्दों से निपटने के लिए 'विशिष्ट एवं रचनात्मक समाधान' तलाश रहे हैं ताकि प्रस्तावित व्यापार समझौता को जल्द लागू किया जा सके। **-राजेश अग्रवाल,** वाणिज्य सचिव

मुनाफावसूली से 21,600 रुपये घटा चांदी का मूल्य

नई दिल्ली, प्रेट्र: डालर में मजबूती और निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते शुक्रवार को दिल्ली में चांदी और सोने के मूल्य में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार, चांदी के मूल्य में 21,600 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। अब दिल्ली में इसका मूल्य घटकर 2.75 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है।

इसी प्रकार, सोने के मूल्य में 3,200 रुपये की गिरावट दर्ज की गई और अब इसका मूल्य 1,62,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कहा कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों और अमेरिका-ईरान तनाव के कारण सप्लाई चेन में आ रही लगातार रुकावटों ने सख्त मौद्रिक नीति लागू करने की जरूरत को और मजबूत कर दिया है। इस कारण शुक्रवार को कीमती धातुओं पर भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला।

- 2.75 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हुई दिल्ली में सफेद धातु की कीमत
- सोना 3,200 रुपये गिरकर 1,62,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया

इंट्रा-डे में रुपया 96.14 के रिकार्ड स्तर तक गिरा

मुंबई, प्रेट्र: कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और महंगाई संबंधी चिंताओं के चलते शुक्रवार को डालर के मुकाबले रुपया इंट्रा-डे में 96.14 के स्तर तक गिर गया। हालांकि, बाद में यह कुछ संभला और गुरुवार के बंद भाव से 22 पैसे टूटकर 95.86 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। रुपया इस वर्ष अब तक छह प्रतिशत से अधिक टूट चुका है और पिछले छह कारोबारी सत्रों में यह दो प्रतिशत कमजोर हुआ है।

6.29 अरब डालर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार

मुंबई, प्रेट्र: आरबीआइ ने शुक्रवार को कहा कि आठ मई को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.295 अरब डालर बढ़कर 696.988 अरब डालर हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार के यह आंकड़े प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाओ की अपील से पहले के हैं। इससे पिछले सप्ताह में कुल रिजर्व 7.794 अरब डालर घटकर 690.693 अरब डालर के स्तर पर आ गया था। इस साल 27 फरवरी को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 728.494 अरब डालर के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया था।

आरबीआइ के आंकड़ों के अनुसार, बीते सप्ताह विदेशी मुद्रा आस्तियां 56.2 करोड़ डालर बढ़कर 552.387 अरब डालर हो गईं। विदेशी मुद्रा भंडार में इनकी सबसे अधिक हिस्सेदारी होती है। इसी तरह, स्वर्ण भंडार का मूल्य 5.637 अरब डालर बढ़कर 120.853 अरब डालर हो गया।

कई साल के निचले स्तर पर पहुंची बैंकों की बट्टा खाता राशि

मुंबई, प्रेट्र: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तरफ से बट्टेखाते में डाले गए कर्ज की राशि वित्त वर्ष 2025-26 में घटकर कई वर्षों के निचले स्तर पर आ गई। कर्ज फंसने के मामलों में कमी और बकाया कर्ज की वसूली में सुधार इसकी प्रमुख वजह रहे।

इन बैंकों के वित्तीय नतीजों के विश्लेषण से पता चलता है कि बैंक आफ बड़ौदा, यूनियन बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक सहित अधिकांश बैंकों ने पिछले आठ वर्षों में सबसे कम कर्जों को बट्टेखाते में डाला। बैंक आफ बड़ौदा ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6,330 करोड़ रुपये के कर्ज बट्टेखाते में डाले, जो 2017-18 के बाद सबसे कम है। इसी तरह, बैंक आफ इंडिया ने 5,735 करोड़ रुपये बट्टेखाते में डाले, जो 2015-16 के बाद न्यूनतम स्तर है। इंडियन बैंक का कर्ज बट्टा खाता 2018-19 के बाद सबसे कम 6,695 करोड़ रुपये रहा। इसी तरह, इंडियन ओवरसीज बैंक का 1,189 करोड़ रुपये रहा, जो कई वर्षों के निचले स्तर पर है। सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने पिछले वित्त वर्ष में 1,718 करोड़ रुपये के कर्ज बट्टेखाते में डाले, जो 2021-22 के बाद सबसे कम है। आमतौर पर बैंक उन कर्जों को बट्टेखाते में डालते हैं, जिनकी वसूली की संभावना कम होती है और जिनके लिए 100 प्रतिशत वित्तीय प्रविधान करना पड़ता है।

- कर्ज फंसने के मामलों में कमी और बकाया कर्ज की वसूली में सुधार रहे इसकी प्रमुख वजह
- बैंक आफ बड़ौदा ने 6,330 करोड़ बट्टेखाते में डाले, यह 2017-18 के बाद सबसे कम

अप्रैल में बेरोजगारी दर छह महीने के उच्चस्तर 5.2 प्रतिशत पर रही

नई दिल्ली, प्रेट्र: अप्रैल में भारत की बेरोजगारी दर छह महीने के उच्चस्तर 5.2% पर पहुंच गई। जबकि, मार्च 2026 और अप्रैल 2025 में यह 5.1 प्रतिशत थी। सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी अप्रैल, 2026 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वे अनुसार शहरी बेरोजगारी दर मार्च, 2026 के 6.8 प्रतिशत से थोड़ा कम होकर अप्रैल, 2026 में 6.6 प्रतिशत हो गई, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर इसी समय के दौरान 4.3 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गई।

अप्रैल में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के पुरुषों की बेरोजगार दर 5.1 प्रतिशत रही, जबकि मार्च, 2026 में यह पांच प्रतिशत थी। इसी तरह अप्रैल में ग्रामीण पुरुषों की बेरोजगारी दर 4.7 प्रतिशत रही, जो इसी वर्ष मार्च 4.4 प्रतिशत थी। वार्षिक आधार पर पुरुषों की बेरोजगारी दर 0.1 प्रतिशत घटी है।

बीते वित्त वर्ष के लिए आइटीआर जमा करने की प्रक्रिया शुरू, 31 जुलाई तक है मौका

नई दिल्ली, आइएएनएस: यदि बीते वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) में आप पर कोई कर देनदारी है या फिर आपको रिफंड लेना है तो इसके लिए आप आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने सोमवार को बताया कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर आइटीआर-1 और आइटीआर-4 फार्म के एक्सल प्रारूप जारी कर दिए गए हैं। करदाता दोनों फार्म के एक्सल प्रारूप या आनलाइन फाइलिंग विकल्प का चयन करते हुए आइटीआर दाखिल कर सकते हैं।

आयकर विभाग की इस घोषणा के साथ आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आइटीआर फाइल करने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। सामान्य तौर पर जिन करदाताओं का आडिट नहीं होता है, उन्हें 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल करना होता है। इस समय आय के प्रकार और करदाता की श्रेणी के आधार पर कुल सात आइटीआर फार्म उपलब्ध हैं। आइटीआर-1 (सहज) उन सभी करदाताओं के लिए है जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है। आइटीआर-4 (सुगम) उन व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और फर्मों (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को छोड़कर) के लिए है जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है।

आयकर विभाग ने आइटीआर-1 और आइटीआर-4 के एक्सल प्रारूप जारी किए, आनलाइन-आफलाइन भरें आयकर रिटर्न

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) पहले ही बदलाव के अनुसार सभी आइटीआर फार्म जारी कर चुका है। इन बदलावों में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, शेयर बायबैक से होने वाले नुकसान और कुछ विशिष्ट ट्रेडिंग लेन-देन से संबंधित अतिरिक्त रिपोर्टिंग आवश्यकताएं शामिल हैं।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

राष्ट्रीय जागरण

छह दिन पहले केरलम पहुंचेगा मानसून

नई दिल्ली, प्रेट्र : इस साल केरलम में मानसून छह दिन पहले आ जाएगा और इसके साथ ही देश में वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाएगी। मौसम विभाग ने शुक्रवार को अपने पूर्वानुमान में कहा कि इस साल केरलम में दक्षिण-पश्चिम मानसून का आगमन 26 मई को होने की संभावना है। आमतौर पर मानसून केरलम में एक जून को दस्तक देता है और उत्तर की ओर बढ़ते हुए देश के अन्य हिस्सों को प्रभावित करता है। जैसे-जैसे मानसून उत्तर की ओर बढ़ता है, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने लगती है। पिछले वर्ष केरलम में मानसून का आगमन 24 मई को हुआ था।

मौसम विभाग ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून केरलम में 26 मई को आने की संभावना है, जिसमें चार दिन की त्रुटि हो सकती है (यह चार दिन पहले या बाद में आ सकता है)। अगले 24 घंटों के दौरान मानसून के दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान-निकोबार द्वीप में आगे बढ़ सकता है। **इस साल होगी सामान्य से कम वर्षा:** जून से सितंबर तक चार महीने के मानसूनी सीजन में वार्षिक औसत की 70% बारिश होती है। यह कृषि और फसलों, समग्र अर्थव्यवस्था और जलाशयों एवं जलभंडारों को रिचार्ज करने के लिए महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मानसूनी सीजन में भारत में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है।

पश्चिमी विक्षोभ अब और ज्यादा विनाशकारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: उत्तर भारत का मौसम तेजी से बदल रहा है। ताजा अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पश्चिमी विक्षोभ अब ज्यादा ताकतवर, ज्यादा लंबे समय तक सक्रिय और अधिक खतरनाक होते जा रहे हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड जैसी विनाशकारी बाढ़, हिमालयी इलाकों में भूस्खलन एवं उत्तर भारत में अचानक होने वाली रिकार्ड बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस बार मई में भी ज्यादा बारिश और कम गर्मी को इसी बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी आफ रीडिंग के मौसम विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययन में 70 वर्षों के मौसम संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि हिंदूकुश और हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभों की संख्या बढ़ी है। खासतौर पर मई-जून में ज्यादा सक्रियता हो गई है। दो दशकों में मई-जून में पश्चिमी विक्षोभों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है।

मौसम विभाग के महानिदेशक डा. मृत्युंजय महापात्रा का कहना है कि मई में पश्चिमी विक्षोभों की संख्या जरूर बढ़ रही है, लेकिन इसे सीधे जलवायु परिवर्तन से जोड़ने से पहले और शोध की जरूरत है।

समृद्ध हिमालयी जैव विविधता के बीच करें बाबा केदार के पांच स्वरूपों के दर्शन

सार्वजनिक परिवाहन मार्ग से जुड़े हैं ऊखीमठ, मक्कूमठ और गोपेश्वर स्थित शीत केदार समूह के ये प्रसिद्ध धाम

14.07 लाख यात्री कर चुके हैं अब तक चारों धाम में दर्शन इस वर्ष

5.77 लाख ने किए सिर्फ केदारनाथ धाम में दर्शन, चारों धाम में यह सर्वाधिक संख्या

10 नवंबर अन्नकूट पर्व पर गंगोत्री और 11 नवंबर को भैयादूज पर्व पर बंद होंगे यमुनोत्री व केदारनाथ धाम के कपाट

यात्रा

दिनेश कुकरेती • जागरण

देहरादून: चारधाम यात्रा के दौरान आप बाबा केदार के सभी पांच स्वरूपों (पंच केदार) के दर्शन भी कर सकते हैं और वह भी शीत केदार समूह के मंदिरों में। इन धामों तक पहुंचने की राह भी बेहद आसान है। न तो आपको कई-कई किमी का दूरी पैदल नापनी पड़ेगी और न ही लंबी-लंबी लाइनों में लगने की ही जरूरत पड़ी है। दरअसल, सभी शीत केदार मंदिरों (ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, मर्कटेश्वर मंदिर मक्कूमठ और गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर) तक ऋषिकेश से निजी व सार्वजनिक वाहन सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा पंचम केदार कल्पेश्वर धाम पहुंचने के लिए भी महज एक किमी पैदल चलना पड़ता है। इस यात्रा के दौरान आप प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चोपता, खूबसूरत उर्गम घाटी और समृद्ध हिमालयी जैव विविधता के भी दर्शन कर सकते हैं। ये सभी मिलकर आपकी यात्रा को सफल बनाएंगे।

मनमोहक उर्गमघाटी।

गोपीनाथ मंदिर।

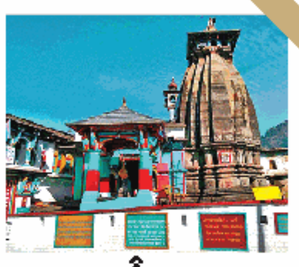

ओंकारेश्वर मंदिर।

पंचम केदार कल्पेश्वर धाम।

ऐसा दिखता है चोपता का नजारा।

मर्कटेश्वर धाम, जोकि तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ का शीतकाल प्रवास है।

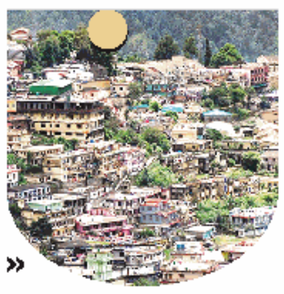

बाबा गोपीनाथ की नगरी गोपेश्वर का मनमोहक नजारा • सभी फोटो जागरण आर्काइव

ओंकारेश्वर धाम : यहां विराजते हैं पंचकेदार

रुद्रप्रयाग जिले में ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर बाबा केदार ही नहीं, द्वितीय केदार बाबा मध्यमेश्वर का भी शीतकालीन गद्दीस्थल है। यहां पांचों केदार पिंडी रूप में विराजमान हैं, इसलिए मंदिर की ख्याति पंचगद्दी स्थल के रूप में भी है। यहां की सुरम्य वादियां, ठीक सामने नजर आने वाली चौखंभा की हिमाच्छादित चोटियां और बांज-बुरांश के घने जंगल हर किसी का मन मोह लेते हैं। नगर के मध्य में ओंकारेश्वर मंदिर स्थापित है, जिसका निर्माण अतिप्राचीन धारतुर परकोटा शैली में हुआ है। मान्यता है कि बाणासुर की बेटी उषा व भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध की शादी इसी स्थान पर हुई थी।

मर्कटेश्वर धाम : यहां मिलती है शांति

रुद्रप्रयाग जिले में मक्कूमठ गांव स्थित मर्कटेश्वर मंदिर तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ का शीतकाल प्रवास है। यह गांव चारों ओर से देवदार, बांज, बुरांश व धुनेर के घने जंगल से घिरा है। मर्कटेश्वर मंदिर भी कत्यूरी शैली में बना है। ऊखीमठ से मक्कूमठ पहुंचने के लिए 32 किमी और भीरी से 16 किमी की दूरी तय करनी पड़ती है। मक्कूमठ, उन लोगों के लिए अद्भुत जगह है, जो शहर के शोर से दूर किसी शांतिपूर्ण जगह की तलाश में हैं।

कल्पेश्वर धाम : दुर्वासा ने किया था तप

चमोली जिले की उर्गम घाटी के देवग्राम में स्थित पंचम केदार कल्पेश्वर धाम पहुंचने के लिए अब एक किमी से भी कम का सफर पैदल तय करना पड़ता है। कल्पेश्वर धाम को कल्पनाथ नाम से भी जाना जाता है। यहां सालभर भगवान शिव के जटा रूप में दर्शन होते हैं। कहते हैं कि इस स्थल पर दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे घोर तप किया था। मंदिर के गर्भगृह का रास्ता एक गुफा से होकर जाता है। धाम के कपाट बारहों महीने खुले रहते हैं।

गोपेश्वर के गोपीनाथ : दूसरा सबसे ऊंचा मंदिर

चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में 71 फीट ऊंचा गोपीनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर के बाद उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा मंदिर है। चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ के शीतकालीन प्रवास स्थल इस मंदिर में भी भोलेनाथ का अभिषेक सिर्फ बिल्व पत्र से होता है। चारधाम यात्रा मार्ग में पड़ने के कारण यहां पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत नहीं पड़ती। नागर शैली में बने इस मंदिर का इतिहास नौवीं से 11वीं सदी के मध्य कत्यूरी शासन काल का माना जाता है। प्रांगण में अष्टधातु निर्मित पांच मीटर लंबा त्रिशूल स्थापित है।

सार्वजनिक वाहन, होटल व होम स्टे की सुविधा उपलब्ध

इस यात्रा के लिए आप ऋषिकेश पहुंचें। निजी व सार्वजनिक वाहन सुविधा उपलब्ध है। पूरे यात्रा मार्ग पर होटल व होम स्टे की सुविधा है। ज्यादातर होम स्टे में पहाड़ी किचन उपलब्ध हैं, जहां आप पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं।

अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है उर्गम घाटी

हरे-भरे बुग्याल और घने जंगलों से घिरा चोपता नंदा देवी व त्रिशूल हिमालय की चोटियों के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। उर्गम घाटी की सुंदरता भी सम्मोहित करती है। आध्यात्मिक शांति की तलाश हो या प्रकृति की सुंदरता, उर्गम घाटी अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

आज का भविष्यफल: 16 मई, 2026 शनिवार — पं. के.ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति
ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या का राशिफल।
आज का राहुकाल : प्रातः 09 बजे से 10 बजकर 30 मिनट तक।
आज का दिशाशूल : पूर्व
आज का पर्व एवं त्योहार : वरगदाही, वट सावित्री व्रत, अमावस्या, शनि जयंती।

कल 17 मई 2026 का पंचांग

कल का दिशाशूल : पश्चिम
कल का पर्व एवं त्योहार : पुरुषोत्तम/अधिक मास प्रारंभ। विक्रम संवत 2083 शके 1948 उत्तरायण, उत्तरगोल, वसंत ऋतु अधिक ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 21 घंटे 42 मिनट तक तत्पश्चात द्वितीया, कृतिका नक्षत्र 14 घंटे 33 मिनट तक तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र, शोभन योग 06 घंटे 16 मिनट तक तत्पश्चात अतिगंड योग, वृष में चंद्रमा।

मेष: व्यावसायिक योजना को बल मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा।

वृष: पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। बहुप्रतीक्षित कार्य संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

मिथुन: शाही खर्च से बचना होगा। रुपये-पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। धन हानि की आशंका है।

कर्क: कालसर्प योग बनने के कारण मन अशांत रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।

सिंह: आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। सत्ता का सहयोग रहेगा।

कन्या: पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। सुखद समाचार मिलेगा, पर वाहन चलाने में सावधानी रखें।

तुला: चल या अचल संपत्ति के लिए ऋण लेने का प्रयास सार्थक होगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

वृश्चिक: धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि। ससुराल का सहयोग मिलेगा। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा।

धनु: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व उत्साहवर्धक होगी।

मकर: संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आर्थिक प्रयास फलीभूत होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

कुंभ: किया गया कार्य संपन्न होगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यश, कीर्ति में वृद्धि होगी।

मीन: पुरुषार्थ सार्थक होगा। भाई-बहन का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में निकटता आएगी।

वर्ग पहेली-3336

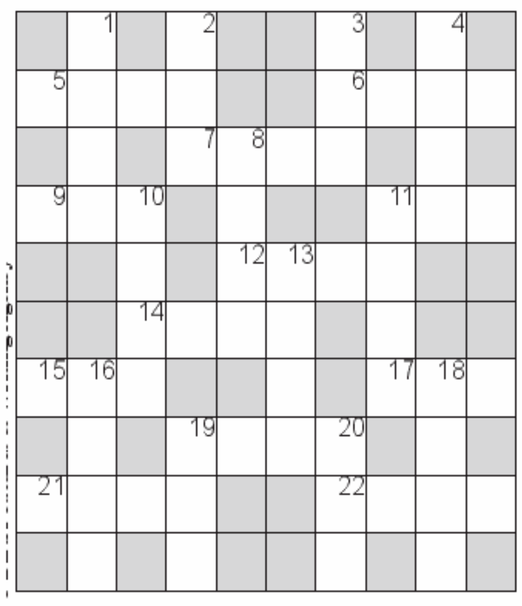

© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं:
5. जमीन के नीचे बनी कोठरी (4)। 6. नुकसान पहुंचाने वाला (4)।
7. समाप्त या पूरा करना (4)।
9. दुखी, संतप्त, खिन्न (3)।
11. बिना नाम का (3)।
12. वहन करने योग्य (4)।
14. हाथ से बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र (4)।
15. तंग या परेशान करना (3)।
17. दिखाना, आकृष्ट कराना (3)।
19. कतरन से बने छोटे-बड़े टुकड़े (4)।
21. संपूर्ण रूप से (4)।
22. जयघोष (4)।

ऊपर से नीचे:
1. जुदा, अलग (4)।
2. रसीला, रसयुक्त (3)।
3. दुनिया, आलम, संसार (3)।
4. बोलने में अटकना (4)।
8. मनुष्यता (4)।
10. खिसकना, रेंगना (4)।
11. असज्जित, अनियंत्रित (4)।
13. बलराम को यह भी कहा जाता है (4)।
16. सितार जैसा एक बाजा (4)।
18. कुछ भी पता न चलना, ... खबर न होना (2,2)। 19. पंक्तिबद्ध (3)।
20. दृष्टि, निगाह (3)।

कल का हल

ध	न	वा	न				स	ब	ब
व			क	सा	व	ट			च
ल		हा	ल	त			ह		प
	अ			वा			मे	नें	न
	ला			ह	मं	क	ला	म	
	पं	हं	चा	न	ना			स्का	
बं	ना	म			क			र	
चा		ल			रं	जं	नी		मुं
खु			गु	म	ना	म			ना
चौं	ह	त				नौं	का	बं	दी

सुडोकू-3336

	2			1				6
				4			2	
9		7	3		2		5	
6			5			8		2
	9			3	1		6	
8		5		7				3
	4		6		9	5		
	3	9		5				8
5					3		7	

कल का हल

7	5	2	4	1	6	9	3	8
4	3	6	9	8	7	5	1	2
9	8	1	2	3	5	4	6	7
3	1	4	8	6	2	7	5	9
5	6	9	7	4	3	8	2	1
8	2	7	5	9	1	6	4	3
6	4	8	1	2	9	3	7	5
1	9	5	3	7	4	2	8	6
2	7	3	6	5	8	1	9	4

महान सौंदर्य, अत्यधिक ताकत और बहुत धन का वास्तव में कुछ खास उपयोग नहीं है। एक सच्चा हृदय सबसे ऊपर है।

– बेंजामिन फ्रैंकलिन

महंगाई का मोर्चा

पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी कि तेल और गैस की कमी की वजह से आने वाले दिनों में जरूरी वस्तुओं की महंगाई बढ़नी तय है। खासतौर पर रसोई गैस की किल्लत की वजह से आम लोगों के सामने कैसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं, यह सब जानते हैं। इस दौरान देश में ईंधन, बिजली और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की वजह से थोक महंगाई दर अप्रैल में 8.3 फीसद दर्ज की गई, जो मार्च में 3.88 फीसद थी। साफ है कि घरेलू बाजार पर अब अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर पड़ना शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ समय पहले वाणिज्यिक गैस सिलेंडर और विमानन टर्बाइन ईंधन के दाम में खासी बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन उसके असर का दायरा कुछ हद तक सीमित था। अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का मोर्चा जिस तरह खुला है, उससे साफ है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव के साए में तेल की आपूर्ति लंबे समय तक बाधित रही, तो इसका असर जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित करेगा। गौरतलब है कि तेल कंपनियों की ओर से शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन-तीन रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं सीएनजी की कीमत में भी दो रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया।

जाहिर है, ईरान पर इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के बाद वैश्विक स्तर पर ऊर्जा कीमतों में जिस तरह की तेजी आई है, अब तेल कंपनियां आम उपभोक्ताओं पर भी उसका बोझ सीधे डालना शुरू कर चुकी हैं। यों जब ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को बाधित किया था और दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के तेलशोधन केंद्रों और ठिकानों पर मिसाइल दागे गए, तभी से यह साफ था कि इसका असर दुनिया भर में होने वाली तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ेगा और नतीजतन सभी क्षेत्रों में महंगाई बढ़ेगी। खासतौर पर उन देशों में ज्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है, जहां तेल और गैस की आपूर्ति को सहज बनाए रखने के विकल्प सीमित हैं। दरअसल, होर्मुज जलमार्ग से दुनिया भर में लगभग बीस से पच्चीस फीसद तेल और गैस की आपूर्ति होती है और इसी वजह से इसके बाधित होने के प्रभाव का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। स्वाभाविक रूप से भारत में भी तेल और गैस की कमी पैदा हुई।

हालांकि अमेरिका की ओर से लगाई गई शर्तों के बीच भारत ने रास्ता निकालने की कोशिश की थी, लेकिन अब युद्ध से उपजी जटिलता जैसे-जैसे लंबी खिंचती जा रही है, वैसे-वैसे विकल्प भी सिमटते जा रहे हैं। यह छिपा नहीं है कि डीजल के दाम में बढ़ोतरी के साथ ही माल ढुलाई की कीमत बढ़ती है और उसकी वजह से सभी जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई में बढ़ोतरी होती है। यानी फिलहाल डीजल के दाम तीन रुपए बढ़े हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका के रुख के असर में वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट के जो हालात बने हुए हैं, उसमें यह कहना मुश्किल है कि तेल के दाम में वृद्धि यहीं रुक जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर खाने-पीने से लेकर जरूरत की हर चीज की कीमतें बेलगाम हुईं, तो यह एक स्वाभाविक परिणति होगी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की वजह से उपजे ऊर्जा संकट में जरूरत इस बात की है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस की उपलब्धता वाले देशों के साथ कूटनीतिक संवाद स्थापित करे और देश में गहराती मुश्किल को कम करने के लिए पहलकदमी करे।

वाजिब सवाल

निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं संवैधानिक संस्था है, जो चुनावी प्रक्रिया का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यही वह संस्था है, जो लोकतंत्र के मूल तत्त्व को जिंदा बनाए रख सकती है। मगर पिछले कुछ वर्षों से निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, उससे उसकी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ गई है। दरअसल, कोई भी प्राधिकरण तभी स्वायत्त और निष्पक्ष हो सकता है, जब उस पर कोई बाहरी दबाव न हो और उसके पदाधिकारियों का चयन भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निष्पक्ष तरीके से किया जाए। निर्वाचन आयोग में नियुक्तियों को लेकर कई स्तर पर आरोप लगते रहे हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को इस मामले में कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं और यह तभी सुनिश्चित किया जा सकता है, जब निर्वाचन आयोग स्वतंत्र हो और इसके कार्यों में स्वायत्तता प्रतीत भी हो।

गौरतलब है कि वर्ष 2024 में लागू किया गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 में यह प्रावधान है कि निर्वाचन आयोग में आयुक्तों की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी। इस समिति में पहले प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल थे, मगर नए कानून में प्रधान न्यायाधीश की जगह केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है। शीर्ष अदालत में इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। सवाल है कि तीन सदस्यीय चयन समिति में सरकार के दो प्रतिनिधि शामिल होने से क्या नियुक्ति प्रक्रिया में पूरी निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है, ऐसे में अगर निर्वाचन आयोग की संरचना पर ही सवाल उठते रहे, तो जनता के भरोसे का क्या होगा। इसी पहलू पर गौर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि विश्वास का स्तर इतना होना चाहिए कि ऐसा प्रतीत हो कि चयन समिति में कोई तीसरा निष्पक्ष व्यक्ति भी शामिल है। शीर्ष अदालत की इस टिप्पणी से निर्वाचन आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया को संतुलित किए जाने की उम्मीद जगी है।

पर्यावरण की फिक्र के समांतर दायित्व

हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां प्रदूषण और वैश्विक ताप के मूल में पिछले कई दशकों से अपनाई गई व्यवस्था है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण का सारा बोझ आम लोगों के कंधों पर डाल दिया जाता है।

कुशाग्र राजेंद्र

आज हम ऐसे दौर में हैं जहां पर्यावरणीय संकटों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। शहरों की हवा जहरीली हो चुकी है। नदियां कचरे और रासायनिक गंदगी का बोझ ढो रही हैं। कचरे के पहाड़ हमारे ही मोहल्लों की सरहद पर उग आए हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस दबाव की आहट साफ सुनाई दे रही है। यह सब दूर के भविष्य की चेतावनी नहीं, यह अब हमारा वर्तमान है। गौर करें तो पाएंगे कि प्रकृति और संसाधन के साथ जो हमारा संबंध था, वह पूरी तरह बदल गया है। हमारी आदतें बदल गई हैं। प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते बदलने के कई कारण हैं। विकास का वैश्विक माडल, आर्थिक नीतियां, बाजारवाद, वर्तमान शहर नियोजन और डिजिटल एल्गोरिद्म एक साथ मिल कर हमारी आदतें बदल रहे हैं।

मगर व्यवस्था में बदलाव को नजरअंदाज कर अच्छी आदतों के साथ पर्यावरण संरक्षण का सारा बोझ आम लोगों के कंधों पर डालने की परिपाटी है। हर व्यक्ति अपनी कुछ आदतें बदलें, तभी पर्यावरणीय संकट से निजात मिल सकती है। बत्ती बंद कीजिए, पानी बचाइए, कचरा अलग कीजिए, कपड़े सोच-समझ कर खरीदिए, कार की जगह बस और मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए इत्यादि। जैसे लगता है कि मौजूदा संकट केवल आम लोगों की आदतों का ही परिणाम हो।

हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां ज्यादातर बड़े संकट जैसे प्रदूषण, वैश्विक ताप इत्यादि के मूल में पिछले कई दशकों से अपनाई गई व्यवस्था है। मगर सरलीकरण का आलम यह है कि अंगुली सबसे पहले आम लोगों की आदतों पर उठती है। जलवायु परिवर्तन से लेकर पानी, ऊर्जा और कचरे के सवाल तक, सार्वजनिक विमर्श में अक्सर यह संदेश गूंजता है कि अगर आम लोग थोड़ी 'अच्छी आदतें' अपना लें, तो हालात बदल सकते हैं। नल बंद रखिए, प्लास्टिक थैला छोड़िए, साइकिल चलाइए, ये सब जरूरी बातें हैं। मगर जब पूरा ध्यान यहीं केंद्रित हो जाता है, तो असली वजह धुंधली होने लगती है। व्यवस्थाजनित संकटों का समाधान केवल व्यक्तिगत संयम में खोजना एक तरह से जिम्मेदारी के बड़े हिस्से को अदृश्य कर देना भी है।

पानी का सवाल उठाइए, तो चर्चा अक्सर हमारे स्नानागार और रसोई से शुरू होती है। सलाह दी जाती है कि ब्रश करते समय नल न बहने दें, बाल्टी से नहाएं, पाइप से गाड़ी न धोएं। इन सबका महत्त्व कम नहीं है, लेकिन वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर जल-उपयोग का सबसे बड़ा हिस्सा खेती, उद्योग और शहरी आपूर्ति व्यवस्था में खपता है, जबकि घरेलू उपयोग उसका छोटा अंश है। खेतों तक जाने वाली नहरों में यदि जगह-जगह रिसाव हों, शहरों की पाइपलाइनें वर्षों से मरम्मत के बिना पानी बहाती रहें और उद्योग अपना गंदा पानी बिना शोधन के नदियों में छोड़ते रहें, तो अकेले घरों का अनुशासन कुल तस्वीर को कितना ही बदल पाएगा। फिर भी जागरूकता अभियानों में दिखाई देता है- टपकता नल और ब्रश करता बच्चा, न कि रिसाव वाली नहर या अंधेरे में चुपचाप नदी की ओर बहता फैक्टरी का नाला।

ऊर्जा मामले में भी यही कहानी दोहराई जाती है। सवाल है कि ऊर्जा-उपभोग और उत्सर्जन की सबसे बड़ी मांग कहां से आ रही है। भारी उद्योग, सीमेंट, इस्पात

और रसायन उद्योग, डेटा सेंटर, विमानन तथा मालवाहक जहाज, ये सारे क्षेत्र मिल कर ऊर्जा की बहुत बड़ी हिस्सेदारी निगलते हैं, जबकि घरेलू स्तर की बचत का दायरा संरचनात्मक सहयोग के बिना सीमित रह जाता है। उपभोग के मोर्चे पर हम सब एक खालिस उपभोक्ता बनते जा रहे हैं। बाजार व्यवस्था की भूमिका

> नए शहरों के नियोजन में भी विरोधाभास दिखाई देता है। सार्वजनिक अपील यह होती है कि लोग निजी वाहन कम चलाएं, बस-मेट्रो का उपयोग करें। आसपास जाने के लिए साइकिल चलाएं और पैदल चलें। मगर जैसे-जैसे शहरों का विस्तार हुआ है, नई आबादी आमतौर पर उन इलाकों में बसाई गई हैं जहां न भरोसेमंद बस सेवा है, न मेट्रो, न साइकिल पथ। ऐसी स्थिति में निजी वाहन विकल्प नहीं, मजबूरी बन जाता है। आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग इस मजबूरी को कार और दोपहिया से संभाल लेता है। जो नहीं संभाल पाते वे रोजमर्रा की यात्रा में समय और सुरक्षा दोनों की ऊंची कीमत चुकाते हैं।

सबसे महत्त्वपूर्ण है। बाजार में उपलब्ध अधिकतर उत्पाद इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि उनकी उम्र सीमित रहे। मरम्मत कठिन या महंगी हो और उपभोक्ता कुछ ही वर्षों में नया सामान लेने को प्रेरित हो जाए। मोबाइल फोन और टीवी से लेकर घरेलू उपकरणों तक यह प्रवृत्ति अब औद्योगिक माडल का हिस्सा बन चुकी है। उपभोक्ताओं से कहा जाता है कि कम खरीदिए, सोच-समझ कर खरीदिए, लेकिन जब दुकान में टिकाऊ और मरम्मत-योग्य विकल्प लगभग नदारद हों तथा सस्ते वही सामान हों जो जल्दी टूटने के लिए बनाए गए हों, तो जिम्मेदार उपभोग की नैतिकता भी अपने आप में अधूरी हो जाती है।

'इस्तेमाल करो और फेंको' की व्यवस्था ने हमारी प्रकृति सम्मत आदतों की जमीन ही बदल दी। बोतलबंद पानी से लेकर सुविधाजनक पैकेजिंग और तेज वितरण ने जीवन को निस्संदेह आसान बनाया, पर बदले में प्लास्टिक, थर्मोकोल और ई-कचरे के पहाड़ खड़े कर दिए। आनलाइन बाजारों ने एक कदम और आगे बढ़ कर प्रचार-रणनीतियों से हमारी इच्छाओं का नक्शा तक अपने हाथों में ले लिया है। 'केवल आज की विशेष छूट' और 'बस दो पीस बचे हैं' जैसी तरकीबें यह सुनिश्चित करती हैं कि जरूरत और चाहत के बीच की रेखा लगातार धुंधली होती जाए।

नए शहरों के नियोजन में भी इसी तरह का विरोधाभास दिखाई देता है। सार्वजनिक अपील यह होती है कि लोग निजी वाहन कम चलाएं, बस और मेट्रो का उपयोग करें। आसपास जाने के लिए साइकिल चलाएं और पैदल चलें। मगर जैसे-जैसे शहरों का विस्तार हुआ है, नई आबादी ज्यादातर उन इलाकों में बसाई गई हैं जहां न भरोसेमंद बस सेवा है, न मेट्रो और न साइकिल पथ। ऐसी स्थिति में निजी वाहन विकल्प नहीं, मजबूरी बन जाता है। आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग इस मजबूरी को कार और दोपहिया से संभाल लेता है। जो नहीं संभाल पाते वे रोजमर्रा की यात्रा में समय और सुरक्षा दोनों की ऊंची कीमत चुकाते हैं। बाद में यही लोग भीड़ और प्रदूषण बढ़ाने वाले नागरिकों की श्रेणी में रख दिए जाते हैं, जबकि शहर की मौलिक योजना और परिवहन नीति पर सवाल अपेक्षाकृत कम ही उठते हैं।

डिजिटल दौर में 'फुटप्रिंट' की भाषा, चाहे वह कार्बन की हो या डेटा की, तेजी से लोकप्रिय हुई है। ऐप बताने लगते हैं कि आपकी हर उड़ान, हर भोजन, हर खरीदारी से कितनी अतिरिक्त मात्रा में उत्सर्जन जुड़ रहा है। यह जानकारी उपयोगी है, क्योंकि वह हमारी रोजमर्रा की आदतों को देखने की एक नई दृष्टि देती है, लेकिन जब पूरा नैतिक दायरा केवल व्यक्ति तक सिमट जाता है, तो उत्पादन प्रणालियों, ऊर्जा स्रोतों, व्यापार नियमों और नियामक ढांचों की भूमिका छिप जाती है। सामने दिखता रहता है- केवल गैर-जिम्मेदार उपभोक्ता।

यह कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि व्यक्ति की जिम्मेदारी शून्य है। हर किसी के पास कुछ न कुछ विकल्प होते हैं और हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। निजी जीवन में संयम, संसाधनों का सम्मान, पुनः उपयोग, मरम्मत और साझा उपयोग जैसी आदतें न केवल प्रतीकात्मक हैं, बल्कि व्यावहारिक भी हैं। संकट मौजूदा आर्थिक व्यवस्था और विकास के प्रारूप के हैं, तो समाधान भी व्यवस्था के स्तर पर ही निकलेंगे, हालांकि उनकी शुरुआत व्यक्ति से होकर ही गुजरती है। जरूरत उस संतुलित दृष्टि की है जिसमें हम न तो सारी उम्मीद 'ऊपर की शक्तियों' पर छोड़ दें, न ही पूरा नैतिक बोझ केवल आम नागरिकों पर डाल दें। जब व्यक्तिगत नैतिकता और व्यवस्थागत बदलाव एक-दूसरे के पूरक की तरह देखे जाएं, तभी यह उम्मीद की जा सकती है कि हमारी सामूहिक शक्ति सचमुच उस दिशा में काम करेगी जहां पृथ्वी, समाज और भविष्य, तीनों के हित एक साथ बचाए जा सकें।

दुनिया मेरे आगे

कृतज्ञता का उजाला

संध्या राजपुरोहित

जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि अनुभवों का एक गहरा सरोवर है, जिसमें सुख की चमकती लहरें भी हैं और दुख की अथाह गहराइयां भी। हम इन गहराइयों में उतरते हैं, कभी टूटते हैं, तो कभी संभलते हैं। प्रश्न यह है कि क्या हर क्षति, हर वियोग, हर असफलता केवल शोक या दुख का कारण है? या उसके भीतर कोई ऐसी रोशनी भी छिपी है, जो हमें जीवन को नए अर्थों में देखने का साहस देती है? 'शोक/दुख नहीं, शुक्रिया करें' यह विचार केवल शब्दों का संयोजन नहीं, बल्कि जीवन को समझने की एक परिपक्व, संतुलित और मानवीय दृष्टि है। जितनी बार भी टूटना होता है, वह सबक होता है, तो संभलना दरअसल जिंदगी के नए अध्यायों को सीखना। तो इसके प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव मानवीय संवेदनाओं के लिहाज से एक सहज प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मगर भावुकता में हम कई बार इन पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं और इस तरह एक सुंदर संवेदना के जरूरी पक्ष के अहसास से दूर रह जाते हैं।

हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में शोक की अपनी गरिमा और गहराई है। यह हमारे प्रेम, लगाव और संबंधों की सच्चाई को दर्शाता है। जब कोई अपना बिछड़ता है, तो आंसू आना स्वाभाविक हैं। जब कोई सपना अधूरा रह जाता है, तो पीड़ा भी स्वाभाविक है। मगर समस्या तब जन्म लेती है, जब यही दुख की स्थिति हमारे भीतर स्थायी निवास बना लेती है, जबकि वह हमें वर्तमान से काट देता है और जीवन की संभावनाओं को धुंधला कर देता है। यहीं शुक्रिया का भाव एक प्रकाशस्तंभ की तरह उभरता है। शुक्रिया यानी कृतज्ञता। यह वह सूक्ष्म, लेकिन शक्तिशाली भाव है, जो हमें हर अनुभव के भीतर छिपे अर्थ को पहचानने की दृष्टि देता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन से विदा हो गया, तो क्या केवल उसका जाना ही हमारे स्मरण का केंद्र होना चाहिए? या फिर यह भी हो सकता है कि उसने हमारे जीवन को अपनी उपस्थिति से समृद्ध किया, कुछ अनमोल क्षण दिए, कुछ सीखें दीं, कुछ स्मृतियां दीं, जो आज भी हमारे अस्तित्व में धड़कती हैं और इसके लिए उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए।

जब समाज इस दृष्टि को अपनाता है, तो संबंधों की प्रकृति में एक गहरा परिवर्तन आता है। हम खोने के भय में जीने के बजाय, पाने के सौभाग्य को महसूस करने लगते हैं। हम शिकायतों के बोझ से मुक्त होकर, कृतज्ञता के उजाले में जीना सीखते हैं। शोक हमें अतीत में जकड़ता है, जबकि शुक्रिया हमें वर्तमान में जड़ें जमाने और भविष्य की ओर आशा से देखने की प्रेरणा देता है। आज का समय जहां तेजी, प्रतिस्पर्धा और एकाकीपन का दबाव बढ़ता जा रहा है, वहां यह दृष्टिकोण और भी आवश्यक हो उठता है। हम अक्सर यह गिनते रहते हैं कि हमें क्या नहीं मिला- समय, समझ, साथ, अवसर। अगर हम ठहरकर यह देखने लगें कि हमें क्या मिला है, तो हमारी दृष्टि ही बदल जाती है। यही परिवर्तन हमें भीतर से समृद्ध करता है।

सामाजिक स्तर पर भी यह विचार अत्यंत सार्थक है। जब कोई आपदा आती है, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानवीय, तो समाज शोक में डूब जाता है, जो स्वाभाविक है, लेकिन अगर उसी क्षण हम यह भी देखें कि उस संकट ने हमें क्या सिखाया- मानवता का हाथ थामना, एक-दूसरे के लिए खड़ा होना, संवेदनाओं को जीवित रखना, तो हम उस पीड़ा को केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में भी देख सकते हैं।

व्यक्तिगत जीवन में असफलताएं भी इसी दृष्टि की मांग करती हैं। हर बार की हार केवल हार नहीं होती। वह एक संकेत होती है रुककर सोचने का, दिशा बदलने का और स्वयं को नए सिरे से गढ़ने का। अगर हम अपनी असफलताओं के प्रति भी कृतज्ञ हो सकें, तो वे हमारे विकास की सीढ़ियां बन जाती हैं। 'दुख नहीं मनाएं, शुक्रिया करें' का आशय यह नहीं है कि हम अपने दुख को नकार दें या संवेदनहीन हो जाएं। बल्कि इसका अर्थ है दुख को पूरे मन से स्वीकार करना, पर उसमें स्थायी रूप से डूब नहीं जाना। यह एक संतुलन की साधना है जहां आंसू भी अपनी जगह पर हैं और मुस्कान भी अपना अर्थ नहीं खोती। अगर यह भाव हमारे परिवारों और समाज में स्थान पा जाए, तो हमारी अगली पीढ़ियां जीवन को अधिक सकारात्मक और संतुलित दृष्टि से देख सकेंगी। वे विपरीत परिस्थितियों में टूटेंगी नहीं, बल्कि उनमें अवसर खोजेंगी। वे संबंधों को बोझ नहीं, बल्कि उपहार मानेंगी।

आखिर जीवन एक अनवरत यात्रा है, जहां हर मोड़ पर कुछ छूटता है, कुछ मिलता है। अगर हम हर छूटने पर केवल शोक मनाएंगे, तो इस यात्रा की सुंदरता से वंचित रह जाएंगे, लेकिन अगर हम हर मिलने और छूटने दोनों के लिए 'शुक्रिया' कहना सीख जाएं, तो जीवन केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक उत्सव बन सकता है। इसलिए जब भी जीवन हमें किसी कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा करे, तो एक पल ठहर कर, उसके बाद मुस्कुराकर हमें यह कहना चाहिए कि 'शुक्रिया', क्योंकि हर अनुभव, चाहे वह कैसा भी हो, हमें कुछ सिखाने, कुछ गढ़ने, और कुछ नया बनाने ही आता है।

> अगर हम अपनी असफलताओं के प्रति भी कृतज्ञ हो सकें, तो वे हमारे विकास की सीढ़ियां बन जाती हैं। 'दुख नहीं मनाएं, शुक्रिया करें' का आशय यह नहीं है कि हम अपने दुख को नकार दें या संवेदनहीन हो जाएं। बल्कि इसका अर्थ है दुख को पूरे मन से स्वीकार करना, पर उसमें स्थायी रूप से डूब नहीं जाना।

बिन पानी सब सून

कहीं हिमनद पिघल रहे हैं, कहीं जंगल जल रहे हैं, तो कहीं जल संकट बढ़ रहा है। वहीं दुनिया के कई बड़े शहर धीरे-धीरे धंसने लगे हैं। यह केवल वैज्ञानिकों की चिंता नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है। जकार्ता, ढाका, बैंकाक, मेक्सिको सिटी और शंघाई जैसे शहरों का धीरे-धीरे धंसना इस बात का संकेत है कि प्रकृति अब अत्यधिक दोहन का जवाब देने लगी है। धरती धंसने का सबसे बड़ा कारण भूजल का अंधाधुंध दोहन है। इंसान जमीन के नीचे जमा हजारों साल पुराने पानी को इतनी तेजी से निकाल रहा है कि मिट्टी और चट्टानों के बीच खाली जगहें सिकुड़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की रपट के अनुसार दुनिया की लगभग 40 फीसद आबादी जल संकट की स्थिति में पहुंच चुकी है। भारत के कई शहर जैसे दिल्ली, बंगलुरु और चेन्नई भी तेजी से भूजल संकट की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर, समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि वैश्विक तापमान इसी तरह बढ़ता रहा, तो इस सदी के अंत तक समुद्र का स्तर एक मीटर तक बढ़ सकता है। सोचिए, जब शहर नीचे धंसेंगे और समुद्र ऊपर उठेगा, तो करोड़ों लोगों का क्या होगा?

– विभूति बुपक्या, दिल्ली

आशंकाओं के बीच

आखिरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। विपक्षी नेता पांच राज्यों के चुनाव से पहले जब यह आशंका जता रहे थे कि चुनाव के बाद तेल और गैस के दाम बढ़ेंगे, तो सत्ता पक्ष के समर्थक इसको राजनीतिक बयानबाजी बता रहे थे। वह आशंका निराधार नहीं थी। विपक्ष की बातों पर इसलिए भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि गैस और पेट्रोलियम मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि कच्चे तेल का मूल्य जब तक 130 डालर प्रति बैरल के नीचे रहेगा, तब तक बाजार में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। मगर अब जबकि कच्चा तेल 110-115 डालर प्रति बैरल पर बना हुआ है, तो पेट्रोलियम मंत्री ने अपने बयान से विपक्ष को हमलावर होने का मौका दे दिया। जहां तक तेल कंपनियों के घाटे का प्रश्न है, तो वह तर्कसंगत इसलिए नहीं कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम वर्षों तक 70 डालर प्रति बैरल के आसपास स्थिर रहे थे, तब किन तेल कंपनियों ने इसका लाभ ग्राहकों को पहुंचाया था?

–नरेंद्र टोंक, मेरठ

भविष्य से खिलवाड़

राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी यानी एनटीए का गठन पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए हुआ था, लेकिन लगातार हो रही गड़बड़ियों ने उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुखद यह है कि जांच का बोझ छात्रों पर डाला जा रहा है, जबकि असली जिम्मेदार तो अब भी संदेह के घेरे से बाहर हैं। देश को केवल पर्चाफोड़ के आरोपियों की नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की जवाबदेही तय करनी होगी। वरना मेहनत हारती रहेगी और भ्रष्टाचार जीतता रहेगा। नीट परीक्षा रद्द होना केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि लाखों मेहनती और मेधावी छात्रों के सपनों पर सीधा प्रहार है। वर्षों की कठिन तैयारी, परिवार की उम्मीदें और बच्चों का मानसिक संतुलन सब कुछ एक लापरवाह व्यवस्था की भेंट चढ़ गया। युवाओं के सपने बिखर गए। यदि परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र वाट्सएप पर एक दूसरे को भेजे जा रहे थे, तो स्पष्ट है कि यह सेंध व्यवस्था के भीतर से लगी है और कार्रवाई वहीं होनी चाहिए।

– अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

गरिमा के विरुद्ध

कुछ दिन पहले हवाई यात्रा के दौरान तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से कथित अभद्रता की घटना केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा, स्त्री का सम्मान, नागरिक अधिकार और सार्वजनिक जीवन में आचरण के स्तर पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। अगर किसी जनप्रतिनिधि, विशेषकर एक महिला सांसद को उनके वैचारिक मतभेद, राजनीतिक विचार या किसी रपट को प्रस्तुत करने के कारण सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार अपमानित किया जाता है, तो यह केवल एक स्त्री की गरिमा पर ही हमला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद की आत्मा पर भी आघात है। असहमति और आक्रामकता के बीच एक स्पष्ट रेखा है। किसी भी नारी की गरिमा उसके राजनीतिक विचारों से बड़ी है और संविधान प्रत्येक नागरिक को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार देता है।

– वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

धर्मेंद्र प्रधान को 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव तो 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किया था। 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी के चुनाव प्रभारी की भूमिका निभाई थी। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव प्रभारी के रूप में अहम भूमिका निभाई थी। 2021 में पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान नंदीग्राम के चुनाव प्रभारी रहे। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

एक नहीं बोले, दो नहीं बोले, तीन नहीं बोले, अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो फिर सत्ता पक्ष से कोई गलती ही नहीं हुई है। भाजपा के नए-नवेले नेता राघव चड्ढा के सही होने के बहुमत वाले तर्क को मानेंगे तो नीट परीक्षा की धांधली में अपनी जिम्मेदारी पर चुप्पी साध कर सत्ता ने मामला रफा-दफा कर दिया। जब सरकार हर तरफ बचत की बात कर रही है, नेता से लेकर जज तक साइकिल से दफ्तर जा रहे हैं, तो 2026 में नीट-परीक्षा दोबारा ली जाएगी। दोबारा होने वाली परीक्षा में लगने वाले संसाधनों के आंकड़े पर

बेबाक बोल

हम बात नहीं करेंगे। बात करेंगे जवाबदेही, नैतिकता और आदर्श की, जिसका भंडार सत्ता पक्ष की तरफ तो खत्म हो गया सा दिखता है। घनघोर विभागीय नाकामी के बाद भी किसी मंत्री के मुख से इस्तीफे की बात नहीं निकलती, कार्रवाई तो दूर की बात है। लगता है कि सत्ता नैतिकता व आदर्श के सारे संसाधन सिर्फ विपक्ष के लिए संरक्षित कर चुकी है, ताकि उसे इसकी किसी तरह की कमी महसूस न हो। नाकामी के किसी भी आरोप का जवाब न देही के राजनीतिक चलन पर बेबाक बोल।

जवाबनदेही

मुकेश भारद्वाज

'हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। वह यूपीए की सरकार में होता था। यह राजग की सरकार है।' केंद्रीय रक्षा मंत्री के बयान का भावार्थ निकालें तो उत्तरदायित्व, जवाबदेही, नैतिकता...ये सब यूपीए सरकार के बंधन थे। राजग सरकार इन बंधनों से मुक्त है।

राजनाथ सिंह जब यह बयान दे रहे थे तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि राजग सरकार में उनकी बात पत्थर की लकीर बना दी जाएगी। राजग सरकार के मंत्री चाहे जिस स्तर पर भी नाकाम होंगे, न तो उनसे कोई सवाल किया जाएगा, और न ही वे किसी और के सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य होंगे। जमीनी हकीकत तो यह है कि जो मंत्री अपने सामान्य विभागीय काम-काज से जितना दूर, जितना उदासीन है, उसकी उन्नति की राह उतनी ही उज्ज्वल है।

नीट परीक्षा में पेपर लीक सामने आने के बाद ओड़ीशा में बीजद के एक नेता ने आरोप लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान का बस शरीर ही दिल्ली में रहता है, उनके प्राण तो ओड़ीशा में बसते हैं। हो सकता है कि बीजद नेता उन चुनावों में राजग की जीत से जलन में हों, जिन्हें जीतने में शिक्षा मंत्री की प्रधान भूमिका को रेखांकित किया जा सकता है।

वैसे भी राजनाथ सिंह की सरकार वाले मंत्रियों का पसंदीदा गाना हो सकता है-दिल्ली में मंत्री मुसाफिर है/आता है जाता है...। संसद सत्र में शामिल होने की मजबूरी नहीं हो तो राज्यों के विधानसभा चुनावों के अस्थायी शिविर ही उनका निवास हैं। जिन राज्यों में चुनाव का एलान हो जाता है, केंद्रीय मंत्रिगण से लेकर बड़े नेता, नतीजों तक वहीं के मेहमान हो जाते हैं। अपने चुनावी शिविर से निकल कर कभी-कभी दिल्ली से जुड़े गैर चुनावी कार्य की खानापूर्ति कर देते हैं।

पहले बात करते हैं, 2024 की। राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी ने 5 मई 2024 को नीट-यूजी परीक्षा आयोजित की। परीक्षा समाप्ति के कुछ घंटों के अंदर ही सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने के आरोप लगे। पता चला कि 30 से 50 लाख रुपए तक में पेपर बेचे गए। नतीजों में असामान्य तरीके से छात्रों के 720 में से सौ फीसद अंक (720) आए। विवाद तब आगे बढ़ा जब 1563 छात्रों को कृपांक दे दिए गए। अब कई विद्यार्थियों को 718 और 719 अंक मिले, जिसे अव्यावहारिक माना गया और नीट की परीक्षा राजनीतिक मुद्दा बन गई। इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह तो माना कि परीक्षा की पवित्रता भंग हो गई, लेकिन दुबारा परीक्षा नहीं हुई। उस वक्त पेपर लीक को 'क्षेत्रीय' मान कर पूरे देश में दोबारा परीक्षा करवाने से इनकार कर दिया गया।

अब हम आते हैं 2026 में। विद्यार्थियों को ही पता चलता है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। एक आम शिक्षक पुलिस तक पहुंचता है, लेकिन वहां भी मामले की गंभीरता को नहीं समझा गया। हंगामा मचते ही इस बार नीट की परीक्षा दोबारा करवाने का एलान कर दिया गया। यानी महज दो साल में पेपर लीक क्षेत्रीय से राष्ट्रीय हो गया। लेकिन राजनाथ सिंह वाली इस्तीफे नहीं होते वाली सरकार से इसका 'श्रेय' लेने अभी तक कोई सामने नहीं आया है।

तब और अब में एक अंतर यह है कि 2024 में धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक की बात नहीं मान कर वक्त जाया कर रहे थे। 13 जून 2024 को धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि नीट परीक्षा में पेपर लीक के कोई सबूत नहीं मिले हैं। साथ ही उन्होंने 'एनटीए' को भी बेदाग घोषित कर दिया था। उस वक्त उन्होंने विद्यार्थियों के विरोध को साजिश बताते हुए इस मुद्दे को 'हवा' देने का ठीकरा भी कोचिंग केंद्रों पर फोड़ा।

2026 में बिना कोई समय गंवाए पेपर लीक को 'राष्ट्रीय' मानते हुए दुबारा परीक्षा करवाने का एलान कर दिया गया। इस मसले पर प्रेस कांफ्रेंस में प्रधान ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि 2024 में भी बख्शा नहीं गया था। वहीं सभी यह सवाल कर रहे हैं कि क्या गारंटी है कि 2025 में पेपर लीक नहीं हुआ होगा? पिछले साल लीककर्ता अवकाश पर तो नहीं गए होंगे? हो सकता है, पिछली बार आम लोगों की पकड़ में न आया हो?

जब इतने बड़े मसले पर जिम्मेदारी को लेकर सत्ता पक्ष में चुप्पी छाई है तो बोल कौन रहा है? हर आम आदमी के इंटरनेट के पन्ने पर नायक बने कोचिंग संचालक ही दिख रहे हैं। एक कोचिंग नायक सरकार से कह रहे हैं कि दस रुपए का 'डायपर' भी 'लीक' रोक लेता है, आप नहीं रोक पा रहे हैं। मीडिया के हर मंच पर विद्यार्थियों की आवाज की अगुआई कोचिंग संचालक कर रहे हैं, सत्ता से वे ही सवाल पूछ रहे हैं। कोचिंग संचालकों की बढ़ती साख का असर यह है कि पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने टिकट भी दिया था। यह दूसरी बात है कि अवध ओझा चुनाव हार गए थे। लेकिन, इन दिनों कोचिंग संचालक जिस तरह से राष्ट्रीय नायक बन रहे हैं, वह दिन दूर नहीं दिख रहा, जब इनमें से कोई 'जेन जी' के समर्थन से तमिलनाडु का 'तलपति विजय' बन कर पूरी व्यवस्था को चौंका दे। जो लोग शिक्षा तंत्र की सबसे बड़ी समस्या हैं, सरकार की नाकामी ने उनके ही नायकत्व का बाजार मजबूत कर दिया है।

पिछले काफी समय से एक देश एक चुनाव का विमर्श गढ़ने की तैयारी हो रही है। इस विमर्श के समांतर हमारे संस्थानों की हालत किस तरह की है? आरोप है कि पिछले दस वर्षों में नब्बे से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। 'राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी' का मकसद भी एक देश, एक परीक्षा ही है। लेकिन यहां सिर्फ भ्रष्टाचार ही 'एक' हो पा रहा है, बाकी सब कुछ 'अनेक' ही है।

किसी भी देश की साख उसके संस्थानों से होती है। 2024 में परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हो जाने के बाद भी उससे जुड़े शीर्ष जिम्मेदारों को पवित्र प्रसाधन ही माना गया। शीर्ष के किसी बड़े जिम्मेदार पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इसका नतीजा है कि फिर लाखों विद्यार्थी रोते हुए पूछ रहे हैं कि इसमें हमारा क्या कसूर है? शायद उनका कसूर यह है कि उनमें से एक विद्यार्थी ने इतने बड़े भ्रष्टाचार को सामने ला दिया। ऐसे हालात देख कर लगता है कि हमें अभी उतना ही भ्रष्टाचार पता है, जितना सामने आया है, पता नहीं असली हालात कितने भयावह होंगे।

चिकित्सा के क्षेत्र में अक्सर भ्रष्टाचार के ऐसे मामले आते हैं, जो हमें चौंकाते हैं। एकबारगी पूरी मानवता से भरोसा डगमगाने लगता है। हम बाद में इसलिए चौंकते हैं, सवालरत होते हैं क्योंकि पूरा देश डाक्टर बनाने की प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार को आसानी से भूल जाता है। नीट 2024 में क्या सत्ता के शीर्ष से किसी ने जिम्मेदारी ली? जो विद्यार्थी इतने भ्रष्ट-तंत्र, गैरजिम्मेदारी वाले माहौल से गुजरते हुए डाक्टर बनेंगे उनसे हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वे 'डाक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है' वाली डाक्टरी करेंगे। कोरोना-काल में एमबीबीएस के अंतिम सत्र की कक्षाएं आनलाइन करने वाले मेडिकल विद्यार्थियों पर तंज होते थे कि इनसे इलाज मत करवाना, ये आभासी डाक्टर हैं। हमारे तंत्र ने विद्यार्थियों के सामने भ्रष्टाचार को क्षेत्रीय से राष्ट्रीय बना दिया है। जिस देश की परीक्षा ही पवित्र न हो, वहां संस्थानों की पवित्रता कैसे बरकरार रहेगी?

अब अरोड़ा?

पंजाब सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा इस समय जेल में हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 100 करोड़ के जीएसटी घोटाले में आरोपी बनाया है। मंत्री बनने से पहले वे राज्यसभा सदस्य थे। आम आदमी पार्टी ने उन्हें पिछले दिनों लुधियाना से विधानसभा उपचुनाव लड़ाया था। जीत के बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया तो राज्यसभा की यह सीट अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र गुप्ता को दे दी। राघव चड्ढा की भाजपा से नजदीकियां देखते हुए आम आदमी पार्टी ने गुप्ता को राज्यसभा में अपना वक्ता बनाया। लेकिन पिछले दिनों राघव चड्ढा के साथ गुप्ता भी आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उन्हीं के साथ अशोक मित्तल भी भाजपा में आ गए। लवली यूनिवर्सिटी के मालिक मित्तल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार नहीं किया था, पर उन पर काले धन को सफेद करने का आरोप लगा कर छापे मारे थे। राघव चड्ढा के साथ मित्तल भी भाजपा में आ चुके हैं। उनके खिलाफ प्रर्वन निदेशालय की कार्रवाई का अब कोई अता-पता नहीं। चर्चा है कि जमानत पर छूटने के बाद अरोड़ा भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। भाजपा इस चुनाव में खेला करना चाहेगी। प्रवर्तन निदेशालय के छापों से उसे अपना कुनबा बढ़ाने में आसानी होगी। बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद ही तंज कसा जा रहा था कि अब ईडी की पूरी टीम पंजाब की ओर कूच करेगी।

परीक्षा 'गारंटी' की

भाजपा की पश्चिम बंगाल में असली परीक्षा तो अब शुरू होगी जब उसकी चुनाव पूर्व दी गई गारंटियों का उल्लंघन होगा। जो काम सबसे आसान था वह सुवेंदु अधिकारी ने कर दिया। सरकार बीएसएफ को सीमा पर जमीन देगी ताकि बाड़ लगाई जा सके और बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को रोका जा सके। असली मुश्किल तो भाजपा सरकार को नकदी से जुड़ी गारंटियों को पूरा करने में आएगी। महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने का वादा कब पूरा होगा? दिल्ली में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आठ मार्च 2025 को महिला दिवस है और उस दिन से ही दिल्ली की भाजपा सरकार महिला सम्मान निधि का पैसा महिलाओं के खाते में डालना शुरू कर देगी। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय बंगाल से कई गुना ज्यादा है। तब भी 2500 रुपए नहीं दे पा रही भाजपा सरकार। बंगाल में तो वादा 3000 का है, कैसे होगा पूरा?

राजपाट

संगठन के काम में जुटे नेताजी

विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री की दौड़ एक राज्य में सबसे लंबी चली। यहां केंद्रीय नेतृत्व में सक्रिय नेता जी इस दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर चले घमासान के बाद उन्हें खुद केंद्रीय नेतृत्व की बात को समझना पड़ा। अब ये नेता जी अपने पुराने काम पर लौट आए हैं। एक के बाद एक राज्यों व संगठनों के लिए आदेश जारी कर रहे हैं। बीते चुनावों की वजह से संगठन में इन आदेशों के नहीं मिलने का मलाल देखा जा रहा था। इस निर्णय से संबंधित राज्य के सांसदों ने भी राहत की सांस ली है। उन्हें भी इस बात का डर था कि नेता जी कहीं राज्य में ही डेरा डाल कर न बैठ जाएं, जिससे उनकी गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।

रेवंत पर नजर है

दराबाद की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को अपने साथ आने का प्रस्ताव दे दिया। यों प्रधानमंत्री का अंदाज मजाकिया था। प्रधानमंत्री ने संदर्भ के साथ यह बात कही, लेकिन उनकी टिप्पणी आकस्मिक नहीं थी। बेशक उन्होंने राज्य की भलाई के लिए रेवंत रेड्डी को अपने साथ आने की बात कही लेकिन ऐसा लग रहा है कि रेवंत रेड्डी का भला भी इसी में है कि वे भाजपा के साथ आ जाएं। हालांकि अभी तो वे मुख्यमंत्री हैं और उनको सत्ता संभाले हुए ढाई साल ही हुए हैं। इसलिए वे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उनके साथ दो बातें ऐसी हैं, जो संदेह पैदा करती हैं। पहली तो यह कि सोनिया व राहुल गांधी के प्रति बहुत ज्यादा स्वामीभक्ति दिखाते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर गांधी परिवार कहे तो वे एक हजार करोड़ रुपए भी जुटा कर दे सकते हैं। ऐसी बातें करने वालों को हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रेवंत रेड्डी का अतीत संघ का रहा है। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही कांग्रेस में गए हैं। शुभेंदु अधिकारी भी संघ के बाल स्वयंसेवक थे। उसके बाद उन्होंने राजनीति कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के साथ ही की लेकिन आखिरकार भाजपा में गए और वहां जाकर ऐसे रमे कि क्या कोई पुराना स्वयंसेवक रमेगा। आरएसएस में तो यही कहा जाता है कि एक बार जब संघ के संस्कार आ गए तो फिर जाते नहीं हैं। सो, रेवंत रेड्डी पर नजर रखने की जरूरत है।

'बाहरी' की दावेदारी

भाजपा में दूसरे दलों से आने वाले नेताओं के मुख्यमंत्री बनने का सिलसिला जारी है। नया नाम शुभेंदु अधिकारी का जुड़ा है, जो 2020 में ही तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आए थे। उनके नेतृत्व में 2016 की तीन विधायकों वाली भाजपा के विधायकों की संख्या 2021 में बढ़कर 77 हुई और अधिकारी नेता विरोधी दल बन गए। पांच साल बाद 2026 में पार्टी को दो-तिहाई सीटें जिताकर सरकार बनवा दी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए। मीडिया में भाजपा के 'आउटसाइडर सीएम क्लब' की खूब चर्चा होती है। इससे पुराने भाजपाई वफादार त्रस्त दिखते हैं, पर पार्टी आलाकमान की सोच है कि दूसरे दलों के कद्दावर नेताओं को पार्टी नहीं लेती तो इतना विस्तार संभव न होता। इसी क्लब में हिमंता बिस्व सरमा, सम्राट चौधरी और पेमा खांडू हैं। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई थे, पर वे अब मुख्यमंत्री नहीं हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह भी कांग्रेस से ही भाजपा में आए थे। भविष्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया (मध्य प्रदेश), बृजेश पाठक (उत्तर प्रदेश) और राघव चड्ढा (पंजाब) अगर मुख्यमंत्री बने तो इस 'बाहरी समुदाय' की संख्या में और इजाफा होगा।

संकलन : मृणाल वल्लरी

नीति पर हो गठबंधन

भारतीय विविधता को समेटे बिना राष्ट्रीय दलों का विस्तार कितना कठिन है, यह बात पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा नेताओं की कार्यशैली में दिखी। पांच क्षेत्रों की बात करें तो भाजपा गठबंधन को पुडुचेरी में कामयाबी मिली। तमिलनाडु और केरलम में उसके हाथ कुछ खास नहीं आए। मगर पश्चिम बंगाल में मजबूत उभरती क्षेत्रीय पार्टी तृणमूल की हार से इस आशंका को बल मिलना लाजमी है कि क्या क्षेत्रीय दलों के दिन लग गए हैं? यह आशंका बेमानी है। इसके लिए अभी दोनों राष्ट्रीय दलों भाजपा व कांग्रेस को लंबा रास्ता तय करना होगा। सबसे अहम यह है कि इसकी जरूरत भी क्या है? अगर क्षेत्रीय दल खुद को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ते हैं जैसा तलपति विजय करते दिख रहे हैं, फिलहाल। ऊपरी तौर पर उन्होंने किसी संकीर्ण मुद्दों को तरजीह नहीं दी। बहरहाल कमजोर व दिशाहीन विपक्ष लोकतंत्र की कमजोरी का प्रतीक जरूर बन गया। लिहाजा गठबंधन की राजनीति का खाका नीतियों के सहारे बनना चाहिए न कि सिर्फ किसी को सत्ता से हटाने के लिए। तभी लोकतंत्र हमारी विविधता का प्रतिनिधित्व कर पाएगा।

-मुकेश कुमार मनन, पटना।

शिक्षित हो लोकतंत्र

तलपति विजय की पार्टी टीवीके को देश के सबसे शिक्षित नेताओं का मंत्रिमंडल माना जा रहा है। उसके छह विधायक पीएचडी हैं, जबकि स्नातकोत्तर विधायकों की संख्या 22 है। 25 विधायक स्नातक हैं। इसके अलावा 22 विधायक इंजीनियर हैं तो 18 विधायक वकील हैं। इतना ही नहीं, चुने गए विधायकों में से पांच आइआइटी इंजीनियर और आठ विधायक एमबीबीएस डाक्टर भी हैं। अभी तक सामान्यतः यह समझा जाता है कि राजनीति में शिक्षा का कोई महत्त्व नहीं होता परंतु तमिलनाडु की नवनिर्वाचित विधानसभा ने इस भ्रांति को खत्म कर दिया है। विजय की पार्टी टीवीके के उच्च शिक्षित विधायक दल को देश की राजनीति में विकास और तकनीक के नए दौर की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। आशा है कि अन्य प्रदेशों की जनता भी शिक्षा के महत्त्व को समझते हुए आगामी चुनावों में शिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की कोशिश करेगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे शिक्षित लोकतंत्र भी होना चाहिए। तमिलनाडु की जनता ने इसे साबित भी कर दिया है। अन्य प्रदेश भी इसके लिए आगे बढ़ें व लोकतंत्र को शिक्षित और मजबूत बनाएं।

-इशरत अली कादरी, खानूगांव भोपाल।

आपके पत्र

तय क्षय

बीसवीं और इक्कीसवीं सदी की नई पीढ़ी के सामने जेपी से जेपी तक ने इंकलाब के नारे को एक नए तेवर में रखा है। सियासी हालात को बदलने के तौर-तरीके जुदा हों, मगर मकसद एक जैसे ही थे। 1974-75 के दरमियान आजाद हिंदुस्तान की तारीख का मील का पत्थर बना तख्ता पलट का दौर टिकाऊ न हुआ। उस दौर की उपज सूबाई क्षत्रपों ने चुपके से मुल्क की सियासत की नब्ज को पकड़ लिया। जम्हूरियत की किताब में 2024 में दर्ज कहानी में इंकलाब की वह आहट सुनाई देती है जिसमें हुकूमत के सामने सूबाई क्षत्रप खड़े दिखे। तारीख गवाह है कि जंग-ए-आजादी में शामिल सूबाई क्षत्रपों का किरदार अहम था। वक्त बदला तो सूबे और सियासी खुदगर्जी ने क्षत्रपों के न केवल रास्ते बदले बल्कि सियासत का रुख सूबे की तरफ मोड़ दिया। जल्दी ही इस जमात ने अहसास करा दिया कि मुल्क की सियासत इनके इशारे पर चलेगी। सूबों को जागीर समझ बैठे क्षत्रपों के वजूद के खंभे तब एक-एक कर दरकने लगे जब उनके हाथों से खान-पान, रस्म-ओ-रिवाज और लिबास जैसी पहचान छीन ली गई। ढीली पड़ती सूबाई सियासत की मजबूरी ने कहानी का आखिरी पन्ना लिखा तो ज्यादातर क्षत्रपों की पहचान गुम मिली।

-एमके मिश्रा, रांची, झारखंड।

क्रांति का कथ्य

जय प्रकाश नारायण से कमलेश्वर ने पूछा कि आपकी संपूर्ण क्रांति का मूल तत्व क्या है? जेपी ने कहा क्रांति, क्रांति होती है। किसी एक व्यक्ति के प्रश्न का जवाब नहीं होती। आज जेपी की संपूर्ण क्रांति सफल हुई। जेपी के छाते के नीचे समाजवादियों के जमावड़े के साथ आरएसएस ने अपना घेरा बना लिया। समाजवादी क्षत्रपों को मजबूरन हिंदुत्व की धारा में बहना पड़ा। सत्ता बदलते ही उन संस्कृतियों पर ही हमला होता है, जिनके जीवित रहने से पुरानी सत्ता के लौट आने का डर बना रहता है।

-रामानुज चौधरी, तेयाय बेगूसराय।

असरदार अभियान

'कांग्रेस-मुक्त भारत' का सपना देखने वाली भाजपा के लिए कांग्रेस का यह पुनरुत्थान खतरे की घंटी है। अतः कांग्रेस को रोकने के लिए क्षेत्रीय दलों का सिमटना जरूरी है। वैसे केवल क्षेत्रीय दल ही नहीं, भाजपा अन्य राष्ट्रीय दलों को भी समेटने में लगी है। फिलहाल बसपा और माकपा, भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में नहीं हैं। आम आदमी पार्टी भाजपा के निशाने पर है। पूर्वोत्तर का पहला और इकलौता राष्ट्रीय दल, नेशनल पीपुल्स पार्टी (भारत), अब राजग का हिस्सा है। मतलब, क्षत्रपों और क्षेत्रीय दलों को अप्रासंगिक करना भाजपा के 'कांग्रेस-मुक्त भारत' अभियान का ही हिस्सा है।

-बृजेश माथुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

भगवा भवन

हिंदुत्व के विराट छाते की छांव में अपने अस्तित्व की रक्षा करते क्षेत्रीय दलों की अलग विवशता है, क्योंकि राजनीति की भावनात्मक भूमि पर उन्होंने मतदाताओं से अपनी प्रतिबद्धता के सूचकांक में भीषण गिरावट दर्ज की है। द्वितीय जेपी ने अपनी इंजन में इन्हें इसलिए जोड़ा ताकि क्षत्रपों की बची-खुची शेष वोट की शक्ति का इन्हें चतुर्दिक लाभ हो और क्षत्रपों के लिए हिंदुत्व डूबते को तिनका का सहारा बन सके। लोकनायक ने जब बिखरी ईंटों को जोड़कर कांग्रेस की जगह जनता दल रूपी दुर्ग बनाया तो क्षेत्रीय दलों को सत्ता की संजीवनी मिली थी। लेकिन वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की त्रिवेणी में इनका शीतल स्नान होने लगा तो मतदाताओं के मन मलिन होने लगे और इनका जनाधार खिसका। अब क्षत्रपों को अपना भविष्य, भगवा रंग में ही सुरक्षित दिख रहा है।

-अशोक कुमार, पटना, बिहार।

विशेष पन्ना कैसा लगा

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

THE HINDU

जगरनॉट आगे बढ़ता है

SIR के फेज़ 2 की गड़बड़ियों की वजह से फेज़ 3 में ECI से नए तरीके अपनाने की ज़रूरत है।

टी भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने वोटर लिस्ट के अपने विवादित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तीसरे फेज़ की घोषणा की है, जिसमें 16 राज्य और तीन केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, जिनमें कुल 36.73 करोड़ वोटर हैं। फेज़ 2 में जो हुआ उसे देखते हुए — रोल्स में 10.2% की ज़बरदस्त नेट कटौती — ECI के लिए यह समझदारी होगी कि वह इस तीसरे फेज़ को चलाने के तरीके में स्ट्रक्चरल बदलाव करे, ताकि खासकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में दिख रहा वोटरों का वंचित होना दोबारा न हो। कम से कम, आने वाले चुनाव की वजह से इस काम में जल्दबाजी नहीं की जाएगी। SIR की वजह से राज्यों में अलग-अलग लेवल पर बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल का मामला सबसे ज़्यादा खराब है। यह चुनाव आयोग के दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर, मनमाने मानदंडों और कार्यप्रणाली पर निर्भरता का कुल नतीजा था, जिसके चलते हाशिए पर मौजूद और अल्पसंख्यक समुदायों के मतदाताओं की अनुपातहीन रूप से बड़ी संख्या को हटा दिया गया, सबसे उल्लेखनीय रूप से पश्चिम बंगाल में। राज्यों में, एसआईआर की पहचान राज्यों में सशक्त निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के बजाय नई दिल्ली में चुनाव आयोग अधिकारियों द्वारा आंकड़ों और निर्णय लेने के केंद्रीकरण से हुई; बूथों को युक्तिसंगत बनाया जाना गणना के बाद के बजाय उसके समानांतर किया गया, जिससे विलोपन का पैमाना अस्पष्ट हो गया और मतदाताओं के लिए अपने शामिल होने की पुष्टि करना मुश्किल हो गया; और सॉफ्टवेयर की गलतियों के कारण केवल अतिरिक्त प्रविष्टियों के बजाय डुप्लिकेट नामों के पूरे सेट को हटा दिया गया। सबसे बुनियादी बात गणना प्रक्रिया का डिजाइन ही है, जो रोल पर पात्रता स्थापित करने का भार चुनाव आयोग अधिकारियों के बजाय मतदाताओं पर डालती है। इन परिणामों का समग्र परिणाम आंकड़ों में दिखाई देता है: लगभग हर राज्य में मतदाताओं में लिंग-अनुपात में गिरावट आई है जहां एसआईआर आयोजित किया गया था - तमिलनाडु उल्लेखनीय अपवाद है - और सामाजिक रूप से अनुमानित मतदाता-जनसंख्या अनुपात के साथ बेमेल है।

फिर भी, इनमें से किसी भी बात ने ECI को अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। बिहार के सबक को Phase 2 में नहीं अपनाया गया, इससे ही यह शक पैदा होता है कि यह लापरवाही जानबूझकर की गई है। चिंता की बात यह है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बजाय मैनेजर की निगरानी को चुना है, और ज़्यादा पहचान के डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार करने का निर्देश दिया है, न्यायिक अधिकारियों को तैनात किया है, जबकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट के सेक्शन 21(3) और सबूत का बोझ वोटरों पर डालने से जुड़े बुनियादी सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। जैसे-जैसे Phase 3 पूरा हो रहा है-

इसलिए, अब पॉलिटिकल पार्टियों और सिविल सोसाइटी पर यह ज़िम्मेदारी है कि वे वोटर्स को जागरूक करें ताकि यह पक्का हो सके कि उनके एन्यूमरेशन फ़ॉर्म ठीक से प्रोसेस किए गए हैं। ECI को यूनिवर्सल एडल्ट फ़्रैंचाइज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि ऐसे तरीके को जिसमें रोल पर बने रहने की ज़िम्मेदारी खुद वोटर्स पर डाली जाती है।

महाशक्ति शिखर सम्मेलन

जैसे-जैसे US और चीन अपने रिश्तों पर फिर से बातचीत कर रहे हैं, भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मज़बूत करना होगा

चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ दो दिन की बातचीत के बाद शुक्रवार जैसे ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग से रवाना हुए, दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच कुछ समय के लिए समझौता हुआ। यह कब तक चलेगा, यह देखना बाकी है, क्योंकि यह समिट ट्रेड से लेकर ताइवान तक, रिश्तों में तनाव लाने वाले मतभेदों की लंबी लिस्ट में बिना किसी साफ नतीजे के खत्म हुई। इसके बजाय, दोनों पक्ष ऐसे रिश्ते में कुछ स्थिरता लाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिसमें हाल ही में कई उतार-चढ़ाव आए हैं।

मिस्टर शी ने रिश्तों के लिए एक नया लेबल दिया, जिसमें मिस्टर ट्रंप के बाकी कार्यकाल और उसके बाद भी "स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के साथ एक कंस्ट्रक्टिव रिश्ते" की बात कही गई। अगर दोनों कुछ स्टेबिलिटी की ज़रूरत पर सहमत होते हैं, तो उनकी प्रायोरिटीज़ अलग लगती हैं। मिस्टर शी ने मिस्टर से कहा।

ट्रंप ने कहा कि ताइवान रिश्ते का सबसे ज़रूरी मुद्दा है, जिसे अगर ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो यह टकराव में बदल सकता है। ताइवान पर US का रुख वैसा ही है, जिसमें हथियारों की बड़ी बिक्री शामिल है। यह तनाव कम करने की नीति ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अगली बिक्री को कैसे संभालेगी, यह देखना बाकी है। मिस्टर ट्रंप के लिए, चीन से ज़्यादा अमेरिकी सामान खरीदना और रेयर अर्थ्स पर कंट्रोल कम करना, रिश्तों की सेहत के मुख्य पैमाने हैं। उन्होंने कहा कि बीजिंग 200 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदने, सोयाबीन की खरीद बढ़ाने और US बीफ़ एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियों में ढील देने पर सहमत हो गया है – ये "तीन B" हैं जिन पर उन्होंने ज़ोर दिया है। US ने 10 चीनी कंपनियों को एडवांस्ड Nvidia चिप्स की खरीद फिर से शुरू करने की भी इजाज़त दी है। दोनों पक्षों ने ट्रेड के मुद्दों को मैनेज करने के लिए एक बोर्ड ऑफ़ ट्रेड बनाने पर चर्चा की है, जिसमें कुछ चीनी सामानों पर टैरिफ कम करना, और नॉन-सेंसिटिव सेक्टर में चीनी इन्वेस्टमेंट को हरी झंडी देने के लिए एक बोर्ड ऑफ़ इन्वेस्टमेंट बनाने पर भी चर्चा की है।

अगर ये डील पक्की हो जाती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनसे एक खतरनाक ट्रेड वॉर में कुछ रुकावट आ सकती है। हालांकि, बीजिंग समिट ने दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच रिश्तों में बड़े पैमाने पर बदलते स्ट्रक्चरल डायनामिक्स की याद भी दिलाई है। अगर US आज भी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, तो ग्लोबल असर डालने की उसकी काबिलियत की लिमिट पर सवाल उठ रहे हैं, ईरान वॉर के बाद तो और भी ज़्यादा। चीन ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि अब उसे इंतज़ार करने या अपने ग्लोबल लक्ष्यों को छिपाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसा कि मिस्टर शी ने मिस्टर ट्रंप से कहा, क्या चीन और US थ्यूसीडाइड्स ट्रैप से बच सकते हैं, जिसमें पहले से मौजूद ताकत और उभरती ताकत के बीच टकराव होना ही है, और रिश्तों का एक नया मॉडल बना सकते हैं? यह सवाल भारत और बाकी दुनिया के लिए अहम है, जिन्हें इस दुश्मनी से निपटना है। US के दबाव का सामना करते हुए, और बढ़ते हुए घमंडी चीन के साथ मुश्किल रिश्तों को संभालते हुए, आने वाले सालों में भारत की डिप्लोमेसी के दो बड़े टेस्ट होंगे। भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और आज़ादी को कमज़ोर करने के बजाय, उसे मज़बूत करना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता होगा।

व्यापार, आपूर्ति शृंखला और आर्थिक शासन कला

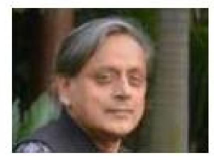

शशि थरूर
चौथी बार के सांसद
(कांग्रेस पार्टी, लोकसभा) के लिए
तिरुवनंतपुरम, संसदीय के अध्यक्ष
स्थायी समिति
बाहरी हवा और साहित्य पर
अकादमी
29 किताबों के पुरस्कार विजेता लेखक, जिनमें शामिल हैं 'पैक्स इंडिका' (2012) और 'द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर' (2020)

टी पिछले दशक ने इकॉनमी और जियोपॉलिटिक्स के बीच की पुरानी लाइन को खत्म कर दिया है, जिससे एक ऐसी दुनिया बन गई है जिसमें सप्लाई चेन, ट्रेड रूट, एनर्जी कॉरिडोर और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पावर के असली बैटलग्राउंड बन गए हैं। जो कभी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी डेक का हिस्सा हुआ करता था, वह अब नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग का रोज़ का हिस्सा है। टैरिफ सैंक्शन की तरह काम करते हैं, सेमीकंडक्टर अलायंस डिफेंस पैक्ट जैसे लगते हैं, और ज़रूरी मिनरल्स का फ्लो भी उतना ही असर डाल सकता है जितना कभी फौज की तैनाती करती थी। इस नए ऑर्डर में, देश न सिर्फ सेनाओं या आइडियोलॉजी से मुकाबला करते हैं, बल्कि रेगुलेटरी सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क और ग्लोबल प्रोडक्शन को एंकर करने की कैपेसिटी से भी मुकाबला करते हैं।

मार्केट और स्टेटक्राफ्ट का फ्यूज़न अब कोई ट्रेंड नहीं रहा; यह 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स का ऑर्गनाइज़िंग प्रिंसिपल है।

स्ट्रेटेजिक फ़ायदे के तौर पर ट्रेड इस बदलाव ने ग्लोबलाइज़ेशन की पुरानी आम सहमति की कमज़ोरी को भी सामने ला दिया है — यह मानना कि ट्रेड स्वाभाविक रूप से सहयोग और साझा खुशहाली को बढ़ावा देता है। तेज़ी से, आर्थिक संबंधों को स्ट्रेटेजिक फ़ायदे के साधन के तौर पर दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है।

टैरिफ, एक्सपोर्ट कंट्रोल, सप्लाई-चेन पर रोक और एनर्जी पर निर्भरता ऐसे टूल बन गए हैं जिनके ज़रिए देश दूसरों के व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी मिनरल्स के लिए होड़, एक-दूसरे पर निर्भरता का हथियार बनाना (चीन के रेयर अर्थ्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से उसे अमेरिका और भारत के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल गया है), और टैरिफ पॉलिटिक्स का फिर से उभरना (जिसका इस्तेमाल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सज़ा देने के लिए किया) ये सभी बताते हैं कि कितनी आसानी से कॉमर्स को ज़बरदस्ती में बदला जा सकता है। ऐसे माहौल में, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को नेशनल सिक्योरिटी से अलग नहीं किया जा सकता, और देशों को ऐसी दुनिया में आगे बढ़ना होगा जहाँ खुशहाली और ताकत एक-दूसरे से जुड़ी हों।

भारत के लिए, इस बदलाव ने विदेश नीति के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़रिए को बढ़ावा दिया है, जो आर्थिक लचीलेपन और डाइवर्सिफ़िकेशन पर ज़्यादा ज़ोर देता है। इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स के इस मेल ने एक ऐसा खास पल बनाया है जिसमें भारत की स्ट्रक्चरल ताकतें दुनिया की स्ट्रेटेजिक ज़रूरतों के साथ जुड़ती हैं। जैसे-जैसे कंपनियाँ और सरकारें कंसन्ट्रेटेड सप्लाई चेन में अपने एक्सपोज़र के बारे में फिर से सोच रही हैं, भारत का स्केल, स्टेबिलिटी और रिफॉर्म ट्रैजेक्टरी इसे ग्लोबलाइज़ेशन के बाहरी हिस्से से बोर्डरूम स्ट्रेटेजी और डिप्लोमैटिक कैलकुलेशन के सेंटर में ले आया है। एक देश जिसे कभी पश्चिम में एक उम्मीद जगाने वाला लेकिन मुश्किल मार्केट माना जाता था, अब उसे एक डाइवर्सिफाइड ग्लोबल इकॉनमी में एक ज़रूरी नोड के तौर पर देखा जाता है — इतना बड़ा कि मायने रखे, इतना स्टेबल कि भरोसा किया जा सके, और इतना खुला कि बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट को सोख सके।

इस नई पोजिशनिंग के पीछे तीन बदलाव हैं। सबसे पहले, भारत के घरेलू सुधारों — डिजिटाइज़ेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, और टारगेटेड डीरेगुलेशन — ने ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट कम की है और प्रेडिक्टेबिलिटी में सुधार किया है, जिससे ग्लोबल कंपनियों के लिए लॉन्ग-टर्म कैपेसिटी बनाना आसान हो गया है।

नई वैश्विक व्यवस्था भारत को पहले कभी न मिले स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक मौके, बैलेंस्ड 'पॉलिसी प्रोमिसक्यूट' के लिए एक केस बनाते हैं

दूसरा, जियोपॉलिटिकल रीकैलिब्रेशन चीन ने दूसरे प्रोडक्शन इकोसिस्टम के लिए एक स्ट्रक्चरल डिमांड बनाई है, और भारत उन कुछ इकॉनमी में से एक है जिनके पास उस डिमांड को पूरा करने के लिए लेबर फ़ोर्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मार्केट की गहराई है।

तीसरा, भारत की अपनी रणनीतिक कल्पना विस्तार: अब यह ट्रेड एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और सप्लाई-चेन डिप्लोमेसी को नेशनल स्ट्रेटेजी के बाहरी हिस्से के तौर पर नहीं, बल्कि स्टेटक्राफ़्ट के मुख्य साधन के तौर पर देखता है।

नया सिस्टम और भारत इस माहौल में, बड़ी ताकतों के साथ भारत के रिश्ते सिर्फ़ पारंपरिक जियोपॉलिटिक्स के बजाय इकोनॉमिक सिक्योरिटी से ज़्यादा बन रहे हैं। सेमीकंडक्टर कोलेबोरेशन, क्रिटिकल-मिनरल पार्टनरशिप, डिफेंस-इंडस्ट्रियल को-प्रोडक्शन और डिजिटल-पब्लिक-इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट, ये सभी इस बात के उदाहरण हैं कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में इकोनॉमिक रेजिलिएंस को कैसे शामिल कर रहा है। ये सिर्फ़ कमर्शियल अरेंजमेंट नहीं हैं; ये एक ऐसी दुनिया पर स्ट्रेटेजिक दांव हैं जहाँ असर मिलिट्री अलायंस के साथ-साथ प्रोडक्शन नेटवर्क से भी होता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ Pax Silica, Pax Americana को पूरा करता है, लेकिन Pax Americana के उलट, इसके लिए मिलिट्री पार्टनरशिप की ज़रूरत नहीं होती।

साथ ही, भारत को जोखिमों से भी निपटना होगा इस नए सिस्टम का। एक-दूसरे पर निर्भरता मज़बूत बना सकती है, लेकिन यह सामने भी ला सकती है। किसी एक पार्टनर पर बहुत ज़्यादा निर्भरता — चाहे वह टेक्नोलॉजी, मिनरल या मार्केट के लिए हो — कमज़ोरियाँ पैदा करती है जिनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। चुनौती यह है कि आर्थिक रिश्तों का एक ऐसा अलग-अलग तरह का पोर्टफोलियो बनाया जाए जो भारत की आज़ादी को बढ़ाए, न कि उसे रोके। आपसी रिश्तों में खुलापन कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन 21वीं सदी के तीसरे दशक की ट्रेड की दुनिया में, यह भारत के बर्ताव के लिए एकमात्र सही "डिफ़ॉल्ट तरीका" हो सकता है। बेशक, दूसरी तरह के व्यापार खुलापन में भी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। भले ही वह कई पार्टनर के पीछे हो, भारत को एक सावधानी भरा बैलेंस बनाना होगा: स्ट्रेटेजिक स्पेस छोड़े बिना इंटीग्रेशन को गहरा करना, उस पर निर्भर हुए बिना इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना, और पहले के ज़माने की गलतियों को दोहराए बिना ग्लोबलाइज़ेशन को अपनाना। यह ग्लोबल बदलाव भारत की अंदरूनी आर्थिक स्ट्रेटेजी पर भी नई माँगें डालता है। ग्लोबल सप्लाई चेन को मज़बूत करने के लिए, भारत को लॉजिस्टिक्स, रेगुलेटरी क्लैरिटी और वर्कफ़ोर्स स्किल में सुधार करते रहना चाहिए। उभरती टेक्नोलॉजी में आगे रहने के लिए, उसे रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और भरोसेमंद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा। ज़रूरी मिनरल्स को सुरक्षित करने के लिए, उसे विदेश में मज़बूत पार्टनरशिप और देश में टिकाऊ एक्सट्रैक्शन पॉलिसी बनानी होंगी। और तानाशाही वाली दुनिया में एक डेमोक्रेटिक विकल्प के तौर पर अपनी साख बनाए रखने के लिए, उसे यह पक्का करना होगा कि आर्थिक विकास के साथ इंस्टीट्यूशनल ताकत और सामाजिक मेलजोल भी हो।

दांव ऊंचे हैं क्योंकि यह मौका ऐतिहासिक है। लिबरलाइज़ेशन के बाद पहली बार, ग्लोबल इकॉनमी सिर्फ़ भारत को ही नहीं बुला रही है

भाग लें — यह सक्रिय रूप से भारत की उपस्थिति की मांग कर रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत जियोपॉलिटिकल मांग के इस पल को लंबे समय की आर्थिक क्षमता में बदल सकता है।

जैसे-जैसे ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम अलग-अलग हिस्सों में बंट रहा है ओवरलैपिंग गठबंधन और कस्टम-टेलर किए गए आर्थिक इंतज़ामों के बावजूद, भारत का काम नई दीवारों के पीछे हटना नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर भरोसे के साथ खुला रहना है। लक्ष्य न तो पूरी तरह से इंडिविजुअलिज़्म है और न ही भोला-भाला ग्लोबलिज़्म, बल्कि एक ऐसा कैलिब्रेटेड इंटीग्रेशन है जो किसी एक पार्टनर पर बहुत ज़्यादा निर्भरता से बचता है।

सीरियल डेटिंग तब सबसे अच्छा काम करती है जब हर पार्टनर को आपके दूसरे रिश्तों के बारे में पता हो, पता हो कि कई ऑप्शन मौजूद हैं लेकिन उनमें से किसी से भी खतरा न हो। यही वजह है कि एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और मज़बूत सप्लाई चेन भारत के बाहरी जुड़ाव के लिए सेंट्रल बन गए हैं: ये वो एरिया हैं जहाँ ग्लोबल कॉम्पिटिशन का अगला फेज़ तय होगा।

इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अब फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा नहीं है; यह इसके ऑर्गनाइज़िंग प्रिंसिपल्स में से एक है। जो देश अपनी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को अपने डिप्लोमैटिक पोज़िशन के साथ अलाइन कर सकते हैं, वे उभरते हुए सिस्टम को शेप देंगे, न कि उससे शेप लेंगे।

यह समय ग्लोबल ट्रेड के आर्किटेक्चर में एक बड़े बदलाव के साथ भी मेल खाता है। 20वीं सदी के आखिर में जो मल्टीलेटरलिज़्म था – जो यूनिवर्सल नियमों और आम सहमति पर आधारित था – उसने जियोपॉलिटिकल दुश्मनी और घरेलू पॉलिटिकल दबावों के बोझ तले अपनी रफ़्तार खो दी है। इसकी जगह, देश लचीले बाइलेटरल और रीजनल अरेंजमेंट की ओर रुख कर रहे हैं, जो उन्हें स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी के हिसाब से पार्टनरशिप बनाने की इजाज़त देते हैं। भारत के लिए, यह बदलाव कोई झटका नहीं बल्कि एक मौका है। यह एक ज़्यादा तेज़, इंटरेस्ट-ड्रिवन डिप्लोमेसी के लिए जगह बनाता है जो भारत के स्केल, स्टेबिलिटी और रिफॉर्म ट्रैजेक्टरी का फ़ायदा उठाकर अलग-अलग जगहों और सेक्टर में गठबंधन बना सकता है।

भारत दुनिया के चौराहे पर इन ट्रेंड्स के मिलने से भारत एक अहम मोड़ पर आ गया है। दुनिया अलग-अलग तरह के प्रोडक्शन बेस, भरोसेमंद डिजिटल इकोसिस्टम और स्थिर डेमोक्रेटिक पार्टनर्स की तलाश में है। भारत यह मांग पूरी कर सकता है — लेकिन तभी जब वह देश में कॉम्पिटिटिवनेस और विदेश में क्रेडिबिलिटी में इन्वेस्ट करता रहे। अभी लिए गए फैसले तय करेंगे कि भारत नई ग्लोबल इकॉनमी का सेंट्रल एंकर बनेगा या सिर्फ इसके कई पार्टिसिपेंट्स में से एक बनकर रह जाएगा। यह मौका ऐतिहासिक है, लेकिन यह ऑटोमैटिक नहीं है। इसके लिए मकसद की क्लैरिटी, इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी और बिना किसी डर या फेवर के दुनिया से जुड़ने का कॉन्फिडेंस चाहिए।

ऐसी दुनिया में जहां खुशहाली और ताकत अब शिपिंग लेन के बजाय सप्लाई चेन से चलती है, भारत का भविष्य ग्लोबलाइजेशन और आत्मनिर्भरता में से किसी एक को चुनने से नहीं, बल्कि दुनिया के साथ ऐसी शर्तों पर जुड़ने की कला में महारत हासिल करने से तय होगा जो उसकी ऑटोनॉमी की रक्षा करें और उसके एम्बिशन को बढ़ाएं।

विकसित भारत के लिए सिर्फ़ ग्रोथ नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी भी ज़रूरी है

सौमित्र भादुड़ी
प्रोफेसर
मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स

मैं भारत का हालिया आर्थिक प्रदर्शन भरोसा जगाने के लिए काफी मजबूत रहा है। पिछले दशक में, और विशेष रूप से COVID-19 महामारी के बाद के समय में, भारत ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ को मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ इस तरह से जोड़ा है जैसा कुछ ही बड़ी इकॉनमी कर पाई हैं। रियल GDP ग्रोथ मज़बूत बनी हुई है, जो FY2024-25 में 6.5% तक पहुँच गई, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी में से एक बन गया है। इस परफ़ॉर्मेंस को मज़बूत घरेलू डिमांड, कम इनवेस्टमेंट, धीरे-धीरे स्केल कंसोलिडेशन और मोटे तौर पर स्टेबल फाइनेंशियल सेक्टर का सपोर्ट मिला है।

हालांकि पिछले कुछ दशकों में भारत की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ अच्छी रही है, लेकिन हाई ग्रोथ बनाए रखने के लिए तेज़ी लानी होगी, खासकर इसलिए क्योंकि भारत 2047 तक विकसित भारत बनना चाहता है।

इस बदलाव के लिए न सिर्फ़ मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना होगा, बल्कि गहरे स्ट्रक्चरल सुधारों के ज़रिए ग्रोथ के सभी इंजन, लेबर, कैपिटल और बेहतर प्रोडक्टिविटी को भी एक्टिवेट करना होगा।

बिना गहराई के मैन्युफैक्चरिंग अब यह बात तेज़ी से मानी जा रही है, जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में दिखाया गया है, कि मैन्युफैक्चरिंग को इस अगले फेज़ का आधार बनाना होगा। हालांकि, चुनौती सिर्फ़ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना नहीं है, बल्कि इसे और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना भी है। भारत का स्ट्रक्चरल बदलाव एक जैसा नहीं रहा है। जहाँ सर्विसेज़ ने ग्रोथ को आगे बढ़ाया है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं बढ़ी है कि लेबर को शामिल कर सके या बड़े पैमाने पर प्रोडक्टिविटी में फ़ायदा उठा सके। ज़्यादातर सफल डेवलपमेंट अनुभवों में, मैन्युफैक्चरिंग कम प्रोडक्टिविटी वाली खेती और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाले मॉडर्न सेक्टर के बीच पुल का काम करती है।

इकोनॉमिक सर्वे इस बात को और मज़बूत करता है, इस बात पर ज़ोर देता है कि ग्रोथ बनाए रखने और बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग ज़रूरी है। इसके बिना, भारत को ऐसे ग्रोथ पैटर्न का खतरा है जो न तो काफ़ी मज़बूत है और न ही स्ट्रक्चरल रूप से स्थिर है। जहाँ सर्विसेज़ में प्रोडक्टिविटी ग्रोथ मज़बूत रही है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी अपनी क्षमता और अपनी ज़रूरतों, दोनों से पीछे रही है।

भारत को लंबे समय तक आर्थिक विकास बनाए रखने के लिए प्रोडक्टिविटी को अनलॉक करना होगा

इंटरनेशनल पीयर्स। एक मुख्य मुद्दा RM स्ट्रक्चर है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की खासियत यह है कि यहां बड़ी संख्या में छोटी, कम प्रोडक्टिविटी वाली कंपनियां हैं और कुछ ही मीडियम साइज़ की कंपनियां हैं जो बड़े पैमाने पर काम कर सकती हैं। यह उन इकॉनमी से बिल्कुल अलग है जो सफलतापूर्वक इंडस्ट्रियलाइज़ हुईं, खासकर ईस्ट एशिया में, जहां मीडियम और बड़ी कंपनियों का एक मज़बूत ग्रुप बना, जिससे एक्सपोर्ट और प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हुई।

इसलिए, मौजूदा स्ट्रक्चर में फैक्टर एलोकेशन के लिए चुनौती है, जिससे लेबर का एक बड़ा हिस्सा खेती में ही रह जाता है, जहाँ प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज़ की तुलना में बहुत कम है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि बड़े इन्वेस्टमेंट के बावजूद — खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में — एफिशिएंसी गैप बने हुए हैं।

ज़ॉम्बी फर्म, रुका हुआ रीएलोकेशन ये स्ट्रक्चरल रुकावटें एक गहरी समस्या में बदल जाती हैं, जो कमज़ोर बिज़नेस डायनैमिज़्म में दिखती है। इकोनॉमिक थ्योरी में, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ अक्सर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से होती है, जिसमें नई, ज़्यादा एफिशिएंट फर्म पुरानी, कम प्रोडक्टिव फर्मों की जगह ले लेती हैं। असल में, भारत में यह प्रोसेस धीमा है। नतीजतन, छोटी, कम प्रोडक्टिविटी वाली "ज़ॉम्बी" फर्मों का बने रहना रिसोर्स के एफिशिएंट रीएलोकेशन में रुकावट डालता है।

ज़ॉम्बी फ़र्म जो अब आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद नहीं हैं, लेकिन फिर भी चल रही हैं, वे कैपिटल और लेबर को फंसा लेती हैं, जिन्हें वरना ज़्यादा प्रोडक्टिव कामों में लगाया जा सकता था।

हाल की स्टडीज़ से मिले सबूत इस चिंता को और पक्का करते हैं। एक पेपर, "ज़ॉम्बी फ़र्म्स इन इमर्जिंग मार्केट्स: सर्वाइवल एंड फ़ंडिंग मैकेनिज़्म" (2025), दिखाता है कि ज़ॉम्बी फ़र्म्स, फ़र्म्स का काफ़ी छोटा हिस्सा हैं, लेकिन कुल कर्ज़ और एसेट्स में उनका हिस्सा बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा कम प्रोडक्टिविटी वाले इस्तेमाल में फंसा हुआ है, जिससे सिस्टम में कमियां पैदा हो रही हैं। रिसर्च यह भी दिखाती है कि ज़ॉम्बी बनना एक धीरे-धीरे होने वाला प्रोसेस है। फ़ाइनेंशियल गिरावट फ़र्म्स को ज़ॉम्बी कहे जाने से बहुत पहले शुरू हो जाती है, और एक बार जब वे इसमें आ जाती हैं।

राज्य, वे कोर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में बहुत कम रिकवरी दिखाते हुए कर्ज पर ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। समस्या लगातार बनी रहती है, साइक्लिकल नहीं। सबसे ज़रूरी बात, नैन्सिंग का नेचर मायने रखता है। बैंक-नैन्स्ड फर्मों के ज़ॉम्बी बनने, लंबे समय तक संकट में रहने और थोड़ी रिकवरी के बाद भी फिर से खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके उलट, इक्विटी-नैन्स्ड फर्मों में ज़ॉम्बी बनने का खतरा कम होता है और उनके लगातार ठीक होने की संभावना ज़्यादा होती है।

ये नतीजे एक गहरी इंस्टीट्यूशनल समस्या की ओर इशारा करते हैं। फाइनेंशियल और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर अक्सर कमज़ोर कंपनियों को बाहर निकलने में मदद करने के बजाय उन्हें बनाए रखते हैं। यह ज़्यादा प्रोडक्टिव कंपनियों से क्रेडिट को बाहर करके रीएलोकेशन को कमज़ोर करता है, जिससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ग्रोथ कम हो जाती है।

दो-तरफ़ा स्ट्रैटेजी भारत के विकसित भारत के रास्ते के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग-लेड स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है जो स्केल और एफिशिएंसी दोनों पर ध्यान दे। भारत ने दिखाया है कि वह तेज़ी से बढ़ सकता है। अगला फेज़ यह पक्का करना है कि यह ग्रोथ प्रोडक्टिविटी और इनकम में लगातार बढ़ोतरी में बदले।

यह बात अब समझ में आ रही है कि भारत की विकास कहानी में मैन्युफैक्चरिंग एक कमज़ोर कड़ी है और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए ग्लोबल वैल्यू चेन में गहराई से जुड़ना, ट्रेड में रुकावटों को मैनेज करना और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश करना ज़रूरी होगा। बिज़नेस में तेज़ी और प्रोडक्टिव रिसर्च और डेवलपमेंट के ज़रिए प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। इसका मतलब है कि कंपनियों को बढ़ने देना, लेकिन साथ ही कमज़ोर कंपनियों को बाहर निकलने देना। इसलिए, सुधारों का फोकस नियमों को आसान बनाने, लेबर की दिक्कतों को कम करने, दिवालिया होने की प्रक्रिया को मज़बूत करने, क्रेडिट देने में सुधार करने और फाइनेंसिंग तक पहुँच बढ़ाने पर होना चाहिए।

विकसित भारत का विज़न आखिरकार इस पर निर्भर करता है इस बात पर कि क्या भारत इस बदलाव को पूरा कर सकता है। ग्रोथ ने नींव रख दी है, लेकिन बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी और कमज़ोर कंपनियों का बाहर निकलना यह तय करेगा कि यह विकसित भारत की छलांग को बनाए रख पाएगा या नहीं।

Machine Translated by Google

ग्राउंड जीरो

17 साल बाद, युद्ध के निशान अभी भी मौजूद हैं

गृहयुद्ध खत्म होने के कई साल बाद भी, श्रीलंका के तमिलों को गरीबी, भारी बेरोज़गारी और ज़मीन की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
उनका मानना है कि सरकारों ने युद्ध से तबाह हुए लोगों के लिए कोई पूरी योजना बनाने के लिए बहुत कम किया है।
उत्तरी और पूर्वी इलाकों में। जबकि बच्चों की एक पीढ़ी बहुत कम समझ के साथ बड़ी हो रही है
मीरा श्रीनिवासन की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके माता-पिता भेदभाव और कमी से जूझ रहे हैं।

टीलेल्ड, तमिलों के जीवन के रूप में
श्रीलंका का उत्तर और पूर्व
युद्ध बल्ले पर आसानी से खत्म नहीं होते-

18 मई को, समुदाय 17 साल पूरे करेगा
लंबे और भयानक गृहयुद्ध के अंत के बाद से
जिसने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। इसकी परछाई के साथ
उस युद्ध की यादें जो सशस्त्र बलों ने बनाई थीं, आज भी ताज़ा हैं
सेना और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम
(LTTE) से लड़े गए सैनिकों को इस सालाना याद में शायद ही जोड़ा जा सकता
है। यह उनकी मुश्किल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखता है और उन पर भारी पड़ता
रहता है।
भविष्य के लिए उम्मीदें।

"उस दौरान यह बहुत कठिन और जोखिम भरा था
वर्ष [1983-2009]," नतारासा पद्मलीला कहती हैं,
54, उत्तरी मुल्लईतिवु के उदयरकट्टू से
"हम इधर-उधर घूमते रहे, जो भी मिला खाया
उपलब्ध था, ताड़ के फल से कपड़े धोता था,
और हमेशा गोलाबारी के डर में रहते थे। लेकिन अब ज़िंदगी
और भी कठिन लगता है।"

यह तमिलों के बीच एक आम बात है - नहीं
क्योंकि वे इनके बीच अंतर नहीं कर सकते
एक जीवंत युद्ध के गंभीर खतरे और रिकवरी की धीमी, दर्दनाक गति, लेकिन
क्योंकि "शांति" है
अभी तक कोई ठोस राहत या बेहतर जीवन की असली उम्मीदें नहीं आई
हैं। एक ऐसा जहाँ वे कर सकें
अच्छा जीवन यापन करें, अपने परिवार का भरण-पोषण करें
दिन में तीन बार खाना, मिलिट्री वालों की नज़रों से बचकर आज़ादी से
घूमना, अपने प्रियजनों को याद करना,
और ठीक हो जाओ।

ऐसा कोशिश न करने की वजह से नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग हैं
शिवरासा योगेश्वरी ने जिन विकल्पों को नहीं खोजा है
युद्ध खत्म होने के बाद से। घरेलू काम करने से
सऊदी अरब में काम करने वाले, रोज़गार पाने के लिए
छोटे खेतों में दिहाड़ी मजदूरी से लेकर दुकान तक
असिस्टेंट के तौर पर, उसने हर चीज़ को आज़माया है।

"बाहर से मेरी ज़िंदगी भले ही नॉर्मल दिखती हो।
लेकिन इस बात के अलावा कि मैं अपना
बच्चों को स्कूल ले जाओ, मेरे पास सबके लिए दिखाने के लिए कुछ नहीं है
51 साल के इस व्यक्ति का कहना है, "यह काम बहुत थका देने वाला है।"
पड़ोसी किलिनोच्ची जिले में रहते हैं।
उसके दुबले-पतले शरीर में थकान को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है और
तनावपूर्ण चाल.

अभाव को कम आंकना

2009 से, जन-केंद्रित तमिल राजनीति
मुख्य रूप से युद्धकालीन जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित किया गया और
दिल में अभी भी अनसुलझा राजनीतिक सवाल
जातीय संघर्ष का। चाहे संसद में हो या
प्रतिनिधियों के साथ अपनी लगातार बैठकों में
विदेशी सरकारों की — जिन पर कई तमिल
नेताओं को न्याय की उम्मीद बनी हुई है —
वे जबरन गायब कर दिए जाने, संदिग्धों को लंबे समय तक हिरासत में रखने जैसे
मुद्दे उठाते हैं
सख्त आतंकवाद विरोधी कानून, सेना और सरकार के समर्थन से ज़मीन पर
कब्ज़ा, प्रांतीय काउंसिल चुनाव,
और पावर डिवोल्यूशन। वे इस बारे में बहुत कम बात करते हैं
गरीबी, बेरोजगारी, ग्रामीण आजीविका पर दबाव, बढ़ती जीवन लागत और व्यापक

आम लोगों में निराशा की भावना।

ये सच्चाई डेटा से पता चलती है। 2022-
23 संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में बहुआयामी अध्ययन
तीन आयामों के आधार पर कमज़ोरियाँ —
शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा, जीवन स्तर —
और स्कूल में उपस्थिति सहित 12 संकेतक,
स्वास्थ्य, बेरोज़गारी और ऋणग्रस्तता,
मुल्लईतिवु, किलिनोच्ची और वावुनिया पाए गए
उत्तर में, और पूर्व में बट्टिकलोआ, ये सभी

> तमिल राजनेताओं लड़ रहे हैं हमारे अधिकारों के लिए। केंद्र (सरकार कोलंबो में) लेना चाहिए हमारी देखभाल जीविका
>
> पेरूमल
> प्रदीपन
> मछुआरे
> किलिनोच्ची

ये तमिल बहुल ज़िले हैं, जो द्वीप के सबसे कमज़ोर ज़िलों में से हैं।

"तमिल राजनेता हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।
केंद्र (कोलंबो में सरकार) को
हमारे भरण-पोषण का ध्यान रखें," किलिनोच्ची के एक शेरमन पेरुमल प्र-दीपन
कहते हैं,
कि एक "उडुप्पु" [कपड़े, गरिमा को दर्शाता है] और दूसरा, "सप्पाडु" [जीवित
रहने के लिए भोजन] जैसा है। हालाँकि वह इसके कारणों को बताता हुआ प्रतीत
होता है
तमिल नेतृत्व को सम्मान और समान अधिकार,
और बुनियादी सामग्री को पूरा करने की जिम्मेदारी
राष्ट्रीय सरकार को उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, वह उन्हें ढूंढता है
उसकी अपनी ज़िंदगी में उलझा हुआ है: ज़िंदा रहने की उसकी लड़ाई
वह अपनी इज्ज़त की चाहत से अलग नहीं है।

"मैं 32 साल का हूँ। मेरे पास 15 लाख (लगभग ₹4.4 लाख) से ज़्यादा हैं
लाख) का कर्ज़ था, जब मैंने खरीदने के लिए पैसे उधार लिए थे
मैं हर दिन संघर्ष करता हूँ ताकि मेरा परिवार न करे
भूखे रहना पड़ता है। कर्ज देने वाले का सामना करना अपमानजनक होता है।
यह मेरी ज़िंदगी है," वह रोते हुए कहता है।

सितंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले तमिल लोग राष्ट्रपति अनुरा कुम-
आरा दिसानायके को लेकर सतर्क लग रहे थे।
राष्ट्रपति चुनाव - उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार और
अब विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा को
उनका वोट शेयर सबसे ज़्यादा था - लेकिन उन्होंने जल्दी ही
नवंबर में आम चुनावों में बदलाव
उसी साल। उदाहरण के लिए, जना में, नेशनल
पीपुल्स पावर (NPP) ने तमिल पार्टियों को हराया और छह में से तीन सीटें जीतीं।

14 नवंबर को होने वाले संसदीय चुनावों से कुछ दिन पहले यह बदलाव साफ़
दिख रहा था।
जना के तटीय गांव पासैयूर में रैली में, डिस-सनायके ने लोगों की ज़मीन वापस
करने का वादा किया
सरकारी एजेंसियों द्वारा। उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को फिर से शुरू करने, नौकरियाँ
बनाने और एक ऐसा देश बनाने का वादा किया जहाँ सभी
नागरिक, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों, महसूस करते हैं
बराबर। एक "साधारण नेता" की उनकी लोकप्रिय छवि,
करिश्माई आउटरीच और साफ़ मैसेजिंग ने तमिलों को यकीन दिलाया कि उन्हें
एक मौका मिलना चाहिए।
पूर्व में बट्टिकलोआ में, NPP शीर्ष पर उभरा
उस चुनाव में सभी तमिल-बहुल क्षेत्रों में।

भूमि तक पहुँच

अप्रैल 2025 में, वासविलन से पलाली तक एक सड़क
जना प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित शहर
मिलिशिया के 34 साल बाद, इसे जनता के लिए फिर से खोला गया।

सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जना मार्केट का एक शॉट। मीरा श्रीनिवासन

देश में कई संकट आने से, पहले से ही युद्ध प्रभावित इलाकों में खतरा बढ़ गया है।
अक्टूबर में, सरकार ने इसे "सुरक्षा चिंताओं" के कारण बंद कर दिया था।
2025 में, रक्षा मंत्रालय ने बची हुई प्राइवेट ज़मीनों को उनके मालिकों को सौंपने
में तेज़ी लाने के लिए "ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावटों" को हल करने
के लिए एक हाई-लेवल मीटिंग बुलाई।

इस पहल का स्वागत किया है, लेकिन वे सवाल उठाते हैं
इसका धीमी गति से लागू होना।

सिर्फ़ मिलिट्री ही लोगों को कंट्रोल नहीं करती
ज़मीन पर दावा करने वाली दूसरी सरकारी एजेंसियां भी हैं, जैसे कि पुरातत्व और
वन विभाग। यह चिंता खास तौर पर मुल्लैतिवु ज़िले में ज़्यादा है।

विपक्षी पार्टी इलनकाई तमिल अरासु कडची (ITAK) के विधायक थुरैरासा
रविकरण, जो संसद में जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, के अनुसार, दिस्सा-नायके
प्रशासन ज़्यादा जवाबदेह रहा है।

जिले की सड़कों और पुलों सहित बुनियादी ढांचे की जरूरतों के लिए अपने पहले
के राज्यों की तुलना में यह बेहतर है।
उन पर तेज़ी से और पॉज़िटिव जवाब दिया है
लेकिन जब ज़मीन पर कब्ज़ा करने की बात आती है
उन्होंने कहा, "विभिन्न राज्य एजेंसियों द्वारा जिले में लगाए गए आरोपों के बावजूद, ऐसा लगता है कि वे
इसे संबोधित करने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं।"

पिछले कुछ सालों में यह मुद्दा बार-बार उठा है
उत्तर और पूर्व के जिलों में फैल गया।
मुल्लईतिवु में कुरुन्थुरमलाई एक स्थल बन गया
तमिल, जिनके पूर्वजों ने
पहाड़ी पर बने मंदिर में शिव की पूजा करने वाले सैनिकों को अचानक सैनिकों ने
बताया कि वे मंदिर नहीं जा सकते।
"पुरातात्विक" स्थल, भले ही यह तेजी से बदल गया
एक स्तूप के साथ बौद्ध पूजा केंद्र में बदल दिया गया।

"जहां हिंदू पारंपरिक रूप से प्रार्थना करते थे, वहां बौद्ध मंदिर बनाना और वन
संरक्षण के नाम पर लोगों की कृषि-सांस्कृतिक भूमि पर कब्जा करना

यह एक बहुत बड़ी चिंता है। हम उत्तर और पूर्व में सिंहलियों की इन प्लान्ड बस्तियों
को एक तरह से देखते हैं
क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदलने का," रविक-अरन ने कहा, और आगे कहा: "हमें
यह नहीं भूलना चाहिए कि भूमि पर विवाद ही बड़े संघर्षों को जन्म देते हैं।"

नौकरी ढूँढना

एक ऐसे जिले में जहां ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं
और जीविका के लिए शेरीज़, भूमि तक सीमित पहुँच
इसका मतलब है कि इनकम में भारी गिरावट आई है।
पब्लिक सर्विसेज़ में जो कुछ पद खाली हैं, वे हैं
युवाओं के लिए आने वाली कुछ अच्छी नौकरियां।
अनौपचारिक, ग्रामीण आजीविका पर भी भारी निर्भरता
इसका मतलब है कि बेरोजगारी की सामाजिक दर
ये एरिया पिक्चर को बिगाड़ देते हैं।

उत्तर में बेरोज़गारी ज़्यादा है
और बाकी द्वीप की तुलना में पूर्व में, गवर्नर
उत्तरी प्रांत के नागलिंगम वेथा-नयाहन ने रोजगार सृजन के लिए सरकार के प्रयासों
की ओर इशारा करते हुए कहा।

"एलिफेंट पास में सॉल्टर्न को पुनर्जीवित किया जा रहा है।
वे कहते हैं, "कुरुनचथिवु में साल्टर्न एक और हाई पोटेंशियल एरिया है जिस पर हम
फोकस कर रहे हैं।" सरकार ने वहां रिकंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू किया है।

परान-थान में एक समय की मशहूर केमिकल फैक्ट्री, जो युद्ध की वजह से लगभग
चार दशकों से बंद थी। "इसे बनाने का काम चल रहा है

रोजगार बढ़ाने के लिए परांथन, मन्कू-लाम और कांकेसंथुरई में तीन नए इंडस्ट्रियल
ज़ोन बनाए जाएंगे
और आर्थिक विकास। हम वैल्यू एडिशन सुविधाओं और कोल्ड स्टोरेज को बढ़ाने
पर भी विचार कर रहे हैं।
कृषि उपज के लिए, ताकि हम निर्यात बाजार का दोहन कर सकें," राज्यपाल, जो
एक पूर्व सरकारी एजेंट हैं (जिला कलेक्टर के समान) कहते हैं

भारत) जिन्होंने जन में सेवा की है।

स्थानीय लोग लंबे समय से स्थानीय संसाधनों से जुड़े छोटे उद्योगों की मांग कर रहे
हैं।
कदम अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इन प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह चालू होने,
रोज़गार पैदा करने, मांग बढ़ाने में कम से कम कुछ साल लगेंगे।

और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फिर से ज़िंदा करना। इस बीच,
तमिलों में सबसे गरीब - द्वारा निर्धन
युद्ध के बाद भी संकट का खामियाजा भुगतना जारी है
संकट, 2019 के ईस्टर बम विस्फोटों से, कोविड-19 महामारी, द्वीप के वित्तीय
संकट
2022 में, अब पश्चिम एशिया में युद्ध के लिए। चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के
स्केल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की भारी किफ़ायत सिर्फ़

इससे उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं।

एक अलग संघर्ष

इसी संदर्भ में पद्मलीला कहती हैं कि जीवन
अब और मुश्किल है। वह अपने समय को एक
युवा LTTE लड़ाका। वह इस आंदोलन में शामिल हो गईं-
अपनी किशोरावस्था के अंत में, इस उम्मीद के साथ कि
तमिल संघर्ष से राज्य की हिंसक स्थिति खत्म हो जाएगी
भेदभाव। "ईमानदारी से कहूँ तो, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है
एक पोराट्टम [संघर्ष] में उम्मीद है । यह केवल तब हुआ जब मैं
उनसे जुड़ने के बाद मुझे संगठन की समझ आ गई
उन्होंने लिट्टे प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरन का जिक्र करते हुए कहा, ''यह अन्ना
की विचारधारा और ढांचे के बारे में है।''

जैसा कि कैडर में आम था, उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी
युद्ध में और अलग-अलग जगहों पर सेवा की। "हम
उद्देश्य और आदर्शवाद से बंधे थे, और मुझे लगा
एक व्यक्ति के रूप में देखभाल की जाती है। चाहे वह पौष्टिक भोजन हो,
चाहे कपड़े हों या मानसिक शक्ति, मेरा ध्यान रखा गया।
लेकिन अब, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। इसीलिए मैं यह कह रहा हूँ।
संघर्ष कठिन है," वह कहती हैं.

पद्मलीला अपने पति अरुमुगम नटरासा और तीन बच्चों के साथ मुल्लैतिवु में रहती
हैं।
आज, उनके पति, जिनसे वह इस दौरान मिली थीं
युद्ध में लगी चोटों की वजह से, वह व्हीलचेयर इस्तेमाल करता है। "उसे अपने
परिवार के साथ एक देखभाल करने वाले की ज़रूरत है
वह कहती हैं, ''एक तरफ.''

वह छोटे खेतों में काम करने के लिए बाहर निकलती है जब कोई
उसके बच्चों में से एक घर पर है। उसकी कमाई, सरकार के महीने के डिसेबिलिटी
अलाउंस और अस्वसुमा कैश से परिवार मुश्किल से गुज़ारा करता है।

चुनिंदा गरीब परिवारों के लिए ट्रांसफर स्कीम।

"मेरी बड़ी बेटी एक छोटा सा सिलाई का व्यवसाय चलाती है-
"बाकी दो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं", वह कहती है।

नतारासा एक बिस्तर पर बैठी है, जो
उनके लिविंग रूम में एक जोड़े के अलावा, फर्नीचर
प्लास्टिक की कुर्सियों का। वह बिना एक शब्द बोले ध्यान से सुनता है। "युद्ध ने
उस पर सच में असर डाला। वह बस
वह कहती हैं, "हम चुप रहते हैं।" ट्रॉमा से लेकर, विकलांगता, अभाव और निराशा
तक, युद्ध के
उसके छोटे से घर में कई निशानियां हैं।

उनकी बड़ी बेटी, जो अब 23 साल की है, को छोड़कर, उनके बच्चे तमिल
संघर्ष को नहीं समझते, उनके
पद्मलीला के अनुसार, माता-पिता की भूमिका, या युद्ध ही महत्वपूर्ण है। "हमारे
वर्तमान जीवन को समझने के लिए उनके पास कोई संदर्भ या इतिहास की समझ
नहीं है। मुझे लगता है कि
डिस्कनेक्ट करें, लेकिन ऐसा ही है। जब तक उनके
हमारी ज़िंदगी हमसे बेहतर है, अच्छी नौकरी और
अच्छा भविष्य है, मैं ठीक हूँ," वह कहती है।

पद्मलीला के अनुसार, यह सिर्फ़ उनके बच्चे ही नहीं हैं
जो अपने अतीत से स्वतंत्र हैं; यह तमिल है
राजनीति भी। "ये राजनेता हमेशा सामने आते हैं
मावीरार नाल [नवंबर में लिट्टे कैडर के परिवारों द्वारा मनाया जाने वाला 'शहीद
दिवस'] और मुल्ली-वैक्कल स्मरणोत्सव [नागरिक बलिदान का जश्न मनाने के
लिए]
युद्ध मई में खत्म होगा]। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कैसे
वह कहती हैं, "हमें दूसरे दिनों में जीने में मुश्किल होती है।"
"लिट्टे" के प्रति सम्मान और "आस्था" के बीच मतभेद
राजनीतिक मंचों पर "शहीदों" का अपमान और आंदोलन के बचे लोगों की घोर
उपेक्षा उन्हें दुख पहुंचाती है।

अपनी रोज़ी-रोटी कमाने की कई कोशिशों से पहले, यो-गेश्वरी भी LTTE का
हिस्सा थीं। पोर्ट्रेट
उसके भाई-बहनों की, जो भी आउट्ट से थे
और युद्ध के दौरान मारे गए, उनके लिविंग रूम में टंगे हुए हैं।
"आंदोलन में मुझे 'इनबाम' [खुशी] कहा जाता था। मुझे लगा
एक व्यक्ति के रूप में देखा और महत्व दिया जाता है। आज, मैं मजबूर हूँ
सिर्फ़ ज़रूरी सामान खरीदने के लिए पैसे उधार लेना।
जब मैंने एक और पूर्व लड़ाके को देखा तो मेरा दिल बैठ गया
"बस स्टॉप पर मूंगफली बेचते हुए। वह कैप्टन रह चुके हैं। यही हमारी ज़िंदगी है,"
वह शांत भाव से कहती हैं।

> तमिल नेता मावीरार नाल के लिए आए
> लिट्टे के परिवारों ने 'शहीद दिवस' मनाया
> नवंबर में कैडर] और मुल्लिवइक्कल
> स्मरणोत्सव [गृहयुद्ध का अवलोकन करने के लिए]
> उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि हम कैसे
> दूसरे दिनों में जीने के लिए संघर्ष
>
> नटरासा पद्मलीला
> कृषि मजदूर

आर. जगदीश्वरन का कहना है कि उनके फोन में CID (क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) या TID (टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) के दर्जनों नंबर सेव हैं। 35 साल के जगदीश्वरन ने कहा, "मेरे फोन में CID (क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) या TID (टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) के दर्जनों नंबर सेव हैं।"

शेर एसोसिएशन के नेता केवल संक्षिप्त थे
LTTE, युद्ध के अंत की ओर है, लेकिन 17 साल से जारी निगरानी से बच नहीं
सकता।
इसका अंत। "वे हर समय फोन करते हैं और हमारे बारे में पूछते हैं
पता चलेगा, हम क्या कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि मैं
आपके जाने के बाद फ़ोन आएगा कि मुझसे कौन मिलने आया था।"
वह कहते हैं, "इससे निपटना बहुत निराशाजनक है जब
युद्ध खत्म हो गया है, आंदोलन बहुत पहले खत्म हो चुका है, और
हम बस जीने की कोशिश कर रहे हैं।"

योगेश्वरी को भी CID की लगातार पूछताछ का सामना करना पड़ा है। "पिछले
साल, उन्होंने
उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि क्या आंदोलन फिर से शुरू होगा। मैंने उनसे कहा कि
यह सब खत्म हो गया है।
— कि मैं बस जीने और अपने बच्चों को पालने की कोशिश कर रहा था।" आम
कहानी के उलट कि ज़्यादातर तमिल पैसे से ज़िंदा रहते हैं, या कामयाब भी होते हैं

विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों, उनके जैसे परिवारों से पैसे मिलते हैं
बाहर या आने वाले पैसे से कोई लिंक नहीं है।

हर संकट के बाद लिखने के अलावा, एक के बाद एक आई सरकारों ने कोई
योजना बनाने के लिए बहुत कम किया है।
अरुणासलम एलंगेश्वरी का कहना है कि युद्ध प्रभावित क्षेत्र के लिए व्यापक आर्थिक
योजना की आवश्यकता है।
आर्थिक विकल्पों के लिए एक समन्वयक
पूर्वी बट्टिकलोआ जिले में सुरिया महिला विकास केंद्र। "बट्टिकलोआ ने पिछले कुछ
दशकों में कई झटके झेले हैं - युद्ध,

सुनामी, ईस्टर बम विस्फोट, महामारी, आर्थिक संकट, चक्रवात दितवाह और युद्ध

पश्चिम एशिया," वह कहती हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की
आपदाओं के गंभीर स्थानीय प्रभावों पर जोर देते हुए।

पिछले दो वर्षों में बट्टिकलोआ, श्रीलंका में से एक
लंका के सबसे गरीब जिलों में सबसे ज़्यादा
घरेलू नौकर और देखभाल करने वालों के तौर पर काम की तलाश में जाने वाले
प्रवासी मज़दूरों की संख्या, ज़्यादातर पश्चिम एशियाई देशों में। "हर कोई जाने के
लिए बेताब है। आप जानते हैं कि

संकट जब एक तटीय समुदाय sh in छोड़ देता है
हम यह भी देखते हैं कि परिवार तीन गुना कम खाना खा रहे हैं।
एलन-गेस्वरी कहती हैं, "दो लोगों को खाना देना मुश्किल है, और कई लोग कर्ज़ में हैं।"
वह आगे कहती हैं कि परिवारों को सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, "किसी छोटे,
टारगेटेड तरीके से नहीं, बल्कि एक तरह से
इस दबाव से निपटने के लिए "व्यापक नीति" की आवश्यकता है।

"सरकार को भी देने पर विचार करना चाहिए
लोगों के समूहों, खासकर महिलाओं को ज़मीन दी जाए, ताकि
वे इसे एक साथ मिलकर विकसित कर सकते हैं।
अलग-अलग बिज़नेस को सपोर्ट करने के मकसद से
बार-बार नाकाफ़ी साबित हुए हैं। एक-एक प्रोग्राम और एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया
नहीं हो सकते
वह कहती हैं, "एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था में टिके रहना। सही रिवाइवल के
लिए एक साफ़ आर्थिक नज़रिए की ज़रूरत है।"

meera.srinivasan@thehindu.co.in